खण्ड–07 सत्र–02 / अंक–12

बृहस्पतिवार 11 मार्च, 2021 / 20 फाल्गुन, 1942 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

दूसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड–07 (भाग–1) में अंक 09 से अंक 13 सम्मिलित है।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली–54

सम्पादक वर्ग
EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन
सचिव
C. VELMURUGAN
Secretary

महेन्द्र गुप्ता
उप सचिव (सम्पादन)
MAHENDRA GUPTA
Deputy Secretary(Editing)

विषय–सूची

सत्र–2(भाग–1) बृहस्पतिवार, 11 मार्च, 2021/20 फाल्गुन, 1942 (शक) अंक–12

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	3–4
2.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	5–18
3.	अल्पसंख्यक कल्याण समिति के प्रथम प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण एवम उस पर संक्षिप्त चर्चा	19–32
4.	सदन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के प्रथम एवम द्वितीय प्रतिवेदन से सहमति	33–34
5.	सदन द्वारा प्रशासनिक मामलों के विभाग से संबंधित स्थायी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमति	34
6.	ध्यानाकर्षण (नियम–54)	35–49
7.	वार्षिक बजट (2021–22) पर चर्चा	50–99

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र – 2, बृहस्पतिवार, 11 मार्च, 2021/20 फाल्गुन, 1942 (शक) अंक 12

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाहन 11:03 बजे समवेत हुआ।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए

1.	श्री अजेश यादव	16.	श्री नरेश यादव
2.	श्री अजय दत्त	17.	श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
3.	सुश्री आतिशी	18.	श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
4.	श्री अमानतुल्ला खान	19.	श्री ऋतुराज गोविंद
5.	श्री अब्दुल रहमान	20.	श्री रघुविंदर शौकीन
6.	सुश्री भावना गौड़	21.	श्री राजेश गुप्ता
7.	श्री बी.एस.जून	22.	श्री राज कुमार आनंद
8.	श्री धर्मपाल लाकड़ा	23.	श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
9.	श्री गिरीश सोनी	24.	श्री रोहित कुमार
10.	श्री गुलाब सिंह	25.	श्री शरद कुमार चौहान
11.	श्री हाजी युनुस	26.	श्री सोम दत्त
12.	श्री जय भगवान	27.	श्री शोएब इकबाल
13.	श्री कुलदीप कुमार	28.	श्री शिव चरण गोयल
14.	श्री मुकेश अहलावत	29.	श्री सोमनाथ भारती
15.	श्री महेन्द्र यादव	30.	श्री सौरभ भारद्वाज

31.	श्री सही राम	41.	श्री मदन लाल
32.	श्री एस.के.बग्गा	42.	श्री मोहन सिंह बिष्ट
33.	श्री विशेष रवि	43.	श्री ओमप्रकाश शर्मा
34.	श्री वीरेंद्र सिंह कादियान	44.	श्री पवन शर्मा
35.	श्री अखिलेश पति त्रिपाठी	45.	श्री प्रलाद सिंह साहनी
36.	श्रीमती ए. धनवती चंदीला ए.	46.	श्री राजेश ऋषि
37.	श्री अभय वर्मा	47.	श्री विजेंद्र गुप्ता
38.	श्री अनिल कुमार बाजपेयी	48.	श्री करतार सिंह तंवर
39.	श्री अजय कुमार महावर	49.	श्री प्रकाश जारवाल
40.	श्री जितेंद्र महाजन		

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र–2, वीरवार, 11 मार्च, 2021/20 फाल्गुन, 1942 (शक) अंक–12

सदन पूर्वाह्न 11.03 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी महा शिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव प्रकृति स्वरूप हमारे आधार स्तम्भ हैं। वे सृष्टि की उत्पति, स्थिति और संहार के अधिपति हैं तथा सृष्टि निर्माण के आदि स्त्रोत हैं। मैं इस पावन पर्व पर यह कामना करता हूं कि वे हम सब के जीवन में सुख, स्मृद्धि, उन्नति प्रदान करें। हमारे राष्ट्र के जीवन में उन्नति प्रदान करें। आप सभी को एक बार फिर महा शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बंदना जी ये नहीं आए हैं क्या ? आज हमारे दो माननीय सदस्यों का जन्मदिन है। मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूं। सर्वप्रथम माननीय सदस्या श्रीमती बंदना कुमारी जी का जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं तथा कामना करता हूं कि वे अपने व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन में नई ऊंचाईयां प्राप्त करें। दूसरा हमारे माननीय मंत्री कैलाश गहलौत जी का भी जन्मदिन है उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और लंच के वक्त केक की व्यवस्था कर लीजिए, लंच के वक्त केक काटेंगे उसी स्थान पर। अब देखो आज जन्मदिन तो मना लो, केक खिलाएंगे। 280 श्री संजीव झा, श्री नरेश यादव, श्रीमती प्रमिला टोकस।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकसः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपने क्षेत्र की

समस्या को उठाने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि हमारे तीन क्लस्टर हैं मेरी विधान सभा में – मोहम्मदपुर आदर्श बस्ती, मलाई मंदिर, लाल बहादुर शास्त्री कैंप। इसमें जिस भी हमने एनजीओ को दिया है उस NGO ने बिजली का बिल अदा नहीं किया इसलिए वहां तीनों कलस्टर की बिजली काट दी गयी है जिससे वहां के बच्चियों को, हमारी माताओं बहनों को शौच के लिए जाने में दिक्कत होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कैसे भी करके उन लाइटों को और काफी दिन हो गए हैं, हमने लैटर भी लिखे हैं पर अभी तक उसपे कोई कार्यवाही नहीं हुई है, उस लाइट को जल्द से जल्द जुड़वाएं क्योंकि वहां की जनता बड़ी दुखी है, हमारी माताएं, बहनें, हमारी बच्चियां जो शौच के लिए जाती हैं अंधेरे में बड़ा उनको डर लगता है और मैं एक और निवेदन करना चाहती हूं महिलाओं के शौचालय के बाहर तो डस्टबिन रखे हुए हैं, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि बाहर के साथ–साथ प्रत्येक क्यूबिकल के अंदर भी डस्टबिन व लाइट होनी चाहिए ताकि हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियों को रात में जाने से उनको डर लगता है या हमारे जो बच्चे हैं उनको डर लगता है तो क्यूबिकल के अंदर भी लाइट होनी चाहिए और मेरा एक और अनुरोध है कि डस्टबिन के साथ साथ सैनिटरी–नैपकिन का भी इंतजाम हो महिलाओं के शौचालयों में क्योंकि अभी भी हमारी कुछ महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें अभी भी ऐसी हैं या तो पैसों के अभाव से अभी भी वो कपड़े का यूज करती हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी एवं महिलाओं के शौचालय में बाहर के साथ–साथ प्रत्येक क्यूबिकल के अंदर भी डस्टबिन व लाइट होनी चाहिए ताकि हमारी दिल्ली की सभी झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों में जितने भी शौचालय हैं उसमें सैनिटरी–नैपकिन का इंतजाम हो ताकि हमारी किसी भी बहन–बेटी को कपड़े का इस्तेमाल न करना पड़े और इतना ही नहीं बड़े दुख की बात है अध्यक्ष जी, हमारी माताएं–बहनें पैसों के अभाव में जिस कपड़े को यूज करती हैं, उसको धोकर दोबारा यूज करती हैं। तो मेरा मंत्री साहब से विनम्र निवेदन है कि हमारी जितनी भी झुग्गी–झोपड़िया हैं, जितने भी हमारे महिला शौचालय हैं सभी शौचालयों में नैपकिन का इंतजाम किया जाए ताकि किसी भी हमारी माताओं–बहनों को इस कपड़े का इस्तेमाल न करना पड़े और जब हम बार बार उसी कपड़े को यूज करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो हमारी माताओं–बहनों को।

माननीय अध्यक्षः हो गया प्रमिला जी।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकसः उससे भी बचाया जा सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मेरे क्षेत्र का और दलित समाज का एक मुद्दा है, सफाई कर्मचारियों एक मुद्दा है उसपर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, कुछ दिन पहले मेरे पास कई सौ लोग जो सफाई कर्मचारी हैं दलित समाज के मेरे क्षेत्र के लोग हैं वो आए और घबराए हुए थे, बड़े दुखी थे और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वे हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में काम करते हैं 1900 एम्प्लाई हैं, सफाई कर्मचारी और उनका कांट्रेक्ट अभी खत्म होने वाला है और जिस कंपनी को कांट्रेक्ट मिला है उसका नाम है 'ओरियन सिक्योरिटी सौल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड'। इस कंपनी के कुछ लोग इन्हें आके रोज धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तुम्हें यहां से बाहर निकालेंगे। ये सब बहुत दुखी हैं और ये लोग कह रहे थे सर हमने कोरोना के समय में अपनी जान को हथेली पर रखकर काम किया और कोरोना के बाद आज कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं है, कोई कमाने का साधन नहीं है। अगर हमारी ये नौकरी भी छूट गयी 1900 लोग की, अगर ये सफाई कर्मचारियों की नौकरी छूट गयी तो उन्हें कहां मिलेंगी। तो ये सब अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं और इस संदर्भ में मैंने डिपार्टमेंट को लैटर लिखा, मैंने उनसे पूछा दिल्ली विधान सभा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कई बार फोन किया, मैंने एसएमएस भिजवाए कोई जवाब जवाब नहीं दिया। इस संदर्भ में मैं आपके पास भी आया, मैंने आपको भी एक लैटर के माध्यम से पूरा रिप्रजेंटेशन जो उन एम्प्लाईज का था सफाई कर्मचारियों का था वो भी मैंने आपको दिया और आपने कहा, मुझे आश्वस्त किया कि इसपर काम होगा और ये सारे कर्मचारी बड़े दुखी हैं। अध्यक्ष जी, जब मैं 'ओरियन सिक्योरिटी सौल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड कंपनी' की और डिटेल में गया तो मुझे पता चला कि ये कंपनी चार स्टेटो में ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। आईआईटी पटना में इसको ब्लैकलिस्ट किया गया है, ये इसके दस्तावेज हैं उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थने इसे ब्लैकलिस्ट किया हुआ है गवर्नमेंट आफ इंडिया ने, उसके दस्तावेज हैं और बीएचईएल ने इसे ब्लैकलिस्ट

किया हुआ है उसके दस्तावेज हैं और एयर इंडिया ने इसे ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, उसके दस्तावेज हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो ब्लैकलिस्ट कंपनी है, जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया है क्योंकि वो एम्प्लाईज का पीएफ, ईएसआई में घोटाला करते थे, उन्हें ब्लैकलिस्ट इसलिए किया गया 'ओरियन सिक्योरिटी सौल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड' को कि जो भी मानक हैं वे उनको पूरा नहीं करते और ऐसी कंपनी को एक बहुत बड़ा कांट्रेक्ट दे दिया और वो कांट्रेक्ट लेने के बाद आज जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम उन्हें निकालेंगे। यहां तक कह रहे हैं अगर तुम्हें दोबारा नौकरी चाहिए तो हमें 30 हजार रूपये आपको देने पड़ेगे।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, देखो कल भी मैंने अनाउंस किया था।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से कि।

माननीय अध्यक्षः उस तक सीमित रहिए।

श्री अजय दत्तः इस पर संज्ञान लें, इनको तुरंत बुलाएं और पूछें कि भई ये ऐसा क्यूं कर रहे हैं और जितने भी 1900 कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं दलित समाज के, गरीब तबके के कर्मचारी हैं इस कंपनी को अगर कांट्रेक्ट मिले तो पहले इन लोगों को रखा जाए और इसके खिलाफ जांच जरूर हो कि एक ब्लैकलिस्ट कंपनी को दिल्ली सरकार में इन अधिकारियों के माध्यम से न रखा जाए ये मेरी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद, जय हिन्द।

माननीय अध्यक्ष : अजय दत्त जी ये आप मेरे पास आए थे जो भी आपने बोला है मैंने इस कंपनी को फोन किया था जो आपने ओरियन सिक्योरिटी नाम दिया है। इसका ठेका काफी दिन पहले छूट चुका है, अब दूसरी कंपनी है। अब इस कंपनी के पास ठेका नहीं है वहां का। ये रावल जी से एक बार मिल लें ये जानकारी ली थी सारी। हां जी यूनुस जी। शुरू करिए, हाजी जी।

श्री हाजी युनूसः अध्यक्ष जी धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान दिल्ली में एमसीडी के जो हालात हैं उसके ऊपर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली में एमसीडी के

हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे सफाई का मामला हो। दिल्ली में गंदगी को लेकर हद तो यहां तक हो चुकी है कि मुस्तफाबाद विधानसभा जो कि नार्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा दंगा प्रभावित क्षेत्र है यहां पर दंगे में कोरोना काल में लॉक डाऊन की वजह से लोगों का रोजगार पहले ही काफी हद तक खत्म हो चुका है। उस पर ईडीएमसी की ओर से छोटे–छोटे दुकानदारों को सीलिंग के नोटिस देना यहां तक कि नाई की दुकान, सिलाई की दुकान, परचून की दुकान या कोई मोबाईल रिपेयरिंग करता है उसको भी सीलिंग के नोटिस दिए जा रहे हैं और दुकानदार इसको लेकर यहां तक कि मकानों को भी जो आम लोग जो मकानों में रहते हैं जिनके यहां कोई कारोबार नहीं है उनको भी सीलिंग के नोटिस दिए जा रहे हैं। यहां तक कि इसको लेकर मैं अपने नेता विपक्ष मनोज त्यागी जी और अपने काउंसलर साथियों के साथ दो मर्तबा अक्टूबर में ईडीएमसी की कमिश्नर साहब से मिला। कमिश्नर साहब को लिखित में ये लैटर भी दिया गया कि आप इन गरीबों के, इसको जो उजाड़ना चाहते हैं इसको तुरंत रोकें लेकिन उन्होंने आज तक इसको रोकने का प्रयास नहीं किया और यह अब तक भी बदस्तूर जारी है। सीलिंग के नोटिस भी आ रहे है, सीलिंग भी हो रही है, ये सिलसिला अभी तक रूका नहीं है। मुस्तफाबाद विधान सभा में दंगों में पहले ही लोगों को मकान, दुकान जल गए थे, जैसे तैसे भला करे दिल्ली सरकार का अरविन्द केजरीवाल की सरकार का कि अरविन्द केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार ने, जैसे तैसे उन दुकानदारों को, मकानवालों को मुआवजा देकर उनको ये मौका दिया कि उन्होंने अपने छोटो–मोटे कारोबार शुरू किए और अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। जब वो अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करने लगे तो दिल्ली की एमसीडी उनके बच्चों के मुॅह से जो दो वक्त का निवाला वो लोग खाते हैं इन्होंने उस निवाले को भी छीनने का काम शुरू कर दिया है। मैं आपसे इस सदन के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि भाजपा शासित एमसीडी तुरंत इन गरीबों को नोटिस देना बंद करें और इस सीलिंग को बंद करें और साथ में ये भी विश्वास के साथ ऊपर वाले पर भरोसा रखकर कहता हूं कि आने वाले एमसीडी चुनावों में दिल्ली की जनता तीनों एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार लाएगी और भाजपा को गरीबों के बच्चों के मुंह से जो निवाला छीन रहे हैं इसका सबक सिखाएगी।

माननीय अध्यक्षः हो गया, हो गया।

श्री हाजी युनूसः और अध्यक्ष महोदय एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि कल एक यहां पर जिक्र चल रहा था एक रोड के बारे में। तो मैं जानना चाहता हूं कि दो साल पहले एनएच–9709 बी परियोजना जो कि हमारे देश के केंद्रीय शहरी मंत्री, माननीय नितिन गडकरी जी ने।

माननीय अध्यक्षः भई हाजी जी ये इसमें नहीं है कहीं भी जो आप बोल रहे है, प्लीज। ये इसमें नहीं है। अलग से लिखकर दे दीजिए आप।

श्री हाजी युनूसः एक छोटे से किस्से के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। पीछे जब मैं गुजरात में, विधान सभा इलेक्शन में था, एक किस्सा छोटा सा सर।

माननीय अध्यक्षः हाजी जी ऐसे तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा प्लीज। आपकी बात हो गई 280 में, जो कुछ ओर समस्या है वो लिखकर दे दीजिए वो मैं देख लूंगा।

श्री हाजी युनूसः बस मैं एक छोटे से किस्से के साथ में बात खत्म कर रहा हूं अध्यक्ष जी, एक छोटा किस्सा।

माननीय अध्यक्षः करिए, करिए, करिए जल्दी।

श्री हाजी युनूसः मैं गुजरात के विधान सभा इलैक्शन में था तो वहां एक किस्सा मेरे सामने आया कि एक आदमी, एक बूढ़ी अम्मा के पास आता है और वो उससे कहता है कि अम्मा जी तुम्हारा बेटा हार गया। वो अम्मा जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर कुछ और लोग आए उन्होंने भी ये कहा कि अम्मा जी तुम्हारा बेटा हार चुका है, अम्मा ने कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है। फिर वहां जो बैठे लोग थे जब काफी लोग आए तब उन लोगों ने कहा कि अम्मा जी तुम्हारा बेटा आज हार चुका है, तो वहां जो लोग ये सब कुछ देख रहे थे उन्होंने पूछा कि जब इतने लोग बार–बार आकर अम्मा जी आपसे ये कह रहे हैं तुम्हारा बेटा हार चुका फिर तुम क्यों नहीं मानती। तो अम्मा जी का कहना था बेटा मैं कैसे मान लूं कि मेरा बेटा हार गया है। सबसे पहली बात तो ये कि मेरा बेटा कुछ जानता ही नहीं है, दूसरी बात ये।

माननीय अध्यक्षः चलिए हाजी जी हो गया।

श्री हाजी युनूसः कि वो अगर किसी की मानता नहीं तो उसे हराने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्षः हाजी जी ये विषय नहीं है, समय।

श्री हाजी युनूसः धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए, अजय महावर जी।

श्री अजय कुमार महावर : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद आपने 280 में मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री जी से अपने विधान सभा क्षेत्र घौण्डा के अंतर्गत आने वाला गामड़ी मार्ग के चौड़ीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूॅं। किसी समय इस मार्ग में बहुत बड़ी–बड़ी बसें चलती थीं, अब ये मार्ग धीरे–धीरे संकरा हो गया है। मास्टर प्लान के हिसाब से यह 100 फीट है और ये पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ही आता है। 2012 में भी निगम ने एक सर्वे किया था और इसका डिमार्केशन भी किया था, निशानदेही भी की थीा। लेकिन पता नहीं किन–किन कारणों से, कहां–कहां इसमें रूकावट आ रही है। पीडब्ल्यूडी ने एक सर्वे कंपनी भी हायर की थी, रॉयल इंजिनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 2018 में सबमिट कर दी है । कुछ स्थानीय आरडब्ल्यूएज भी इसकी बाबत कोर्ट के दरवाजे पर गई थी। माननीय न्यायालय ने भी इसको चौड़ीकरण का आदेश दिया है जिसकी कॉपी भी मैंने विभाग को दी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूॅं कि जनहित में, लार्जर पब्लिक इंट्रेस्ट में उस क्षेत्र की मांग को देखते हुए हाथजोड़ कर विनती है कि आप इस अवरोध को दूर करके इस मांर्ग में जो भी बाधाएं आ रही है उसे दूर करें और इसे जल्द से जल्द चौड़ा करवाएं जिससे जो लोग तिलतिल जाम से रोज अपना समय मार रहे हैं उससे उनको निजात मिल सके, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, अभय वर्मा जी।

श्री अभय वर्माः आदरणीय अध्यक्ष जी, 280 के तहत मुझे बोलने का मौका मिला इसके लिए आपको धन्यवाद। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्य रोड है जो साउथ गणेश नगर से होते हुए मदर डेयरी की तरफ जाती है। उसके नाले ठीक से साफ नहीं होने के कारण हर समय वहां का पानी बैक मारकर साउथ गणेश नगर के निवासियों के घरों में जाता है और उनका जीना दूभर हो रखा है। इसके साथ ही उस रोड में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक फाटक के नीचे अंडर पास है जहां पर कई वर्षों से बारहों महीने पानी जमा रहता है। कई बार मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कहा है, जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा है, जुवाइंट इंस्पैक्शन किया है लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा और वहां से हजारों की संख्या में लोग पैदल जाते हैं मंडावली और साउथ गणेश नगर के लोग पैदल जाते हैं, बीपीएस मॉल की तरफ और वो पानी, उनके शरीर पर पड़ता है, कीचड़ उनके शरीर पर पड़ता है। तो मंत्री जी से मेरा हाथ जोडकर निवेदन है कि पीडब्ल्यूडी की ये चौड़ी सड़क जो मुख्य रोड है, इसपर सालों से पानी जमा हुआ है, बारहों महीने पानी रहता है, उसको रोड को ठीक कराने की कोशिश करें और वहां से पानी का जो जमावड़ा है वो खत्म हो ताकि जनता को लाभ मिल सके, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, जब 280 पढ़ें, मुझे सम्बोधित करके, अवसर दिया, आभार अध्यक्ष जी का, ये लाइन छोड़ दीजिए समय बचाइए। सीधा माननीय अध्यक्ष महोदय, अपना पढ़ना शुरू करें। भावना गौड़ जी।

श्री अभय वर्माः माननीय अध्यक्ष जी मंत्री जी बैठे हैं एक बार संज्ञान ले लें।

माननीय अध्यक्षः अब वो मंत्री जी ने सुन लिया, देख लिया, वो मैं उनसे इस विषय पर नहीं। भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़: धन्यवाद अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पानी के बिलों की समस्या की ओर दिलाना चाहती हूँ । मेरे पालम विधानसभा क्षेत्र में बिना रीडिंग लिए पानी के बिलों को जारी रखने की प्रक्रिया संबंधित मीटर रीडरों एवं क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों द्वारा चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय बिना रीडिंग लिए अनाप–शनाप राशि के बिल पालम विधान सभा क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं जिसे बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। जिन मीटरों की रीडिंग ली भी जाती है उनके बिल भी वास्तविक खपत से ज्यादा और बहुत ज्यादा राशि के भेजे जा रहे हैं और यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। इतना ही नहीं, यदि उपभोक्ता इसकी शिकायत करने के लिए क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी के कार्यालय में जाता हैं तो उसकी सुनवाई नहीं होती, जिसके कारण क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है।

अतः अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कराने की कृपा करें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: जरनैल सिंह जी, सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय आपने 280 में मुझे मौका दिया आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय मुझे ये लगता है कि हम सबकी पीड़ा होगी। माननीय मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पीडब्ल्यूडी मंत्री का। मंत्री जी जो एक, दिल्ली के अंदर खासकर के मेरे अपने क्षेत्र के अंदर मैंने इस पीड़ा का अनुभव किया है कि सड़कें खुदी रहती है। कभी एमटीएनएल खोद देता है, कभी एयरटेल खोद लेता है, कभी टाटा खोदता है, कभी आईजीएल खोदता है। तो ये जो continuous परम्परा चलती रहती है और wastage of money है पीडब्ल्यूडी के रोड्स बनते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है। जल बोर्ड भी खोद लेता है उसको तो मेरा सुझाव था जो मैंने काफी अध्ययन किया उसके बाद मैं सुझाव के ऊपर आया हूं कि सडक की re-designing हो। सैन्ट्रल अभी होकर आ रहा है जो–जो आपकी basic amenities की जो फैसिलिटीज हैं ये सड़क के बीचों–बीच होती हैं। जब भी कोई सीवर लाईन

ठीक करनी हो उसको बीच में खोदना पड़ता है। पाइप लाईन ठीक करना है तो बीच में खोदना पड़ता है। तो अगर सड़क के साइडों में flappable corridor हो कि flap को खोला अपने amenity को निकालो, उसको ठीक कर लो और बंद कर लो। मेरा आपसे ये हाथ जोड़कर विनती है कि आप बहुत अच्छी सड़क बनाते हैं, जो सड़क बनाते है वो अद्धितीय बनती है। अगर तीन इंच मोटी हो तो तीन इंच ही बनता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी achievement है जो कि करप्शन फ्री Goverenment को दर्शाता है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं। लेकिन जो सड़क बनते के साथ ही कोई बहुत पहले सरकार में एक प्रोविजन भी आया था कि भई इसका moratorium period हो पांच साल तक के लिए कि अगर सड़क बन रही है तो पांच साल तक के लिए उसको कोई भी एजेंसी खोदेगी नहीं। कोई भी एजेंसी उसको छूएगी नहीं जब तक कि वो पीरियड खत्म नहीं होता है। तो इसका कुछ पालन हो जिससे की जो हजारों करोड़ खर्च कर रहे हो सड़क के ऊपर उसको बचाया जा सके और एक European standard है कि सड़क के दोनों तरफ corridor बना करके उसमें सारी facilities accommodate कर दी जाए कि जब भी किसी को correct करना हो तो उसको खोले correct करें और बंद कर दें। धन्यवाद आपका।

माननीय अध्यक्षः नरेश यादव जी आ गए हैं।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने नियम 280 के तहत मेरी विधान सभा की समस्या उठाने का मौका दिया । अध्यक्ष जी, मेरा क्षेत्र महरौली बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है। बहुत ही ऐतिहासिक शहर है लेकिन महरौली के अंदर लगातार मैं इस सदन में भी ये समस्या उठाता रहा हूं, पानी की एक विकट समस्या है। अध्यक्ष जी, वहां पर पानी के चार यूजीआर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मेरे पिछले टैन्योर से भी पहले वो स्टार्ट हुए थे लेकिन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 25 दिसम्बर, 2019 को किशनगढ़ यूजीआर का जो यूजीआर कम्पलीट हो गया था वहां पर पम्पिंग स्टेशन कम्पलीट हो गया था उसका उद्घाटन किया था। माननीय सीएम साहब ने उसी उद्घाटन के दौरान ही जल बोर्ड के अधिकारियों को ये आदेश दिये थे कि इस एरिया में जो किशनगढ़ एरिया लगता है वार्ड नम्बर–2 महरौली

लगता है वार्ड नम्बर–3, महरौली, गढ़वाल कालोनी बाल्मीकि बस्ती ये सारे एरिया में जहां पानी पांच से छः दिन के बाद मिलता है वहां पर हर दिन पानी आना चाहिए या एक दिन छोड कर पानी की व्यवस्था की जाए। लगातार मेरे फोलोअप करने के बाद भी अध्यक्ष जी दिल्ली जल बोर्ड वालों ने ये चीजें ठीक नहीं की। हमारे माननीय वाइस चेयरमैन साहब राघव चड्ढा जी को भी मैने इसके बारे में बताया कि इसका उद्घाटन माननीय सीएम साहब ने किया था। लोग हमें बोलते हैं इस बारे में कि आप लोगों ने उद्घाटन कर दिया, इलेक्शन से पहले ये दुरूस्त नहीं हुआ। तो जल बोर्ड के अधिकारियों को ये निदेश दिया जाए माननीय अध्यक्ष जी कि वो एरिया जो वार्ड नम्बर–2, वार्ड नम्बर–3 का है वहां पर पानी कम से कम एक दो दिन के गैप में आ जाए पांच छः दिन की बजाए। तो माननीय अध्यक्ष जी पानी की समस्या के लिए मैने यहां पर ये अगर महरौली की बात करूं तो शायद चौथी बार उठा रहा हूं। मैं माननीय मंत्री साहब से भी निवेदन करूंगा कि इस पर आप भी संज्ञान लें क्योंकि उसमें हमारी भी एक रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है कि हम लोग उसका उद्घाटन कर चुके हैं उसके बाद भी वो यूजीआर चालू नहीं हुआ है। आपसे निवेदन है अध्यक्ष जी कि दिल्ली जल बोर्ड को भी यह निर्देश दिया जाए और पानी के लिए हमारी सरकार का भी एक सपना है कि हर दिन पानी मिले, चौबीस घंटे पानी मिले। उसके लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए। बहुत–बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी जो आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री भूपेन्द्र सिंह जून जी।

श्री भूपेन्द्र सिंह जूनः थैंक्यू सर। सर हम सभी जानते हैं कि summer season में fire incident दिल्ली में बढ़ जाती हैं। बिजवासन विधान सभा के महिपालपुर एरिया में तकरीबन 400 छोटे–बड़े होटल्स, restaurants, guest house और पीजी होस्टल चल रहे हैं जो कि Delhi Fire safety Act का टोटल violation करते हैं और सबसे बड़ा culprit है एमसीडी। दिल्ली फायर सर्विस एमसीडी से एक एनओसी मांगता है कि ये बताइए कि बिल्डिंग की हाईट कितनी है। पन्द्रह मीटर की बिल्डिंग का वो सर्टिफिकेट दे देते हैं कि बिल्डिंग की हाईट 12 मीटर है और 12 मीटर में फायर एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे–ऐसे होटल्स है सर जहां पर फायर

टेंडर पहुंच ही सकता। इनफैक्ट ये सारे के सारे tiffin bomb पर बैठे हुए हैं। अगर कोई incident हो गई तो जानमाल की बहुत हानि होगी। दूसरा सर, mostly जो है, कोई भी फायर सेफ्टी measures ऑडिट नहीं कराता। ना किसी के पास smoke management system है ना कोई evacuation plan है ना कोई regular mock drill होती है। Secondly Sir, जो ईश्यू आता है वो Fire Safey Act में lacunaes की उस lacuna के according अगर 12 मीटर बिल्डिंग की हाईट है, गैस्ट हाउस उसमें चल रहा है तो फायर एनओसी की जरूरत नहीं पडेगी। अगर रेस्टोरेंट है उसमें पचास से सिटिंग कम है और 90 meter से एरिया कम है तब भी फायर एनओसी की जरूरत नहीं पडेगी। पीजी होस्टल में अगर 15 मीटर की हाईट पर चल रहा है तो उस पर भी फायर एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो Fire incident तो Sir single storey house में भी हो सकता है। तो फायर सेफ्टी एक्ट को amend करना चाहिए। हर बिल्डिंग्स को जितने कमर्शियल युनिट्स है उन सबको उस में include करना चाहिए। दूसरे हर साल third party Fire audit होना चाहिए ताकि लोगों की जान–माल की सुरक्षा की जा सके। बहुत–बहुत धन्यवाद सर।

माननीय अध्यक्षः थैंक्यू। पवन कुमार शर्मा जी। पवन कुमार शर्मा बोला है मैने। पवन कुमार शर्मा। चलिए पवन जी।

श्री पवन शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान आदर्श नगर विधान सभा के वार्ड–16 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ए–101 इसके सामने एक पार्क है और वहॉ लगभग आधे पार्क में बिल्डर, जेई और पुलिस की मिलीभगत से एक अवैध निर्माण कर दिया है, कब्जा कर लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियन्त्रण करने के लिए पर्यावरण के लिए इतने अच्छे अथक प्रयास कर रही है और दूसरी तरफ एमसीडी और पुलिस मिलकर पार्को पर कब्जा करवा रही है। अध्यक्ष महोदय, वार्ड–16 में जेई अवधेश शर्मा है और काउंसलर है मुकेश गोयल। वहां पर अवैध निर्माण चाहे ये होटल बनाना हो, इन होटलों में illegal गतिविधियां होती है। आए दिन क्षेत्र के निवासी कम्पलेंट करते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अवधेश जेई पर और बाकी सिस्टम पर सख्त से सख्त कार्रवाही करवाई की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष : श्री गिरीश सोनी जी।

श्री गिरीश सोनी: धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से वार्ड नम्बर–1 और वार्ड नम्बर–2 मादीपुर विधान सभा के अंदर चार से पांच हजार जूता फैक्ट्री है तो मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को ये बताना चाहता हूं कि ये जो जूता फैक्ट्रियां हैं। मैने विधान सभा के माध्यम से पहले भी पता किया था कि दिल्ली के अंदर एक भी फुटवीयर मैकिंग या designing institute नहीं है। अब चार से पांच हजार फैक्ट्रियां वहां है मादीपुर के अंदर और वहां पर लगभग 20 से 25 हजार लोग इस व्यवसाय पर dependent है और वहां अगर एक फुट वीयर training institute खोला जाए और वहां footwear designing institute खोला जाए तो मैं समझता हूं जूता उद्योग एक इतना बड़ा उद्योग है जिस तरह गारमेंट उद्योग होता है जूता उद्योग उस बड़े उद्योग में आता है। जिसमें बड़ी–बड़ी विदेशी कम्पनियां भी involve है। मैं ये चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसको संज्ञान में लिया जाए शिक्षा मंत्री जी का सपना भी है। अभी मैं बजट भाषण में सुन रहा था कि वो बता रहे थे कि हम चाहते है कि ऐसे छात्र हम बनाएं जो दूसरो को भी रोजगार दें। मैं समझता हूं कि इसके माध्यम से एक क्वालिटी फुटवीयर बनाना वहां के लोग सीखेंगे और फुटवीयर के माध्यम से दिल्ली के अंदर मादीपुर का नाम काफी रोशन होगा और मैं समझता हूं कि इस उद्योग की वहां इनको ट्रेनिंग मिलने लगे तो एक क्वालिटी फुटवीयर बनने लगेगा और हम उसके माध्यम से काफी बड़ी विदेशों की जो कम्पनियां यहां एन्टर कर रही हैं, हमारा फुटवीयर वहां मादीपुर का विदेशी कम्पनियों से टक्कर ले पाएगा। वहां कोई जूता मंडी भी खोली जाए तो इसमें काफी हद तक विकास आ सकता है और खुद ब खुद वहां के लोग दूसरों को रोजगार देने के लायक बनेंगे ये ही मेरा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध कि इस बात को संज्ञान में लें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। अखिलेशपति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: अध्यक्ष जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं उठाना चाहता हूं आपके सामने। ये केवल मेरा विषय नहीं है। अभी तो सदन में बैठे हुए सारे सदस्यों से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रीविलेज कमेटी का चेयरमैन

हूं और मैं कई बार सदस्यों से बात होती है। कई बार सदस्यों ने पत्र भी लिखें हैं जिसके बारे में मैने आपको सूचना भी दी कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा लगातार जब हमारे सदस्य चिट्टी लिखते हैं तो उसका कोई जवाब उनको पत्रों का नहीं मिलता। जबकि इसी सदन में यह तय किया गया था कि इस तरीके के अगर कोई भी बात होती है तो उसके लिए उचित मैकेनिज्म बनाया जाएगा और उस पर कार्रवाही भी हुई। आपके दिशा निर्देश के अनुसार माननीय मुख्य सचिव ने एक सर्कूलर निकाला और सर्कूलर संख्या मैं पढ़कर बताना चाहता हूं। सीएस/202010362–10363. इसमें कहा गया कि अगर कोई भी अधिकारी/ कर्मचारी चाहे वो दिल्ली सरकार का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे दिल्ली विकास प्राधिकरण का हो या और किसी ऐजेंसी का हो अगर माननीय सदस्यों के द्वारा लिखे गए पत्रों का जवाब नहीं देते तो एक तरीके से misconduct माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन अध्यक्ष जी बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बार–बार वो सर्कूलर लगाकर देने के बावजूद या तो इन लोगों में डर खत्म हो गया है या किसी और तरीके के राजनीतिक संरक्षण के तहत काम कर रहे हैं और चिट्ठियों का जवाब नहीं देते। पीछे अजय दत्त जी ने चिटठी दी, पीछे और माननीय सदस्यों ने चिट्ठी दी और साथ–साथ नरेश जी ने अभी एक बात उठायी कि 280 में जो प्रश्न उठाए जाते हैं यहां पर, हम लोग लोक महत्व के विषय उठाते हैं यहां पर। बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि केवल–केवल वो एक फोरमेलटी बन के रह गया है। हम लोग यहां पर विषय उठाते हैं और उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं होता। उस पर क्या चल रहा है, क्या कार्रवाही होगी, क्या जवाब दिया जाएगा, आज तक उसकी कोई सूचना ही प्राप्त नहीं हो पाती। कोई अधिकारी उस पर क्या कार्य प्रगति कर पाया है उसकी भी सूचना अभी तक सदस्यों को प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये बहुत खेद का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर सदन का संरक्षक होने के नाते आपसे उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द और मैं सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि भई आप लोगों ने जितनी भी चिट्ठियां लिखी हैं और जवाब नहीं आया है, माननीय अध्यक्ष जी को दिया जाए और कोई मजबूत और ठोस नीति बना कर इस पर कार्रवाही करने का कष्ट करें। बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः अंतिम श्री जितेन्द्र महाजन जी।

श्री जितेंद्र महाजनः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान रोहताश नगर विधान सभा में पड़ने वाले पीडब्लयूडी के रोड़ों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। रोहताश नगर विधान सभा के अंतर्गत आने वाले लोनी रोड़, बाबरपुर रोड़ और रोड़ नंबर 65 को चौड़ा करने का प्रपोजल अनेक वर्षों से लंबित है। अनेक बार स्थानीय पीडब्ल्यूडी द्वारा इन रोडों पर निशान लगाए गए और नोटिस दिए गए, मगर अभी तक इनके ऊपर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। रोड़ नंबर 65 जिसका मामला कोर्ट में लंबित था उसके ऊपर भी अब कोर्ट से फैसला आ चुका है। मगर रोड़ नंबर 65 के ऊपर रोड़ नंबर 65 को खोलने का अभी तक भी कोई प्रयास जो है वो संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से संबंधित अधिकारियों से ये जानना चाहता हूं कि इन रोडों को चौड़ा करने का प्रस्ताव कहां अटका हुआ है और इन्हें कब तक चौड़ा किया जाएगा। धन्यवाद जी।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण श्री अमानतुल्ला खां व अब्दुल रहमान जी अल्पसंख्यक कल्याण समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री अमानतुल्ला खानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अल्पसंख्यक कल्याण समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं।[1] अध्यक्ष जी, मैं इस पर कुछ बोलना भी चाहता हूं। ये बड़ा अहम मुददा है।

माननीय अध्यक्षः पांच मिनट अपनी बात रख लीजिए।

श्री अमानतुल्ला खानः पांच मिनट बाद रख लेंगे।

माननीय अध्यक्षः नहीं पांच मिनट के लिए बात रख लीजिए।

श्री अमानतुल्ला खानः पांच मिनट थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिए।

माननीय अध्यक्षः शुरू करिए।

---

1 दि० वि० स० पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–21820 पर उपलब्ध

श्री अमानतुल्ला खानः अध्यक्ष जी, पिछले साल दिल्ली में नार्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में फसाद हुआ। उसमें वहां के जो विधायक थे उनके जरिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड़ के जरिए और वहां के कुछ लोगों के जरिए हमें ये शिकायत मिली कि दिल्ली फसाद में जो लोग मर गए थे दिल्ली सरकार ने उनको दस लाख रूपये जिनकी प्रोपर्टीज का नुकसान हुआ था एक फ्लोर के पांच लाख, दो फ्लोर के दस लाख और जो इन्जर्ड थे उनको दो लाख रूपये देने का ऐलान किया था तो कुछ लोगों को वो नहीं मिल पाया था या कम मिला था या सर्वे में कुछ चीज छूट गई थी वो शिकायत हमको मिली। तो हमने समिति में इस चीज को रखा और हमने एक–एक करके सब लोगों को मुआवजा देने का दिल्ली सरकार से काम किया। दिल्ली के अंदर ये फसाद हुआ इसमें जो लोग मारे गए, उनकी टोटल तादाद 54 थी। फिफ्टी फोर थी जिसमें 11 हिंदु भाई थे और 43 मुस्लिम भाई थे। दिल्ली सरकार ने एक–एक को दस लाख रूपया देने का काम किया। टोटल के टोटल को 54 के 54 लोगों को दिल्ली सरकार ने दस–दस लाख रूपये देने का काम किया। उसके अलावा जो इन्जर्ड थे वो 244 लोग थे। दो सौ 44 के 244 लोगों को मुआवजा देने का काम किया। जो residential property थी वो 724 प्रोपर्टीज को दिल्ली सरकार ने कम या ज्यादा मुआवजा देने का काम किया। जो कमर्शियल प्रोपर्टीज थी वो 1190 कमर्शियल प्रोपर्टीज थी जिनको हमने मुआवजा देने का काम किया। अभी तक दिल्ली सरकार ने 27 करोड़ 19 लाख रूपया इसमें मुआवजा दिया, जिन लोगों के घर जले या जिनके घर वाले मरे या इन्जर्ड हुए या कारोबार तबाह हुए। सैंतालिस लोग ऐसे हैं कि जिनको जो कमर्शियल प्रोपर्टीज थी अभी तक कुछ नहीं मिला तो वो हमने डिविजनल कमिशनर से परमीशन लेकर, रेवेन्यू मिनिस्टर से परमीशन लेकर उनको भी मुआवजे के लिए हमने भेज दिया है। छियासठ लोग ऐसे हैं रेजीडेंशियल में जिनको मुआवजा नहीं मिला। हिंदुस्तान में आजादी के बाद से 48 हजार फसाद हुए, 48 हजार फसाद में पहली ऐसी सरकार है जिसने एक–एक आदमी को ढूंढ कर मुआवजा देने का काम किया। इन 48 हजार फसाद में से ज्यादातर फसाद कांग्रेस हुकुमत में हुए, कांग्रेस ने कराए। जैसे मुरादाबाद फसाद, ईदगाह के अंदर बेकसूर मुसलमानों का कत्लेआम कांग्रेस ने किया। मलियाना कांड, पीएसी के जरिए बेकसूर मुसलमानों का कत्लेआम कांग्रेस हुकुमत ने किया। भागलपुर में बिहार के अंदर कांग्रेस् की हकुमत थी, सैन्टर

में भी कांग्रेस थी और स्टेट में भी कांग्रेस थी वहां पर फसाद भागलपुर में कत्लेआम कांग्रेस ने किया। फिरोजाबाद में कांग्रेस ने किया, अलीगढ़ में कांग्रेस ने किया। उसके अलावा 92 में पूरे हिंदुस्तान में फसाद हुआ था। अकेले महाराष्ट्र में तीन हजार से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ था। उस वक्त में पूरे हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुकुमत थी। 2002 में जब गुजरात में फसाद हुआ तो वहां पर भाजपा की हुकुमत थी, कत्लेआम हुआ। आज तक इन लोगों ने किसी एक आदमी को मुआवजा देने का काम नहीं किया। दिल्ली के अंदर जो फसाद हुआ बीजेपी के लोगों ने फसाद कराया था।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः अमानतुल्ला जी, अमानतुल्ला जी

श्री अमानतुल्ला खानः भाजपा के लोगों ने फसाद कराया।

माननीय अध्यक्षः अमानतुल्ला जी, आप अपनी रिपोर्ट रखिये।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः मुझे अपनी बात तो करने दीजिए।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः अमानतुल्ला जी, आप अपनी रिपोर्ट तक सीमित रहिए। देखिए एक सैकिण्ड। भई आप दो मिनट बैठेंगे।

....व्यवधान....

श्री अमानतुल्ला खानः ये कैसे कह सकते हैं।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः अमानतुल्ला जी।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः अमानतुल्ला जी

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः मैं, बैठिये, बैठिये। मैं खड़ा हूं। मैं रोक रहा हूं।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः बाजपेयी जी आपका तरीका ठीक नहीं है।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः मैं खड़ा हूं आप चलिये कुर्सी पर, चलिये आप कुर्सी पर। आपने रोज का तमाशा बना रखा है। जाइए अपनी कुर्सी पर।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः मार्शलस बाजपेयी को बाहर निकालिये और पूरे दिन के लिए बाहर निकालिए, अनिल बाजपेयी को। बाहर निकालिए अनिल बाजपेयी को। आपने तमाशा बना रखा है रोज। बाहर निकालिए इसको। जो मर्जी आए वेल में आए। बाहर निकालिए इनको। समझते नहीं हैं। सारे सदन को अनिल बाजपेयी जी को बाहर निकालिए तुरंत।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः देखिए,

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः देखिए, ऐसे नहीं चलेगा। ये वैल में क्यों आए। मैं खड़ा हूं और वैल में..

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः आप सुनने देंगे मैं क्या डायरेक्शन..

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः मैं क्या रूलिंग दे रहा हूं सुनेंगे। भाई साहब सुनेंगे मैं क्या रूलिंग दे रहा हूं? मैं क्या रूलिंग दे रहा हूं सुनेंगे? आप सुनने को तैयार नहीं हैं। देखिए अगर वेल में आएंगे, वेल में आएंगे मैं सहन नहीं करूंगा। आप, मैं चैतावनी दे रहा हूं वापस जाइए। मैं खड़ा हूं, मैं बात कर रहा हूं। भई, अमानतुल्ला जी। अमानतुल्ला जी एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। अमानतुल्ला जी। अमानतुल्ला जी। मैं कुछ कह रहा हूं न। मैं अमानतुल्ला जी ये ठीक नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है। आप आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। अमानतुल्ला जी मैं कुछ आग्रह कर रहा हूं।

...व्यवधान.....

श्री अमानतुल्ला खानः XXXX[2]

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः अमानतुल्ला जी मैं सबकुछ कार्यवाही से निकलवा रहा हूं। आप बैठ नहीं रहे। मेरे खड़ा होने के बाद, मेरे खड़ा होने के बाद जो भी अमानतुल्ला ने या किसी और सदस्य ने बोला है उसको कार्यवाही से निकाल दीजिए। मेरे खड़ा होने के बाद जो भी कुछ बोला गया है अमानतुल्ला जी ने या किसी और सदस्य ने वो बाहर निकाल दीजिए कार्यवाही से बाहर निकाल दीजिए। मैंने दे दिया डायरेक्शन दे दिया। अब मैंने दे दिया अब आप बैठेंगे। आप बैठेंगे जब ही बात बनेगी। अमानतुल्ला जी।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः भाई साहब आप ये बिधूड़ी जी ये सफाई मत दीजिए। ये सफाई सदन में देने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा दल या छोटा दल। मुझे मालूम है कितना दल है। मैंने भी जिया है देखा है सबकुछ। अमानतुल्ला जी। अमानतुल्ला जी मेरी बात सुन लीजिए एक बात अमानतुल्ला जी। मैं कुछ बोल रहा हूं आपको

---

2 XXXXX चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

आप सुन नहीं रहे। आप बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं हैं। अमानतुल्ला जी वो माइक बंद है। मैंने बोल दिया वो जब तक खड़े हैं।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः अमानतुल्ला जी। ये जो कुछ आप बोल रहे हैं कार्यवाही में नहीं आएगा। आप जितना बोल रहे हैं ये कार्यवाही में नहीं आने वाला। बोलते रहिए। ये कार्यवाही में नहीं आएगा।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः उनका माइक बंद है। उनका माइक बंद है देख लीजिए माइक बंद है या नहीं।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः अमानतुल्ला जी ऐसे बोलने का कोई लाभ नहीं होने वाले। ये ये रिकॉर्ड में नहीं आ रहा जो कुछ आप बोल रहे हैं रिकॉर्ड में नहीं आ रहा। ये रिकॉर्ड में नहीं आ रहा जो कुछ आप बोल रहे हैं और मैं डायरेक्शन दे चुका हूं। भाई मैं डायरेक्शन दे चुका हूं या तो मुझे बोलने दीजिए व्यवस्था देने दीजिए। अब मुझे व्यवस्था देने दीजिए।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः झा साहब बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए। आप बैठेंगे ओम प्रकाश जी बैठिए।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए प्लीज बैठिए। अभी रहमान जी बैठिए आप। झा साहब बैठ जाइए। रितुराज जी। सोमनाथ जी। बैठिए प्लीज बैठिए अमानतुल्ला जी बैठ जाइए। अमानतुल्ला जी, अब मैं डायरेक्शन दे लूं कुछ मुझे, नहीं मुझे बोलने देंगे। अमानतुल्ला जी एक तो सभी सदस्यों से मेरी ये प्रार्थना है जो भी कमेटी की

रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाती है और उस पर बोलने की इजाजत मांगते हैं, भविष्य में ध्यान रखें उस रिपोर्ट तक हमको सीमित रखना है। रिपोर्ट से बाहर अगर बोलेंगे, रिपोर्ट के बाहर जाएंगे वो कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा। नहीं एक सेकंड सुन लीजिए बात को ऐसे नहीं अमानतुल्ला जी प्लीज। मेरी बात को एक बार समझने का प्रयास करिए। कमेटी की रिपोर्ट जो आपने दी है उस तक हमारी चर्चा उस पर कोई टिप्पणी करनी है उस तक हमको सीमित रहना चाहिए और। भई अमानतुल्ला जी मैं बोल रहा हूं न।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः मैं बोल रहा हूं न। एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दो। मेरी बात पूरी होने दो। एक सेकंड वो रिपोर्ट मैंने देखी है सब कुछ पढ़ा है, समझा है कपिल मिश्रा का जहां तक सवाल है वो हाईलाइट हुई उसके विषय में उस रिपोर्ट में आपने वीडियो दिया है वहां तक अपने आप को सीमित रख सकते थे, रखना चाहिए था।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः भई अमानतुल्ला जी अब बैठ जाइए। अब ये, अब मैं और समय नहीं दे रहा हूं हो गया 15 मिनट लग गए। नहीं अब मैं समय नहीं दे रहा मैं। नहीं आप बैठ जाइए मोहन जी। मैं किसी को समय नहीं दे रहा हूं अब न बैठ जाइए प्लीज। भाई साहब मैं किसी को समय नहीं दे रहा हूं। मैंने जब उनको नहीं बोलने दे रहा, उनको नहीं बोलने दे रहा। नहीं ऐसे नहीं अलाऊड है। मैं ऐसे नहीं अलाऊ करूंगा। मैं ऐसे अलाऊ नहीं करूंगा। मैंने रोका है उनको रोक दिया। उनकी कार्यवाही से निकलवा दिया। बैठ जाइए। किसने कह दिया आपसे, आपसे किसने कह दिया रिपोर्ट में समय नहीं दे सकते। कमेटी की कोई रिपोर्ट आएगी उसमें कोई भी चर्चा करवा सकता है।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः बैठिए। अमानतुल्ला जी अब बैठिए, अब बैठ जाइए प्लीज। बैठ जाइए। न मैं इस पर और चर्चा। मैं और चर्चा अलाऊ नहीं कर रहा हूं।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः मैं इस पर और अलाऊ नहीं कर रहा। मेरे से मिल लीजिएगा। मेरे से मेरे चेम्बर में मिल लीजिएगा। नहीं मेरे से मेरे चेम्बर में मिल लीजिएगा। नहीं मैं अब अलाऊ। मैं किसी की बात। नहीं मैं किसी की बात नहीं सुन रहा हूं अब। मैं बिल्कुल नहीं सुनुंगा। अमानतुल्ला जी मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहूंगा बैठिए अब। अब बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः श्री सही राम जी, करतार सिंह तंवर जी। अब आप बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। अरे मैंने उनको रोक दिया इमीजेट।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः आप जानते हैं सदन के बारे में, आप जानते हैं सदन के बारे में। नहीं सदन के बारे में आप जानते हैं। तमाशा बना रखा है यहां। हद हो गई गुंडगर्दी की। पूरे देश को तमाशा बना कर रखा हुआ है आप लोगों ने। बैठ जाइए अब।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः आप बैठ जाइए मोहन जी बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। अब बहुत हो गया।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः नहीं मैं अब, नहीं मैं अब अलाऊ नहीं। मैं अमानतुल्ला जी अलाऊ नहीं करूंगा। ऐसे सदन की, न मैं बिल्कुल अलाऊ नहीं करूंगा। मैं अलाऊ नहीं करूंगा। न मैं अलाऊ नहीं करूंगा। मैं अब बिल्कुल अलाऊ नहीं करूंगा। आपने सारा समय खराब कर दिया। न।

...व्यवधान.....

श्री सही रामः अरे कुछ और बोलना पड़ जाएगा बैठ जाओ यार, बैठ जाओ प्रस्ताव पढ़ने दो। बैठो, बैठो प्रस्ताव पढ़ रहा हूं बैठो। अरे प्रस्ताव पढ़ने दो। बैठो बैठो।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः 15 मिनट के लिए मैं सदन को पोस्टपोन करता हूं। 15 मिनट के लिए। ठीक 12.15 बजे हम मिलेंगे।

माननीय अध्यक्ष : ठीक सवा बारह बजे हम मिलेंगे। अमानतुल्ला जी एक बार आ जाइए कमरे में।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 12:15 बजे तक के लिए स्थापित की गई)

सदन अराह्न 12.15 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं केवल आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर आप अनुमति दे ंतो बहुत अच्छा होगा।

माननीय अध्यक्ष : बताइए, बताइए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी : आदरणीय अध्यक्ष जी, श्री अमानतुल्ला खॉन साहब की ओर से जो निराधार आरोप भारतीय जनता पार्टी के उपर लगाया गया है। मेरा भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से आपसे ये आग्रह है कि उसको सदन की कार्रवाई से निकाला जाये और हमारे।

माननीय अध्यक्ष : वो मैं आलरेडी कह चुका हूं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी : वरिष्ठ साथी को आज के लिए हाउस सस्पेन्ड कर दिया गया है श्री अनिल वाजपेयी जी को। उनको हाउस में बुलाया जाये क्योंकि बजट के उपर चर्चा हो रही है। वो भी अपना विचार रखना चाहेंगे तो इतना मैं जरूर आपसे फेवर चाहता हूं। ये इसमें आपका, आप सभी हमारी पार्टी की ओर से ये आपसे आग्रह है। आप हमारे आग्रह को स्वीकार करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हू।

माननीय अध्यक्ष : बैठिए। अमानतुल्ला जी, दो मिनट रूक जाइए न। मैं बोल रहा हूं विशेष रवि जी बैठिए। आमनतुल्ला जी दो मिनट बैठिए। एक तो कार्रवाई में जो XXXX[3] शब्द आया है उसको हटा दिया जाये। अनिल वाजपेयी जी को आप बुला लीजिए। आने दीजिए उनको और उन्हें एक बार ये कहके बोलिए कि वो ठीक से मर्यादित होकर बैठें। मैं दो दिन से उनका व्यवहार देख रहा हूं, अनुचित है। मेरी प्रार्थना है, आप समझदार हैं, काफी समझदार हैं। वो मर्यादित होकर बैठें। कोई बात कहनी है तो मर्यादा में बैठकर कहें। मैं सुनूंगा। अमानतुल्ला जी, मेरा ये आग्रह है कि आप इस रिपोर्ट तक अपने आपको सीमित रखें। क्यों, आगे के समय में भी कोई भी चेयरमैन बोलना चाहें तो उसका रास्ता खुला रहे। रिपोर्ट आपकी बहुत अच्छी आयी हुई है। भावनायें बिल्कुल अपनी जगह लेकिन रिपोर्ट अपनी जगह। आप बहुत जल्दी इसको विदिन फाइव मिनट्स पूरा कर दीजिए।

श्री अमानतुल्ला खान : अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष जी, इस पूरे नार्थ–ईस्ट फसाद में तकरीबन साढ़े सात सौ एफआईआर दर्ज हुए। जो दिल्ली पुलिस ने किये। साढ़े सात सौ एफआईआर की कापी दिल्ली पुलिस ने ये कहते हुए पब्लिक डोमेन पर नहीं डाली कि ये बहुत सेन्सेटिव इश्यू हैं इसलिए हम इनको पब्लिक डोमन पर नहीं डाल रहे हैं। समिति ने जब इसको मांगा तो पुलिस ने इसको नहीं दिया। बार–बार हमने मांगा। पुलिस ने इसको हमको नहीं दिया। हमें पॉच एफआईआर ऐसी मिली जिन पर कन्टेन्ट सेम था सिर्फ नाम बदले हुए थे। कन्टेन्ट क्या था कि एक पुलिस वाला जा रहा था तो वहां एक आदमी मिला। उसकी जेब में कट्टा था जो लोडेड था और जो किसी को कत्ल के इरादे से आया हुआ था उसको गिरफ्तार कर लिया। नाम चेन्ज हो गया, दूसरे का नाम आ गया। तो पॉच एफआईआर ऐसी थी तो उसी बुनियाद पर हमने कहा कि दिल्ली पुलिस हमको जितनी भी एफआईआर है उसकी कापी हमें दे ताकि हमें पता तो लगे कि जिन लोगों ने दंगा कराया या जो दंगे में मौजूद थे उनके खिलाफ किन–किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया ये हमें पता लगे लेकिन दिल्ली पुलिस ने बार–बार कहने के बावजूद कमेटी को एफआईआर की कापी नहीं दी और जब हमने आर्डर मांगा भी

3 XXXX चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

कि किस आर्डर के बुनियाद पर तो उन्होंने कहा 2011 का कोई हाईकोर्ट का आर्डर है जिसकी बुनियाद पर हम आपको कापी नहीं दे सकते। 2020 में दंगा हुआ। आप आर्डर की बात कर रहे हो। 2012 के तो क्या वजह थी जिस वजह से आपने समिति को या किसी भी आदमी को एफआईआर की कापी नहीं दी। इस पर दिल्ली पुलिस की मंशा पर सवाल खड़ा करना लाजमी है। दूसरा जो लोग सीएए, एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि सीएए, एनआरसी लोगों को एक कम्यूनिटी को लगता था कि ये कानून उनके खिलाफ है और हिन्दूस्तान के आईन ने ये हक दिया है कि अगर कोई हूकूमत कोई कानून बनाये या कोई ऐसी चीज जिससे लोगों को लगे कि ये हमारे खिलाफ है तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अख्तियार उस कम्यूनिटी को या वहां के लोगों को है। उस बुनियाद पर सीएए, एनआरसी का प्रोटेस्ट किया। इन्होंने क्या किया कि जो लोग सीएए, एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे इन लोगों ने उनको जेल में डालने का काम किया। किन धाराओ में? उन पर सब पर 302 लगाये। दंगे की एक एफआईआर की इन्होंने। उस एफआईआर में तमाम धारायें।

.....व्यवधान.....

श्री अमानतुल्ला खान : आप यह तो बोलने नहीं देंगे। अब तो मैं भाजपा की बात भी नहीं कर रहा।

माननीय अध्यक्ष : अमानतुल्ला जी, अमानतुल्ला जी।

.....व्यवधान.....

श्री अमानतुल्ला खान : मैं तो भाजपा की बात भी नहीं कर रहा।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष : विजेन्द्र जी, अब इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं रखी है गलत। ऐसी इन्होंने कोई गलत।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : अमानतुल्ला जी रिपोर्ट तक रखिए।

श्री अमानतुल्ला खान : मैं रिपोर्ट पर आ जाता हूं।

माननीय अध्यक्ष : हॉ रिपोर्ट पर आइए। बोलिए।

श्री अमानतुल्ला खान : रिपोर्ट पर आ जाता हूं मैं।

माननीय अध्यक्ष : रिपोर्ट पर आ जाइए प्लीज।

.....व्यवधान.....

श्री अमानतुल्ला खान : गुप्ता जी बैठिए आप। विजेन्द्र गुप्ता जी बैठिए, विजेन्द्र गुप्ता जी बैठिए आप। आप बैठिए। विजेन्द्र गुप्ता जी बैठिए आप। हमने ये उनसे पूछा कि ये बताओ दिल्ली पुलिस कि तुमने कितने लोगों पर यूएपीए लगाया। क्या यूएपीए भी मुसलमान हो गया। यूएपीए जिन लोगों ने कत्ल किया। ये जो 53 लोग, 54 लोगों का कत्ल हुआ, इनमें से जो कत्ल करने वाले लोग हैं उन पर यूएपीए लगाया या जो सीएए, एनआरसी की प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन पर क्यों 302 का कत्ल क्यों लगाया। उन्होंने किसको आकर मारा।

माननीय अध्यक्ष : नहीं इसमें है। मैं देख रहा हूं। हॉ मैं देख रहा हूं।

श्री अमानतुल्ला खान : आप बैठिए न।

माननीय अध्यक्ष : पेज 3 और 4 पढ़िए।

श्री अमानतुल्ला खान : है रिपोर्ट में ये।

माननीय अध्यक्ष : विजेंद्र जी पेज 3 और 4 पढ़िए। पेज 3 और 4 पढ़िए आप।

श्री अमानतुल्ला खान : ये है रिपोर्ट में।

माननीय अध्यक्ष : अमानतुल्ला जी अब क्लोज करिए।

श्री अमानतुल्ला खान : एक आदमी शिफाउर्र रहमान, मिरान हैदर जामिया में प्रोटेस्ट कर रहे थे।

श्री विजेंद्र गुप्ता : यह कहां लिखा है।

.....व्यवधान.....

श्री अमानतुल्ला खान : मैं एक बात कह रहा हूं जामिया में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये बताइए उन्होंने दिल्ली दंगों में किसका कत्ल किया जो इन्होंने 302, 308, 307 और यूएपीए के तहत इनको जेल में डाल रखा है। अकेला वो नहीं है। उमर खालिद, उमर खालिद पर इन्होंने।

माननीय अध्यक्ष : अमानतुल्ला जी। इस तक सीमित रहिए। प्लीज।

श्री अमानतुल्ला खान : इशरत जहां पर लगाया। हमें।

माननीय अध्यक्ष : अब कन्क्लूड करिए।

श्री अमानतुल्ला खान : साढ़े सात सौ एफआईआर की रिपोर्ट इनसे इसलिए मांगी ताकि सच्चाई सामने आ सके।

माननीय अध्यक्ष : कन्क्लूड करिए अमानतुल्ला जी।

श्री अमानतुल्ला खान : अध्यक्ष जी,

माननीय अध्यक्ष : भाई अजय जी, महावर जी वो रिपोर्ट तक सीमित हैं। महावर जी ऐसे नहीं चलेगा। वो रिपोर्ट तक सीमित है। मैं टोक रहा हूं बार–बार। रिपोर्ट पूरी पढ़ लीजिए।

श्री अमानतुल्ला खान : हमने रागिनी तिवारी की दंगे वाली वीडियो जिसमें वो दंगा कर रही है, पथराव कर रही है, लोगों के बीच में है, उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, न उसके खिलाफ एफआईआर की। आज वो बाहर घूम रही है। कपिल मिश्रा जो वहां मौजूद था दंगे के टाइम में। इसने चैलेन्ज किया था कि अगर प्रोटेस्ट नहीं हटा तो दंगा होगा, दिल्ली जलेगी और दिल्ली पुलिस को चैलेन्ज किया था।

माननीय अध्यक्ष : अब कन्क्लूड करिए। अमानतुल्ला जी। अमानतुल्ला जी, अब कन्क्लूड करिए।

श्री अमानतुल्ला खान : उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रवेश वर्मा।

माननीय अध्यक्ष : अमानतुल्ला जी, कन्क्लूड करिए आप।

श्री अमानतुल्ला खान : उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई किसके खिलाफ की? बेकसूर लोगों के यूएपीए लगा करके। हमने वीडियो दी। किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो सवाल उठता है कि किसके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने ये काम किया। क्या इसमें भाजपा इन्वॉल्व नहीं है। क्या भाजपा के गृह मंत्री इन्वॉल्व नहीं है। क्या अमित शाह इन्वॉल्व नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : अमानतुल्ला जी, कन्क्लूड करिए।

श्री अमानतुल्ला खान : दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही थी। दिल्ली पुलिस, ये दंगा भाजपा ने कराया है। ये दंगे को कराने वाली भाजपा है। भाजपा के आदमी।

माननीय अध्यक्ष : अमानतुल्ला जी, अब बैठिए। कन्क्लूड करिए। अमानतुल्ला जी, अब कन्क्लूड करिए। हो गया।

श्री अमानतुल्ला खान : प्रवेश वर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं की। अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई क्यों नहीं की। बेकसूर लोगों पर जो सीएए, एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर 307 लगा दी, 308 लगा दी। आपने तो यूएपीए के कानून को भी मुसलमान बना दिया। वो सारी एक कम्यूनिटी के लोगों को डराने का काम किया।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद अमानतुल्ला जी, कन्क्लूड करिए प्लीज। हो गया।

श्री अमानतुल्ला खान : दंगाई बाहर घूम रहे हैं और जब तक ये दंगे होते रहेंगे तब तक इन दंगाईयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए, अमानतुल्ला जी बैठिए। प्लीज। प्लीज बैठिए।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : अमानतुल्ला जी, अब बैठ जाइए। प्लीज। अमानतुल्ला जी, मैं अब अलाऊ नहीं कर रहा हूं। बैठिए। श्री सही राम जी। सही राम जी, करतार सिंह तंवर जी। श्री सही राम जी ये सदन दिनांक 10 मार्च 2021 को सदन में प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत हैं, बोलिये।

श्री सही रामः धन्यवाद अध्यक्ष जी। गुप्ता जी बैठिये आप। गुप्ता जी बैठ जाओ बहुत हो गयी यार।

माननीय अध्यक्षः चलिये करिये।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी बैठ जाओ।

.....व्यवधान.....

मननीय अध्यक्षः अब इन्होंने जो बोला है। भाजपा पर दंगों का आरोप नहीं लगाया। मैं एक एक शब्द सुन रहा हूं ध्यान से। इन्होंने बोला है कि भाजपा के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर कार्यवाही नहीं हुई उन लोगों पर। आप बैठ जाइये विजेन्द्र जी, नहीं आप बैइ जाइये।

.....व्यवधान.....

श्री सही रामः अरे गुप्ता जी। कपिल मिश्रा किसका था, अनुराज ठाकुर किसका है? वो बीजेपी के नहीं हैं। क्या गलत बोल दिया।

माननीय अध्यक्षः सही राम जी चलिये, प्लीज।

श्री सही रामः माननीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः प्लीज, प्लीज। सही राम जी चलिये।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रसताव करता हूं कि ये सदन दिनांक 10 मार्च, 2021 को सदन में प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, ना कहें

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

सही राम जी, समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 10 मार्च, 2021 को सदन में प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, ना कहें,

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

श्री वीरेंद्र सिंह कादियान जी अपनी समिति का प्रतिवेदन सहमति के लिए प्रस्तुत करेंगे।

श्री वीरेंद्र सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 10 मार्च, 2021 को सदन में प्रस्तुत प्रशासनिक मामलों के विभाग से संबंधित स्थायी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, ना कहें,

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

कॉलिंग अटेंशन रूल 54।

माननीय उप–मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया) : ये जैसा मैंने कल–परसों बजट के प्रस्तावों में भी रखा था कि सरकार आजादी के 75वीं वर्ष गांठ पे पूरे 75 सप्ताह के कार्यक्रम करेगी और उसका आगाज 12 तारीख से होगा। चूंकि सभी माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं तो 12 तारीख को शाम को पहला कार्यक्रम का और इसका एक तरह से इस पूरे श्रृंखला का कार्यक्रम पहला कनॉट प्लेस में आयोजित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर मुख्य अतिथि होंगे और मशहूर गायक प्रहलाद सिंह जी वहां पर देश भक्ति और इस तरह का एक प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे तो उसके कार्ड्स मैंने सभी सदस्यों की टेबल पर रखवायें हैं। 75 सप्ताह तक कार्यक्रम चलेगा। कल इसीलिए यहीं सबके टेबल्स पर मैंने कार्ड रखवा दिये हैं तो मेरी तरफ से सभी माननीय सदस्य वहां पर आमंत्रित भी हैं। आप भी सादर आमंत्रित हैं और सभी, जिनके पास बाय चांस नहीं पहुंचे हों तो यहां से मिल जाएंगे। थैंक्यू।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री विजेंद्र गुप्ता जी कॉलिंग अटेंशन (रूल 54)।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, पिछले तीन दिन से लगातार विपक्ष और आज चौथा दिन है। दिल्ली सरकार द्वारा 1 हजार सीएनजी लो फ्लोर बसेस की खरीद की अनियमिताओं की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था और पिछले काफी वर्षो से डीटीसी में कोई नई बस सरकार द्वारा खरीद कर जोड़ी नहीं गयी और जब ये फैसला लिया गया 1 हजार बस खरीदने का तो उसमें भारी अनियमितताएं हैं, भारी घोटाला है।

माननीय अध्यक्षः अमानतुल्लाह जी प्लीज।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैं कुछ तथ्यों के आधार पर और नियम और कानून के आधार पर मैं आपके समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूं।

पहला विषय ये है कि जो 1 हजार बसें खरीदी गयीं, बसों की कीमत है 875 करोड़ रुपया। उसमें तीन साल की वारंटी इंक्लूड है और तीन वर्ष तक बस कम्पनी 2 लाख 10 हजार किलोमीटर तक उसकी वारंटी पीरियड में कवर होगा 875 करोड़

रुपए। ये टेंडर किया गया मार्च में, मार्च, 2020 को टेंडर हुआ और हैरानी की बात ये है कि जब बस का टेंडर किया गया तो बस की एनुअल मैंटेनेंस कॉन्ट्रेक्ट उसको उसके साथ टेंडर में नहीं जोड़ा गया और फिर उसके बाद तीन चार महीने के बाद एक और टेंडर किया जाता है, जिसमें ए.एम.सी. की बात की जाती है और लगभग 35 सौ करोड़ रुपया उन 1 हजार बसेस की कीमत से लगभग चार गुना हो गया। उनकी एनुअल मैंटेनेंस कॉन्ट्रेक्ट के लिए करार किया जाता है। एक टेंडर किया जाता है अब प्रश्न ये है कि उस 35 सौ करोड़ रुपए में वो पहले तीन साल और 2 लाख 10 हजार किलोमीटर जो वारंटी पीरियड में कवर है। यानि की जिस दिन बसों का बेड़ा सरकार को, डीटीसी को प्राप्त होगा, उसी दिन उसकी ए.एम.सी. भी 70 लाख रुपया प्रारंभ हो जाएगी। 70 लाख रुपया पहले दिन से ही बस की एएमसी तय हो जाएगी, पेमैंट शुरू हो जाएगी। हम लोग गाड़ी खरीदते हैं। गाड़ी में भी तीन सर्विस फ्री होती हैं और एक साल तक तो गाड़ी में, नई गाड़ी में कम्पनी खुद हर प्रकार की सर्विस करके देती है। फिर उसपर वारंटी भी कवर है तो मैंटेनेंस भी करके देती है, वारंटी भी है तो पहले ही साल में अगर इसको एवरेज निकाला जाए तो लगभग 890 करोड़ की बसों पर 300 करोड़ रुपया आप एएमसी का लगभग पे कर देते हैं ऑन एन एवरेज 340 करोड़ रुपया लगभग। दूसरे साल भी इतना कर देते हैं, तीसरे साल भी। अगर टोटल लगाया जाए तो जितने की बसें खरीदी है, उतना ही वारंटी पीरियड पे हम उसको एनुअल मैंटेनेंस कॉन्ट्रेक्ट के तौर पर उस पार्टी को पेमैंट कर रहे हैं पहला विषय।

दूसरा विषय ये है कि जब आपने टेंडर किया 1000 बस का तो जब आप एग्रीमेंट करने गये तो आपने साढ़े 12 सौ बसेस का वर्क आर्डर करने का प्लान बना लिया और उसको डिसाइड कर दिया। एक क्लॉज का अध्यक्ष जी इसमें फायदा उठाने की कोशिश की गयी कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी इमरजेंसी या कोई ऐसा आवश्यकता लगती है तो हम इस टेंडर को 25 परसेंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब टेंडर का ओपनिंग हुई और बोर्ड के सामने आया तो उसके साथ ही आपने तुरंत तभी 1000 की जगह साढ़े 12 सौ यानि 25 परसेंट का अर्थ ये हो गया कि अगर 4500 करोड़ का कॉन्ट्रेक्ट बना है तो लगभग आपने उसको पहले दिन ही 1100

करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्डर करने का तय कर लिया।

तीसरा विषय कि 27 नवम्बर को बोर्ड की मीटिंग होती है और बोर्ड की मीटिंग में ये फैसला लिया जाता है, करारनामा तैयार किया जाता है। पहली बात को और स्पष्ट कर दूं। साढ़े 12 सौ बसों का फैसला ले लिया जाता है। हजार की जगह साढ़े 12 सौ, ढाई सौ बसें अतिरिक्त और फिर उससे अगली मीटिंग में वो ढ़ाई सौ अतिरिक्त बस खरीदने का फैसला वापस ले लिया। अतिरिक्त खरीदने का फैसला वापस ले लिया जाता है। यानि की आपने एक हजार का टेंडर किया। बोर्ड में साढ़े 12 सौ का फैसला लिया और उसके बाद उस फैसले को पलट दिया अगली मीटिंग में।

तीसरा। आपने 27 नवम्बर को बोर्ड की मीटिंग में फैसला लिया और उसके बाद साढ़े तीन महीने तक आज तक डीटीसी की बोर्ड की मीटिंग की एक भी मिनट अपलोड होने में इतना समय नहीं लगा। 8 मार्च को जिस दिन सदन बैठा, उस दिन तक भी वेबसाइट पर बस के जिसमें बस की खरीद का फैसला लिया गया, उसके मिनट्स अपलोड नहीं किए गए। सदन में विपक्ष ने मामला उठाया और नाटकीय ढ़ंग से उसी दिन रात को पहले उसके बाद होने वाली मीटिंग के मिनट्स डाले गए और फिर स्थिति ये विचित्र हो गई कि पहले वाले सारे मिनट्स वेबसाइट पर अपलोड है। बाद वाले अपलोड हैं वो वाला अपलोड नहीं है तो बाद में उसको भी अपलोड कर दिया गया। तो ये जो सरकार की इस विभाग में विशेष रूप से मंत्री जी उसके मंत्री भी है और चेयरमेन भी है बोर्ड के। ये जो चीजें सामने आ रही है ये संदिग्ध के घेरे में पूरी बात को ले जाती है। इसके बाद आपने टेंडर किया 1000 बसिज का। 1000 बसिज का जब आप टेंडर कर रहे हैं तो आप सीधा–सीधा 1000 बसिज का आर्डर एल–1 को दीजिए। एल–1 को आपने 1000 बसिज का आर्डर क्यों नहीं दिया। आपने उसको स्पिलिट कर दिया, ऐसा कहीं नहीं होता फाइनेंशियल रूल्स में कि एल–2 को भी कंसीडर किया जाता है। आपने आर्डर देते हुए किया कि 1000 बसे जो खरीदी जाएंगी उसमें 700 एल–1 से ली जाएंगी, 300 एल–2 से ली जाएंगी। अगर आपको 700 ही लेनी थी तो हो सकता है और बहुत सारी कंपनियां आ जाती जिनकी कैपिसिटी 1000 बसें सप्लाई करने की नहीं है। तो वो उसमें टेंडर में नहीं

आई होगी लेकिन आप कहते हैं कि 700 बसे सप्लाई करनी है और उनकी पोटेंशियल होती तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते। टेंडर करने के बाद वर्क आर्डर के समय जो इसमें तमाम फैसले लिए गए हैं वो कंपनियों को ऐसा साफ रूप से प्रतीत हो रहा है कि शर्तें इस प्रकार से रखी गई है कि एक कंपनी विशेष को इसका लाभ मिल सके। एक कंपनी विशेष जो है इस टेंडर को ले सके।

माननीय अध्यक्षः हो गया।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अभी अध्यक्ष जी, दो–तीन पाइंट है मैं टू दा पाइंट ही बात करूंगा मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। इसके बाद आपने जो कंडीशंस रखी इन बसों को स्पिलिट करके और दूसरा एएमसी में जो वारंटी का मामला है। उसका जो एक डबल पेमेंट हो रहा है ओवरलेपिंग हो रही है पेमेंट में और तीसरा आपने जो 1000 बसिज का टेंडर करके इसको टेंडर को स्पिलिट किया और इसके साथ–साथ आपने एएमसी का टेंडर 4 महीने बाद 3 महीने बाद किया। इसका मतलब ये हैं कि जिस समय आप टेंडर कर रहे थे बसों की खरीद का उस समय इससे पहले जब भी ये इस तरह एएमसी के कांट्रैक्ट हुए वो साथ–साथ हुए हैं टेंडर में, टेंडर के साथ–साथ हुए। इसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि ये सारा मामला डेढ़ वर्ष पहले इसी जेबीएम कंपनी जिसको फेवर किया गया है। ये ही जेबीएम कंपनी को इसी तरह टेंडर दिया जा रहा था। हमने इस मुद्दे को सदन में भी उठाया, एंटी–करप्शन ब्रांच में और बाकी तमाम जगह पर हमने उसकी कंप्लेंट की और जब उसकी इंक्वायरी शुरू हुई, तो परिवहन विभाग ने, मंत्रालय ने वो टेंडर विदड्रा कर लिया। इसी कंपनी को टेंडर देना चाहती थी सरकार वो टेंडर विदड्रा कर लिया और एसीबी को लिखा जो एजेंसी जांच कर रही थी उनको लिखा कि हमने तो टेंडर ही विदड्रा कर लिया, इसलिए इसकी जांच करने का कोई औचित्य जबकि आपने एक ऑफेंस कमिट कर दिया। उसके बाद आपने कोई भी फैसला लिया हो आप ये नहीं कह सकते कि इसकी इंक्वायरी न की जाए। अध्यक्ष जी, मैं संक्षिप्त में ये ही कहूंगा कि इससे सरकारी खजाने को बड़ा भारी नुकसान हुआ है और 3500 करोड़ रुपये में जो एएमसी की जा रही है उसका कोई एस्टीमेट नहीं लगाया गया। आज तक मैंने कहीं नहीं देखा कि आप टेंडर में जा रहे हैं और आपके पास एस्ढीमेटिड कॉस्ट नहीं है। आपके पास

कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपने उसको लिमिट कर दिया क्योंकि जिन कंपनियों ने बस खरीद का टेंडर लिया है, वो ही कंपनियां एएमसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। तो कॉम्पिटिशन को लिमिट किया गया। उसके बाद इसमें ये जो बसिज है इसमें कंपनियों को ये साफ रूप से फायदा दिया गया क्योंकि उसका कोई एस्टीमेट ही नहीं था।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी ये रिपिटेशन हो रहा है।

श्री विजेंद्र गुप्ताः ये रिपिटेशन नहीं है जस्टिफिकेशन और आप कोई टेंडर जाता है 10 परसेंट above जाता है या 10 परसेंट below जाता है।

माननीय अध्यक्षः विजेंद्र जी अब हो गया प्लीज। आपकी बात को पर्याप्त समय मिल गया। सारी की सारी बात आ गई।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैं 15 सेकेंड में मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं। सवाल ये हैं कि जो आपने टेंडर किया उसका एस्टीमेटिड कोस्ट कहां है। उसका जस्टिफिकेशन क्यों नहीं है। कॉम्पिटिशन को आपने करटेल किया लिमिटेड लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन हो और उसका फायदा उनको मिले और जब बस खरीद के आर्डर जिसको दे दिया है। उसको एएमसी आप चार महीने बाद एग्रीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि...।

माननीय अध्यक्षः भई विजेंद्र जी, ये बार–बार रिपिटेशन हो रहा है।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैं जो भी रेट कोट करूंगा मेरे रेट जो है वो मान लिए जाएंगे।

माननीय अध्यक्षः बैठिए–बैठिए। अब माननीय परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी इस संबंध में अपना वक्तव्य देंगे।

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलौत): अध्यक्ष महोदय, पिछले 3–4 दिन से ऐसा एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कोई बड़ा घोटाला हो गया और पब्लिक का पैसा, सरकारी खजाना जो है उसको लूटा जा रहा है। जब भी बसों के खरीदने की बात होती है तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। तो विजेन्द्र

गुप्ता जी की ये फेवरेट हॉबी है कि सबसे पहले एसीबी में कंप्लेंट डालेंगे और फिर उसको हर जगह मार्क करेंगे दिल्ली पुलिस, सीबीआई, एनआईए जितनी एजेंसिज हैं इन्हीं की एजेंसिज हैं सारी। पुलिस भी इनकी है, सीबीआई भी इन्हीं की है और

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः भई विजेंद्र जी अब ऐसे नहीं चलेगा। नहीं–नहीं ऐसे नहीं चलेगा। नहीं आप बैठ जाइए, नहीं आरोप लगाए तो वो जवाब नहीं देंगे। नहीं ये कोई तरीका नहीं है। आपको आराम से सुना है सत्ता दल ने। कैलाश जी बैठिए।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः देखिए एक सेकंड कैलाश जी एक मिनट के लिए बैठिए, एक मिनट के लिए। देखिए विजेन्द्र जी सत्ता पक्ष ने आपको बहुत शांति से सुना है और आपमें इतनी तहजीब नहीं है कि मैं मंत्री जी को सुनूं। कोई तहजीब नहीं है आपमें। किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है लेकिन उसको सुनना, उसका उत्तर सुनना वो उत्तर दे रहे हैं बराबर उत्तर दे रहे हैं और ऑन रिकॉर्ड उत्तर दे रहे हैं। आपको उनके उत्तर में कहीं लगे तो आप चैलेंज कर सकते हैं। हां करिएगा उनको बोलने दीजिए। आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे बीच में। हां जी चलिए, बैठिए बैठिए अब। ये कोई तरीका नहीं है।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः मैं ये समझता हूं आप आरोप लगाकर मैदान छोडकर भागना चाहते हैं। आप उत्तर सुनना नहीं चाहते। नहीं आप आरोप लगा कर भागना चाहते हैं।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः बैठिए प्लीज। माननीय मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। नहीं क्या करें वो बोलने खड़े हुए हैं और विजेन्द्र जी को समझ नहीं आ रहा। उनकी तरफ अंगुली दिखा दिखा के बात कर रहे हैं आफ्टर आल मंत्री बोल रहे हैं। नहीं करवाऊं,

कैसे करवाऊं, वो रूकते नहीं हैं एक सेकंड के लिए भी। वो अंगुली दिखा दिखा कर ऐसे बात कर रहे हैं मंत्री से। ईमानदारी का ठेका इन्होंने उठा रखा है सारा।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः बैठिए प्लीज।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण बैठें प्लीज। प्लीज बैठिए। प्लीज बैठिए। माननीय मंत्री जी एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज। देखिए मैं ये बात समझ रहा था तीन दिन से कि विपक्ष आरोप लगाकर हंगामा करेगा। मंत्री को उत्तर नहीं देने देगा और वो ही जो मेरे मन में, नहीं वो ओमप्रकाश जी रुक जाइए।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः नहीं वो टोक रहे हैं उनको।

श्री ओमप्रकाश शर्माः ये भी टोक रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः नहीं कौन टोक रहा है। विजेन्द्र जी को सुनना चाहिए शांति से ये विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष का काम ये है कि सुनने का माद्दा रखे।

श्री ओमप्रकाश शर्माः मंत्री जी बोलें।

माननीय अध्यक्षः सत्ता पक्ष ने सुना है न। सत्ता पक्ष ने उनका एक–एक शब्द सुना है। आप गलत शह दे रहे हैं, गलत परंपरा डाल रहे हैं। माननीय मंत्री जी, और विजेन्द्र जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं अगर आप बीच में बोले। भई अब बैठ जाइए प्लीज बैठिए। बैठिए मैं करता हूं। बैठिए–बैठिए, बैठिए अमानतुल्ला जी। बैठिए प्लीज, प्लीज। मेरी प्रार्थना है विजेन्द्र जी रिक्वेस्ट है हंबल रिक्वेस्ट मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए कोई बीच में नहीं।

.....व्यवधान....

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: सोमनाथ जी बोलने दीजिए।

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलौत): इनको बड़ा दर्द है इनको कि भई हमारी तमाम शिकायतों के बावजूद हर कदम पर जितनी इनमें ताकत है वो सारी यूज करने के बावजूद कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली सरकार बसें कैसे लेके आ रही है। डीटीसी में बसें 12 साल से नहीं आई और मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं it is a matter of record, matter of fact कि जब भी बसों की खरीद की बात होती है विजेन्द्र गुप्ता जी ने हर बार कंप्लेंट की हैं। उन कंप्लेंटों की...

.....व्यवधान....

माननीय परिवहन मंत्री: आप कहीं से पता कर लीजिए।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: तो क्यों, बोलेंगे वो, वो बोलेंगे न।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: नहीं क्यो, बोलेंगे नहीं क्या, बोलने नहीं दोगे क्या उनको? वो जो फैक्ट है वो जो बोल रहे हैं। वो कंप्लेंटें जहां जहां मर्जी आए कर देते हैं उस वक्त।

माननीय परिवहन मंत्री: माननीय डिप्टी सीएम साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा कि पिछले लगभग 1 साल के अंदर हम 1600 नई बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा चुके हैं और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जब तक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार है हम बसें खरीदते रहेंगे चाहे ये कुछ भी कर लें। अगर इनके पास कोई और भी ताकत है उसको भी ले आइए हम डरने वाले नहीं हैं। बसें आएंगी, आ चुकी हैं और भी बसें आएंगी सीएनजी की नई बसें भी आएंगी और इलेक्ट्रिक बसें भी आएंगी आपने जो करना है कर लो क्योंकि हमारा नारा था कि हम राजनीति करने नहीं राजनीति को बदलने आए हैं और दूसरी बात काला अक्षर भैंस

बराबर ये है इनकी आदत और मुझे तो वो याद आ रही है कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलदार हैं। इनको किसी ने समझा दिया कि इसमें घोटाला हो गया ये भी अपना पूरी तैयारी करके और ये नहीं पता कि इसमें लिखा क्या है। वही बात है पढ़ना तो है नहीं कुछ, बस घोटाला हो गया। भई कैसे हो गया, ये तो बताओगे, बस घोटाला हो गया।

....व्यवधान...

माननीय परिवहन मंत्रीः मैं बताऊंगा सारी चीजें एक–एक चीज विस्तार से बताऊंगा।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बहनजी उनको बोलने दीजिए मंत्री जी बहुत कुछ बोलने वाले हैं। वो सारी चीजों पर बताने वाले हैं।

माननीय परिवहन मंत्रीः लेकिन अध्यक्ष जी, इस सदन में जो कि हम कहते हैं कि मंदिर है, ये बातें इनको शोभा नहीं देती और हम जिगरा रखते हैं कि इनके जितने भी आरोप हैं बिलकुल हंस के सुनेंगे और हर चीज का जवाब देंगे क्योंकि हमारा एक ही है कि हमें पब्लिक की सेवा करनी है। पब्लिक का जो काम है वो हमें करते रहना है और सीएम साहब ने जो 10 जो प्रिंसिपल्स बताए थे रामराज्य के उन्हीं पर हमें आगे चलना है । लेकिन इस सदन में जहां बड़ी गंभीर चर्चा होनी चाहिए वहां इतने मतलब जो कहते हैं कि टुच्ची राजनीति करने के लिए बैठे हैं। सिर्फ बोलना है कुछ, क्या बोलना है ये नहीं पता। क्या आरोप लगा रहे हैं ये नहीं पता। किस पर आरोप लगा रहे हैं ये नहीं पता। अब अध्यक्ष जी कुछ जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं क्योंकि जब इन्होंने इतनी बड़ी बात उठाई है तो फिर उसको स्पष्ट करना भी जरूरी है। 11 जुलाई, 2019 में केबिनेट डिसीजन हुआ कि डीटीसी हजार बसें खरीदे और उस केबिनेट डिसीजन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन यह भी था कि जो ये बसें खरीदी जाएंगी इसके साथ–साथ हरेक बस की एक Comprehensive Annual Maintenance Contract भी होगा जिसको ये बार–बार कह रहे हैं एएमसी,

एएमसी। वारंटी भी बताऊंगा क्या होती है ताकि ये कम से कम इनको समझ में आ जाए कि वारंटी और Annual Maintenance Contract में डिफरेंस क्या है और ये केबिनेट डिसीजन है अध्यक्ष जी इसका जो पैरा 3 है ये कहता है DTC will invite bids for अंग्रेजी में है अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः आप पढ़ दीजिए।

माननीय परिवहन मंत्रीः तो।

माननीय अध्यक्षः आज कैलाश जी बड़ा आनंद ले रहे हैं परफेक्ट होकर।

माननीय परिवहन मंत्रीः क्योंकि आनंद का तो मौका इन्होंने दिया, आनंद का मौका इन्होंने दिया और अंत में ये भी बताऊंगा मैं, ये हमने कहीं बताया नहीं है कि कैसे हमने 225 करोड़ रुपये बचाए इसमें ये भी बताऊंगा मैं इनको।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी इनको बोलने दो, प्लीज। बहुत गंभीर मुद्दा है और जितनी वो तैयारी करके आए हैं न उनको बोलने दीजिए, प्लीज।

माननीय परिवहन मंत्रीः तैयारी तो करनी थी, हमें पता था ये होगा, तो पहले दिन से ही तैयारी कर रहे थे हम। तो पैरा 3 कहता है अध्यक्ष जी DTC will invite bids for Comprehensive Annual Maintenance Contract of these Buses as per the provisions of GFR and in compliance of CVC guidelines through open competitive bids मतलब की इसका टेंडर किया जाएगा तो ये केबिनेट का डिसीजन है और इसी केबिनेट में एक और जो डिसीजन था एएमसी के रिगार्डिंग ही DTC will, para five जो है, DTC will synchronize the tender of procurement of buses with the tender of Comprehensive Annual Maintenance Contract in such a manner that at no point of time, the newly procured buses remain unattended, non-operational for want of maintenance. Further, the AMC to be done should be taken into account the various warranty/ guarantees available on the purchase buses for ensuring economy in the AMC contract.

अब इसका ये बेसिकली अध्यक्ष जी पैरा 5 जो है ये कहना चाह रहा है कि भई 2 अलग टेंडर होंगे एक बस खरीदने का और एक दूसरा जो है Comprehensive Annual Maintenance Contract और दोनों जो टेंडर हैं वो उस तालमेल से फ्लोट किए जाएंगे कि जब बसें आ जाएं तो एक भी दिन ऐसा न हो कि कोई भी बस वो बिना annual maintenance contract के रहे। इसका इतिहास अध्यक्ष जी ये है कि डीटीसी में लगातार आपने भी सुना होगा और सभी जो माननीय मेंबर्स हैं उन्होंने सुना होगा कि डीटीसी में लगातार टेंडर फेल करते आ रहे थे। एक combined tender करते थे तो उसमें एएमसी के इश्यूज हुआ करते थे अलग। दूसरी हमारी सबसे बड़ी दिक्कत अध्यक्ष जी ये है कि जो बसें देने वाली कंपनीज हैं वो 2 या 3 ही हैं। अब अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 3 से जो 12 मीटर की लो–फ्लोर बसें दे रही है वो शायद 2 ही रह गई हैं तो टेंडर फेल किया करते थे बार–बार शायद ये चौथी बार जो है टेंडर किया था और जो कामयाब हुआ। तो 11 जुलाई, 2019 को केबिनेट डिसीजन हुआ तो ये हमारे ही ऐसा नहीं की कोई भी कोई मेंबर है या मिनिस्टर है या कोई चेयरमैन है उसने सोचा कि मैं इसके 2 कर दूं 1 कर दूं बकायदा केबिनेट का डिसीजन था और उस केबिनेट डिसीजन के तहत ही हमने सारी कार्यवाही की है। 20 मार्च, 2020 में हमने टेंडर फ्लोट किया हजार बसों का। 19 अगस्त, 2020 में हमने annual maintenance contract का टेंडर फ्लोट किया। 6 अक्टूबर, 2020 में हमने जो बसों की जो टेंडर थी उसकी price bids खोली और एल–1 हमने सिलेक्ट किया। 14, अक्टूबर, 2020 में हमने जो एएमसी की जो बिड्स हैं वो खोलीं। अब जो दोनों, एक खरीदने का टेंडर है और दूसरा ए.एम.सी का है, ये भी हमारे टेंडर का ही पार्ट है ताकि कोई भी बस जो है बिना मेंटेनेंस के न रहे इसीलिए ये भी टेंडर का पार्ट है कि जो भी बसें देने का टेंडर में पार्टिसिपेट करेगा उसको ए.एम.सी के टेंडर में भी पार्टिसिपेट करना है और ये मैं टेंडर डॉक्यूमेंट से ही पढ़ रहा हूं, "the vehicle manufacture-cum-contractor directly and also through their authorized network मतलब कि जो कम्पनी है खुद भी आ सकती है और अगर अपना कोई एजेंट के थ्रू अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो भी आ सकती हैं shall be required to submit comprehensive AMC offer for maintenance of buses upto 7.5 Lakh KMs तो ये भी ओपन टेंडर में लिखा है

कि जिसको, जो बस देने वाले टेंडर में पार्टिसिपेट करेगा उसको ए.एम.सी वाले में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा।

अब ये जो इन्होंने 2–3 चीजें कही। पहला इन्होंने कहा कि वारंटी, ये बार–बार ये कह रहे हैं जी वारंटी, 3 साल की वारंटी है, 3 साल की वारंटी है, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जब आप गाड़ी खरीदते है तो उसमें सारी चीजें फ्री होती हैं। तो मैं इनसे ये भी पूछना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो वो गाड़ी में सफाई करनी होती है, क्या वो भी कम्पनी वाले करके जाते हैं? या अगर उसका मोबिल ऑयल चेंज होता है तो वो भी कम्पनी फ्री देती है? अगर बसों में फिल्टर चेंज होना है तो वो भी क्या कम्पनी वाले वारंटी में ही देते है 3 साल की? ऐसा नहीं है। अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि पहले डीटीसी की जितनी भी बसें थी... अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि पहले डीटीसी सारी बसें खुद मेंटेन किया करती थी, बड़ी–बड़ी वर्कशॉप हुआ करती थी, सारे स्पेयर पार्टस भी, वो डीटीसी के स्टोर हुआ करते थे, उनके अपने टेक्निशियन हुआ करते थे, सुपरवाइजर हुआ करते थे, फोरमैन हुआ करते थे। लेकिन जब से लो–फ्लोर बसें हमारी आनी स्टार्ट हुई तब से, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी थी तो हमारे उस टाइम जो standard floor buses थी तो उसके साथ–साथ, 2006 से चल रहा है ये, तो जो भी हमारी लो–फ्लोर बसिस हैं इसका जो मेंटेनेंस है वो हमारे डीटीसी के जो स्टाफ हैं वो खुद नहीं करते हैं, सारा आउटसोर्स किया जाता है। और लगभग 71 आइटम्स ऐसे हैं कि जो कि वारंटी में कवर नहीं होते। अगर गाड़ी में आपकी बैटरी है, बैटरी का पानी चेक करना है तो वो जो कम्पनी है वो चेक करने नहीं आयेगा। आपकी बस है, सड़क पे जा रही है अगर वो रूक गई तो वो जो कम्पनी है वो कम्पनी वाला वारंटी में वो उस बस को वहां से उठाके लेके नहीं जायेगा tow करके। तो तमाम ऐसी सारी चीजें हैं और मैं ये भी सदन के बीच रखना चाहूंगा कि आज सिर्फ सीएनजी को छोड़कर, दिल्ली सरकार या डीटीसी कुछ नहीं देती है। हरेक चीज, चाहे वो मेंटेनेंस है, चाहे उसको वर्कशॉप है, चाहे सफाई है, चाहे उसकी बैटरी चेक करनी है, हर चीज जो है वो, ए.एम.सी जो हम बोल रहे हैं, annual maintenance contract वो जो कम्पनी है वो उसको अलग से देखती है। तो मतलब कि डे वन से अगर हमारी बसें सड़क

पर बढ़िया तरीके से चलनी हैं, हमारे हर डिपो से अगर हमें ये, ये पक्का करना है कि 100 में से कम से कम 92 परसेंट बसिस हमारी डिपो के बाहर निकले और जो पेसेंजर हैं उनको अवेलेबल हों, तो वो सारी चीजें जो हैं वो ए.एम.सी में ही कवर होती हैं। जो वारंटी पीरियड, वारंटी पीरियड ये चिल्ला रहे हैं बार—बार 3 दिन से, ये सारी चीजें वारंटी में कवर नहीं होती हैं। वारंटी में सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, कोई manufacturing defect है, अगर बस रूक गई, रूकने के बाद जब तक उसको इंजीनियर एग्जामिन नहीं करेगा जब तक।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः आप बोलते रहिए। आप बोलते रहिए। उनकी आदत है।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः भई ओम प्रकाश जी।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी, को, अगर आपको नहीं लगता है तो आप लिखकर भेज दीजियेगा।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः हां, कोई बात नहीं।

माननीय परिवहन मंत्रीः तो ये बार—बार जो कह रहे हैं कि जी वारंटी पीरियड में, वारंटी पीरियड में, ये सारी चीजें वारंटी पीरियड में नहीं आती हैं। उसके बाद अब जो मैं कह रहा था कि हमने 225 करोड़ रुपये कैसे बचाये? ए.एम.सी का एल—1 जो रेट आया अध्यक्ष जी, वो आया 48 रुपये 50 पैसे। उसके बाद हमने डीटीसी के अधिकारियों को, दूसरा जो रेट आया, वो आया 49 रूप्ये 29 पैसे। हमने बार—बार अधिकारियों को कहा कि भई इसमें देखिये कि अगर, हालांकि जब ओपन टेंडर है और वो रेट आ रहे हैं तो ऐसा कोई mandatory या compulsion नहीं है कि उनको फिर दुबारा पूछा जाए कि भई क्या आप रेट कम करोगे। लेकिन फिर भी हमें लगा

कि कहीं न कहीं जो भी पैसा बचेगा वो पब्लिक का पैसा है, उसको बड़े ध्यान से खर्च करना है। तो अध्यक्ष जी, ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने 48 रुपये 50 पैसे से negotiate करके दोबारा वो हम 45 रुपये 50 पैसे पर लेकर आये, इसका मतलब 3 रुपये हमने कम किया। एक बस अगर अपने पूरे 12 साल में साढ़े 7 लाख किलोमीटर अगर चलती है, तो हजार बसों का अगर आप लगाओगे तो मतलब ये टोटल मिलाकर 225 करोड़ रुपये अध्यक्ष जी ये टोटल बनता है। तो जहां ये बार–बार कह रहे हैं कि जी हमने घोटाला कर दिया, घोटाला कर दिया, सारी चीजें जो हैं वो ओपन टेंडर के थ्रू हुई हैं, सारी जो चीजें हुई हैं और जो टेंडर हुआ है ए.एम.सी का उसमें साफ–साफ लिखा हुआ है कि आप जो भी rate quote करेंगे, जो चीजें वारंटी पीरियड में इन्क्लूडिड हैं वो, उसको हटाके आप अपना rate quote करेंगे। तो किसने इनको समझाया ये, ये यही बता सकते हैं क्योंकि इनके सलाहकार जो हैं।

....व्यवधान....

माननीय परिवहन मंत्री: दूसरी चीज इन्होंने कही कि डीटीसी की बोर्ड मीटिंग में एक बार ऐसा हुआ, 25 परसेंट,

....व्यवधान....

माननीय परिवहन मंत्री: 25 परसेंट अध्यक्ष जी जो।

....व्यवधान....

माननीय परिवहन मंत्री: ये भी टेंडर का पार्ट है और कैबिनेट से पूरा अप्रूवड है।

....व्यवधान....

माननीय परिवहन मंत्री: कि 25 परसेंट हम उसको इन्क्रीज कर सकते हैं।

....व्यवधान....

माननीय परिवहन मंत्रीः और अध्यक्ष जी, एक चीज और मैं कह रहा हूं कि जो आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने किसानों को बेच दिया, जिन्होंने जवानों को बेच दिया, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। पूरे भारत, पूरे देश के किसानों को जिन्होंने बेच खाया, जो इतने महीनों से जहां बॉर्डर पर बैठे हैं और वो किस गरूर में हैं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं।

....व्यवधान....

माननीय परिवहन मंत्रीः तो अध्यक्ष जी, मैं इन्हीं को धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और

....व्यवधान....

माननीय परिवहन मंत्रीः जो ये बार–बार ये कह रहे हैं और मैंने ये प्रूव किया है कि 225 करोड़ रुपये जो है वो दिल्ली सरकार का हमने कैसे बचाया। बहुत–बहुत धन्यवाद।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः सदन को लंच के लिए स्थगित किया जाता है। 2.00 बजे हम पुनः मिलेंगे।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन पुनः अपराह्न 2.03 बजे समवेत हुआ।

मननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आदरणीय अध्यक्ष जी, नियम 114 के तहत मैंने एक प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया।

माननीय अध्यक्षः कब?

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः जब से...

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः 1993 के बाद ऐसे अनेक प्रस्ताव हाउस में आए हैं और उन प्रस्तावों के उपर सदन ने अपनी सहमति भी व्यक्त की है। देश के प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के बारे में।

माननीय अध्यक्षः नहीं वो आपने 280 में दिया था, उसमें वो हो गया। अभी बजट में चर्चा में आयेगा तब बोल लेना। नहीं प्लीज। नहीं नहीं कोई, बजट में देखिए ऐसे तो आपने।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं है। हां मैंने पढ़ लिया है आपका पूरा। पूरा पढ़ लिया है मैंने प्लीज आप बैठिए। वैज्ञानिकों का नहीं वो पॉलिटिकल ज्यादा है। बिधूड़ी जी। वो पॉलिटिकल ज्यादा है वैज्ञानिकों का कम है। बैठिए, बैठिए प्लीज। वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी। आप, बजट पर चर्चा में आयेगा न उसमें। नहीं, अब श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उप–मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2021 को प्रस्तुत वार्षिक बजट पर चर्चा होगी। सदस्यों से अनुरोध है कि अपने को बजट भाषण की विषय वस्तु तक ही कृपया सीमित रखें तथा अनावश्यक विस्तार न करें। भाषा की मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। हमें सदन के समय के सदुपयोग का पूरा ध्यान रखना है ताकि निर्धारित समय में अधिक से अधिक सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल सके। मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना भी है कि सदस्य थोड़ा कम बोलें, अपनी बात को संक्षेप में रखें ताकि सभी सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके। आज महा शिवरात्रि भी है 4 बजे सदस्यों की ओर से आग्रह हुआ है कि 4 बजे तक आज कार्यवाही पूर्ण करें बाकी सदस्यों को कल बोलने का मौका मिलेगा। अब चर्चा में सदस्य भाग लेंगे श्री कुलदीप कुमार जी।

श्री कुलदीप कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दिल्ली के उप–मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया द्वारा बजट 2021 पर देशभक्ति बजट दिल्ली वालों का बजट, दिल्ली के दिल के बजट के उपर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जैसा कि पूरा

देश देख रहा है कि किस प्रकार से हम सब लोग अभी कोरोना महामारी से निकल कर आगे की ओर बढ़े हैं और उसमें जिस महामारी से बढ़ कर हम आगे की ओर बढ़े हैं उस महामारी से लड़ने में दिल्ली की सरकार का, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविन्द केजरीवाल जी का जो कार्यशैली रही है क्योंकि जब दिल्ली में या देश में कोरोना महामारी का असर था, प्रकोप था, आसपास के राज्यों को अगर आप उठाकर देखेंगे तो अध्यक्ष जी, एक ओर जो दिल्ली की सरकार लगातार टैस्ट की बढ़ोतरी कर बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाकर, एक एक व्यक्ति का टेस्ट करने की तैयारी कर रही थी, उनके टैस्ट करवा रही थी, जो उनकी किट थी उनका इंतजाम कर रही थी और दूसरी ओर अलग—अलग राज्यों की सरकारें चाहे बगल का उत्तर प्रदेश हो, वो सरकारें ये सोच रही थीं कि किस प्रकार से गलत तरह का डेटा प्रस्तुत किया जाए और किस प्रकार से जनता को ये बताया जाए कि इन अगल बगल के राज्यों में कोरोना महामारी नहीं है और दिल्ली के अंदर है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पूरी सूझबूझ के साथ, पूरे संकल्प के साथ जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने इस कोरोना महामारी से देश को और दिल्ली के लोगों को जिस प्रकार से बचाया और जिस प्रकार से आज हम इस कोरोना महामारी से निकल कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं अगर कल की बात करूं तो दिल्ली के अंदर 71153 टेस्ट हुए हैं जिनमें से मात्र 370 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं मानता हूं कि पूरे देश के अंदर ये सबसे बड़ा इतिहास होगा कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी संख्या में माइक्रो लेवल पर ये टैस्ट किए गए हैं और अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की जो टेस्ट की व्यवस्था थी आप अगर उसको देखें मेरा क्षेत्र कोंडली आता है जहां से मैं आता हूं बगल के घोंडा तक के लोग उत्तर प्रदेश का सटा हुआ जगह है घोंडा, बहुत बड़ी कालोनी है उसके अंदर एक भी जगह, ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर आकर वो अपना टैस्ट करा सकें। लेकिन दिल्ली की सरकार के द्वारा जो हमारे छोटे छोटे लेवल पर जो वहां डिस्पेंसरियां बनी हुई थी, हमारे हॉस्पिटल्स बने हुए थे वहां पर आकर उन लोगों ने टैस्ट कराया और मैं दोबारा धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि दिल्ली के लोगों के अंदर कोरोना महामारी से ज्यादा उसका भय था। उस भय को निकालने के लिए, उस डर को निकालने के लिए जो दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली

के मुख्यमंत्री जी ने आगे कदम बढ़ाए, मैं मानता हूं सराहनीय कार्य है और आप देखें कि चाहे होम आइसोलेशन की पॉलिसी हो, चाहे प्लाज्मा थेरेपी हो, दिल्ली ने देश के अंदर नाम कमाया है और दिल्ली ने देश का नाम पूरे विश्व के अंदर किया है, ये ऐसी पॉलिसी थी। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि एक फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान, पहले की सरकारें सपना दिखाती थी कि आपको रोटी कपड़ा और मकान देंगे लेकिन वो सुविधाएं भी पूरी नहीं हो पाती थी लेकिन दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने लोगों को ये करके दिखाया, इन 6 सालों में बताया कि रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान की गारंटी अगर कोई सरकार लेती है तो वो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी हैं। आज स्वास्थ्य और शिक्षा की जो गारंटी दिल्ली की सरकार ने लेने का काम किया है अध्यक्ष जी, सब लोगों को जिस प्रकार से आज स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिल्ली के अंदर मिल रहा है आप देखेंगे चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, एक वो मोहल्ला क्लिनिक जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 6 साल पहले ये बताया था कि दिल्ली के एक मोहल्ले के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक होगा और वहां पर एक एमबीबीएस डाक्टर बैठेगा, वो आपके टेस्ट करेगा तो हमारे भाजपा के साथी भी यहां बैठे हुए हैं, ये बड़ा मजाक बनाते थे। ये कहते थे कि ऐसा हो नहीं सकता, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो चुनावी जुमले हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, आज हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज दिल्ली की झुग्गी–झोपड़ी बस्ती के अंदर रहने वाला व्यक्ति भी अपना इलाज जा कर बगल के मोहल्ला क्लिनिक से कराता है और वहां से दवाई लेकर आता है और स्वस्थ हो जाता है और उसके साथ साथ एक मॉडल और प्रस्तुत हुआ आज बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहने वाले, ग्रेटर कैलाश एरिये में रहने वाले लोग भी मोहल्ला क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आज उनको वो फैसिलिटिज, वो सुविधाएं उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर मिलने का काम हो रहा है। तो दिल्ली के गरीब लोगों के लिए जिस प्रकार का वरदान ये साबित हुआ मोहल्ला क्लिनिक, मैं कह सकता हूं कि पहली कोई सरकार है देश के अंदर जिसने गरीब झुग्गी–झोपड़ी के रहने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सोचा। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि कल यहां पर बहुत सारे साथी, हमारे भाजपा के साथी भी हमारे कह रहे थे कि

जी डाक्टरों ने ये नहीं किया, डाक्टरों ने उसका इलाज नहीं किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब भाजपा के लोग और भाजपा के नेता और भाजपा के सांसद लॉक डाउन के अंदर ये बैठ कर सोच रहे थे कि लूडो कैसे खेली जाए, रामायण कैसे देखी जाए, उस समय पर वो डाक्टर फ्रंट लाइन में खड़े हो कर, वो नर्सिस, वो सफाई कर्मचारी और ये जो विधान सभा के अंदर बैठे हुए आम आदमी पार्टी के विधायक या दिल्ली के मुख्यमंत्री ये चिंता कर रहे थे कि लोगों की टेस्टिंग कैसे बढ़ाई जाए, लोगों के लिए सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराई जाएं, हॉस्पिटल में बेड कैसे बढ़ाए जाएं, हॉस्पिटल के अंदर उनकी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे ठीक हो जाएं। तो अध्यक्ष महोदय, कहने में और करने में बड़ा फर्क है। हमारी सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने ये करके दिखाया है कि हैल्थमॉडल क्या होता है। मैं दिल्ली के हैल्थमॉडल के बारे में छोटी सी 2 मिनट में एक बात बताना चाहता हूं। आज दिल्ली का गरीब आदमी मोहल्ला क्लिनिक में जाता है, जाकर उसको बुखार है तो वो दवाई ले लेता है, अगर उसको कोई बीमारी है तो वो टेस्ट करा लेता है, कई तरह के, चाहे यूरिन टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, शुगर टेस्ट हो वहां पर टेस्ट होते हैं। अगर उसको वहां से कोई दिक्कत होती है तो वो मोहल्ला क्लिनिक उसको बगल के पोलिक्लिनिक में ट्रांसफर कर देता है, वो वहां जा के अपना इलाज कराता है, अगर उसको वहां कोई दिक्कत होती है तो एक बड़े अस्पताल के अंदर उसको ट्रांसफर कर देता है जहां पर जाकर उसका इलाज होता है। अगर उस बड़े अस्पताल के अंदर अध्यक्ष जी, अगर उस बड़े अस्पताल के अंदर भी कोई बेड खाली नहीं है या उसका टेस्ट नहीं हो पाएगा तो वहां पर बैठा हुआ डाक्टर उसके लिए लिख देता है कि आप जाकर अपना टेस्ट बाहर से करा लीजिए और उसक पेमेंट सरकार करेगी। ये दिल्ली का हैल्थमॉडल है कि गरीब आदमी को, गरीब तबके के व्यक्ति को भी अगर बड़े से बड़ा आपरेशन कराना है, एमआरआई कराना है, सीटी स्कैन कराना है तो वो बिल्कुल मुफ्त में जाकर करा सकता है और किसी भी प्राइवेट लैब से करा सकता है। मैं कह सकता हूं कि दिल्ली का जो हैल्थमॉडल है वो देश के अंदर पहला ऐसा हैल्थमॉडल होगा जहां कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी, सरकार अस्पताल भी ये लिखकर देते होंगे कि आप बाहर से जा कर टेस्ट करा लो और वो प्राइवेट लैब उसका टेस्ट करती होगी और पेमेंट सरकार से लेती होगी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली

सरकार की एक और पॉलिसी हैल्थ के अंदर बड़ी कारगर साबित हुई है 'फरिश्ते' योजना। इस 'फरिश्ते' योजना के अंतर्गत मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर लगभग 30 लोगों का इलाज मैक्स जैसे बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर करा चुका हूं अध्यक्ष महोदय। आज दिल्ली के अंदर चाहे बाहर के राज्य का हो, चाहे किसी उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, लेकिन आज अगर वो दिल्ली के अंदर घुसता है तो ये सुरक्षा अपने आपको महसूस करता है कि अगर दिल्ली के अंदर मेरे साथ भगवान न करे कोई हादसा रोड के उपर चलते हुए हो जाए तो दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो चलाई गयी 'फरिश्ते' योजना है उसके तहत उसका इलाज हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती थी गरीब आदमी के लिए कि अगर कोई दुघर्टना रोड पर चलते हुए हो जाए, उस आदमी को चोट लगती थी, उसका पूरा का पूरा परिवार उस चोट से कराहता था और पूरा परिवार अस्पतालों के बिल पेमेंट करके उस बिल से कराहता था। अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली के लोगों को ये सुविधा देने का काम ये फरिश्ते योजना देने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने किया है। इस हैल्थमॉडल के बारे में किसने सोचा होगा? किसने परिकल्पना की होगी? बड़े बड़े लोग आज से पहले बैठकर सोचते होंगे लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने का कार्य दिल्ली सरकार ने करने का काम किया तो आज गरीब आदमी की, झुग्गी–झोपड़ी वाले व्यक्ति की दिल्ली के एक एक व्यक्ति की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो दिल्ली की सरकार ने किया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने किया है। अध्यक्ष जी, सरकार की एक और बहुत बड़ी उपलब्धि जिसको कह सकते हैं कि सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान इस बजट के अंदर किया है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। अध्यक्ष जी, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्यूंकि जिस एरिये से मैं आता हूं, जिस इलाके से मैं आता हूं वहां पर बहुत गरीब तबके के लोग भी रहते हैं झुग्गी–झोपड़ी का एरिया भी है और ये बात सच है माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में ये कहा था कि वो महिलाएं अपनी बीमारी के बारे में किसी को बता भी नहीं पाती हैं, वो इस बीमारी के साथ जीना सीख लेती हैं और होते होते हो सकता है कि उनकी मृत्यु भी कल को हो जाए। लेकिन अगर दिल्ली की सरकार जो महिला मोहल्ला क्लिनिक खोलने जा रही है मैं कह सकता हूं ये उन महिलाओं के लिए, उन गरीब

महिलाओं के लिए जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती के अंदर रहती हैं जो दलित पिछड़े समाज से आती हैं उनके लिए वरदान साबित होगा, ये मोहल्ला क्लीनिक का जो कॉन्सैप्ट है ये वरदान साबित होगा। अध्यक्ष जी, आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली की सरकार ने जो भी हैल्थके अंदर किया है, जो हैल्थ मॉडल में करने का काम किया है, मैं कह सकता हूं इस कोविड महामारी के अंदर, पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा काम करने का काम, पूरे infrastructure को डेवलप करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने किया है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसका बहुत—बहुत धन्यवाद, बहुत—बहुत आभार।

माननीय अध्यक्षः अखिलेश पति त्रिपाठी, वीरेन्द्र कुमार कादियान जी।

श्री वीरेंद्र सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय माननीय उप—मुख्यमंत्री जी ने जो देशभक्ति बजट पेश किया उस देशभक्ति बजट की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है और हमें भी बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के पश्चात राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और रामराज्य के सिद्धांतों पर चलकर सभी को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भी रोजगार, महामारी से निजात दिलाना इन सबको बखूबी निभाते हुए बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना, इन सारी मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने के पश्चात अब इस वित्तिय वर्ष में जो देशभक्ति बजट पेश किया गया इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति कैसे उत्पन्न हो ये किसी दबाव में या किसी लोभ—लालच से नहीं होती, ये तभी हो पाती है जब लोगों का विश्वास चुनी हुई सरकारों पर, हमारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों पर आपस में विश्वास बनता है तभी राष्ट्रभक्ति की जागृति होती है और आम जनता ये महसूस करती है कि हमारा ख्याल रखने वाला हमने चुनकर भेज रखा है, वो हमारा ख्याल रखेंगे। ये हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारे लोग हैं, हमें भी देश के प्रति सोचना चाहिए और हमें भी राष्ट्रनिर्माण में अहम भूमिका निभानी चाहिए जिससे भ्रष्टाचार उन्नमूलन और दिल से काम करने की प्रेरणा मिलती है वो कार्य दिल्ली की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी ने लोगों के बीच ये विश्वास पैदा करके ये सुविधाएं प्रदान करके पैदा कर दिया है और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना

उत्पन्न हो रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा की रामराज्य की स्थापना, रामराज्य की कल्पना, रामराज्य के सिद्धांत और आम जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है जो कि बखूबी हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी ने जनता में विश्वास भी पैदा करके किया और निभाया भी है। मैं दिल्ली कैंट विधान सभा क्षेत्र से चुनकर इस दिल्ली विधान सभा में आता हूं जो कि सैनिकों की भूमि है वहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी, उनके परिवार और उनके लोग रहते है। माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उन सबने देशभक्ति बजट की काफी सराहना की है और एक बात का और मैं संज्ञान दिलाना चाहता हूं कि चुनाव से पहले दिल्ली एक्स सर्विसमैन असोसिएशन के बैनर तले काफी एक्स सर्विसमैन एसोसिएशनों ने कॉस्टीट्यूशन क्लब पर माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया था और उसमें एक मांग रखी थी कि दिल्ली में भी सैनिक स्कूल होना चाहिए और दिल्ली में भी आर्मड फोर्सिसिज ट्रेनिंग इंस्टीटयूट की स्थापना होनी चाहिए। मैं इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में इसका प्रावधान रखा और इस चीज को मंजूरी दी जिससे जितने भी एक्स सर्विसमैन है, सर्विसमैन है उन्होंने इसका आभार जताया है जिसे अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए भी और इसके सम्मान के लिए जगह–जगह पर इसकी स्थापना करने का, इसको लहराने का जो बजट में प्रावधान रखा है इसकी भी काफी सराहना हो रही है और काफी चर्चा हो रही है। माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में योग और योगा से संबंधित उनके प्रशिक्षकों के लिए भी प्रावधान रखा है जिससे कि हमारे यहां के जो बाशिंदे है वो योग कर सकेंगे जिससे उनका तन और मन स्वस्थ रहेगा और अच्छी स्वास्थ्य के लोग ही अच्छी सोच रखेंगे जिससे समाज में राष्ट्रभक्ति उत्पन्न होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक खेल यूनिवर्सिटी की भी शुरूआत की है जो की घेवरा गांव में बननी है, इससे भी लोगों में काफी उत्सुकता है और हमारे यहां के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के आसपास के प्रदेशों से आने वाले बच्चे वहां पर खेल का प्रशिक्षण ले सकेंगे और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देशभक्ति के लिए जो भी प्रावधान होने चाहिए थे वो इस बजट में रखे हैं और लोगों में काफी खुशी है। मैं एक बात का ओर संज्ञान दिलाना चाहता

हूं कि श्री अरविन्द केजरीवाल जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने किसानों की भी सुध ली है और किसानों के साथ खड़े रहे है। दिल्ली में जब ओलावृष्टि हुई थी तो 50 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर देकर किसानों का भी मानसम्मान रखा था जो कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी रकम किसी भी राज्य में एक क्षतिपूर्ति के लिए नहीं दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने एक करोड़ रुपए का प्रावधान कर रखा है। कोई भी सैनिक, अर्धसैनिक, पुलिस का जवान अगर अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते समय शहीद हो जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनके घर पर जाकर ये सम्मान राशि देकर आते है जो कि एक सम्मानीय कदम है और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्स सर्विसमैनों के लिए बहुत से सराहनीय कार्य किए है जैसे कि उन्होंने ट्रॉस्पोर्ट के इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट में हजारों एक्स–सर्विसमैन को भर्ती किया है। स्कूलों में मिनिस्टेरियल और स्टेट मैनेजर की नौकरी के अवसर दिए। डीटीसी बसों में मार्शल तैनात किए और हमारे बच्चों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी और सिविल डिफेंस में उनको रोजगार देकर भी एक प्रकार से अनुशासन में रहकर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया जो कि राष्ट्रभक्ति का एक संदेश है। मैं एक बार ओर कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि आज देश का किसान दिल्ली की सीमाओं के ऊपर तीन काले कानूनों का विरोध कर रहा है और एमएसपी की गारंटी चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री पहले ऐसे मुख्यमंत्री है पूरे हिन्दुस्तान में जो शुरू से ही किसानों के साथ खड़े हैं और उनकी मांगों को जायज ठहरा रहे है। हम सभी विधायकों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश और आदेश दिया कि किसानों के प्रति, किसानों की सहायता के लिए इस आंदोलन में जो भी बन पाए वो करे। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी ने जय जवान–जय किसान के नारे को सुदृढ़ भी किया है और समाज के अंदर ये दिखा दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जवान के साथ भी है और किसान के साथ भी है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो राष्ट्रभक्ति बजट पेश किया है, ये एक सराहनीय कदम है और मैं आभार प्रकट करता हूं दिल्ली की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप–मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को जिन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया जिससे हमारा मान–सम्मान भी बढ़ा है और लोगों का हमारे प्रति विश्वास भी बढ़ा है और राष्ट्रभक्ति ही ऐसी भक्ति है जो हममे भ्रष्टाचार मुक्ति और अपने दिल और अनुशासन से कार्य करने की प्रेरणा देती है।

आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद कादियान जी, अभय वर्मा जी।

श्री अभय वर्माः आदरणीय अध्यक्ष जी बजट पर चर्चा के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं और माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने देशभक्ति बजट 9 तारीख को इस सदन में प्रस्तुत किया था। एक संयोग समझे या मैं भाजपा का मैंबर हूं इसलिए उस दिन सुबह ही मैंने बिजनेस टाइम्स में एक खबर पढ़ी थी और उस खबर में भारत का अमृत महोत्सव में जो–जो चीजें मैं पढ़ के आया था वो माननीय उप–मुख्यमंत्री जी के पहले दो पेजिज में में बयान था, तो शाम में फिर जाकर मैंने उस खबर के डिटेल में मैं गया तो मैंने देखा कि इस बजट के पहले दो पेज हैं वो दोनों पेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हुआ था 8 तारीख को उसी पर आधारित ये दोनों पेज था, शब्दों को थोड़ा बहुत तोड़–मरोड़ के पेश किया गया। मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कॉपी करना बुरी बात नहीं है, अच्छे कामों का कॉपी होना चाहिए। जैसे रामभक्त, रामराज्य की बात हुई हम इसकी बहुत प्रशंसा करते है लेकिन कम से कम ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमने मोदी जी का जो भाषण हुआ है उस भाषण से प्रभावित होकर हमने ये बजट को।

माननीय अध्यक्षः नहीं अभय जी, अभय जी एक सैकंड, क्या कहना चाह रहे हैं रातों रात में कागज टाइप कर लिए उन्होंने? नहीं मुझे समझ नहीं आता, अरे भई।

.....व्यवधान........

माननीय अध्यक्षः एक सैकंड मत बोलिए आप, नहीं दो मिनट रूकिए। नहीं क्यों नहीं काम है? मैं क्या आंखे कान बंद करके बैठा रहूं। नहीं खाली अम्पायर नहीं हूं मैं।

श्री अभय वर्माः मैं बता रहा हूँ बिल्कुल।

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए।

श्री अभय वर्माः अध्यक्ष जी रातोंरात टाइप हुए हैं मैंने तो सिर्फ पहले 2 पेज की

बात की है।

माननीय अध्यक्षः ठीक है चलिए, चलिए हो गया, आगे बढ़िए।

श्री अभय वर्माः उन दो पजे की बात कर रहा हूं, पूरे बजट की बात नहीं कर रहा हूॅं।

माननीय अध्यक्षः आगे बढ़िए चलिए।

श्री अभय वर्माः और ये दोनों पेज अलग से टाइप हुए हैं ये बजट के कॉपी में स्पष्ट दिख रहा है।

माननीय अध्यक्षः चलिए बोलिए आप, दिल्ली की जनता देख रही है आप जो बोल रहे हैं।

श्री अभय वर्माः हॉ दिल्ली की जनता देख रही है और यही तो मैं तारीफ कर रहा हूं कि आप कॉपी कीजिए, अच्छे कामों का कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है।

माननीय अध्यक्षः चलिए आगे चलिए।

श्री अभय वर्माः लेकिन कम से कम उसको एकनॉलेज कीजिए।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए। करिए–करिए।

श्री अभय वर्माः हॉ। ये तो मैने तथ्य रिकार्ड के साथ बताया है।

माननीय अध्यक्ष : करिए–करिए प्लीज।

श्री अभय वर्माः अध्यक्ष जी, कोविड पर अभी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। दिल्ली सरकार हमेशा अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने कोविड में दो खोज की हैं। एक आईशोलेशन नम्बर दो प्लाज्मा थेरेपी। मैने बिहार का रहने वाला हूं साहब और मैं छुट्टियों में अभी बिहार गया था तो वहां पर लोग मुझे से बार–बार पूछते थे कि प्लाज्मा थेरेपी और आईशोलेशन क्या है कि दिल्ली में संक्रमण रूक नहीं रहा। पूरे देश में संक्रमण रेट जो दिल्ली में है वो छठे नम्बर पर है। प्लाज्मा थेरेपी जिसे

बार—बार ये कहा जाता है कि बहुत फायदा हुआ। स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हैं। जब कम्पेयर करते हैं तो बिहार यूपी, असम, आन्ध्र प्रदेश, केरल इन सब राज्यों में डेथ रेट एक परसेंट से भी कम है। अगर दो सौ केस दिल्ली में हुए हैं अध्यक्ष जी तो साढ़े तीन लोग डेथ केस लेकिन अगर बिहार में दो सौ लोग अगर संक्रमित हुए हैं तो सिर्फ एक आदमी एवरेज बता रहा हूं एवरेज एक आदमी दो सौ लोगों में एक आदमी और दिल्ली में दो सौ लोगों में साढ़े तीन लोग ये एवरेज रहा है।

.....व्यवधान........

श्री अभय वर्मा: जब सच्चाई सामने आ रही है तो ऐसे ही होगा।

.....व्यवधान........

माननीय अध्यक्ष: भई उनको बोलने दें। वो कुछ तो बोलेंगे प्लीज। मैने टिप्पण ी कर तो दी जो भी बोले पता लग गया क्या बोलना है।

श्री अभय वर्मा: बार—बार आईशोलेशन और प्लाज्मा थेरेपी जो अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं

माननीय अध्यक्ष: आपको बोलने का अवसर मिलेगा नोट कर लीजिए। उस पर आप जवाब दीजिए ठोककर।

श्री अभय वर्मा: दिल्ली में डेथ रेट है 1.7 और पूरे भारत का जो डेथ रेट का एवरेज है वो 1.4 है। हम उन आठ राज्यों में है जो नेशनल डेथ रेट से भी अधिक हम डेथ रेट दिये हैं तो क्या फायदा हुआ प्लाज्मा थेरेपी और आईशोलेशन का। रिपोर्ट से अगर हम बात करें आंकडे से बात करें तो पूरा प्रोसिडिंग जो आईशोलेशन और प्लाज्मा थेरेपी का अपनाया गया वो फेल हुआ है अध्यक्ष जी। क्योंकि हमें लाभ मिला नहीं। इससे अच्छा तो यूपी में लाभ मिला है। इससे तो ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट बिहार का था कि वहां कम लोग संक्रमित हुए और डेथ का एवरेज भी कम रहा है।

.....व्यवधान........

माननीय अध्यक्ष : भई अब ऐसे नहीं प्लीज।

श्री अभय वर्मा: आप भी ना करते टेस्ट। जग हंसाई क्यों कराये। मॉडल तो क्या आप अपने को मत बचाइए ये कहकर। आप अपने आप को मत बचाइए।

माननीय अध्यक्ष : भई ये ऐसे नहीं चलेगा।

श्री अभय वर्मा: मैं तो नेशनल एवरेज की बात कर रहा हूं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा दिल्ली का एवरेज है डेथ रेट का। क्या हुआ प्लाज्मा थेरेपी का। उस पर भी चर्चा कर लेंगे अभी हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं।

.....व्यवधान........

माननीय अध्यक्ष : भई ये बार–बार। मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं आप नोट कर लीजिए वो जो बोल रहे हैं। उसके बाद अपने माननीय सदस्यों की बारी आएगी बोलने की उसमें जवाब दीजिए। प्रमिला जी प्लीज। ऐसे सदन का समय चर्चा ही पूरी नहीं हो पाएगी। सत्ता पक्ष अपनी बात को रखने के लिए सक्षम है।

श्री अभय वर्मा : अध्यक्ष जी, अब मैनेजमेंट की बात करते हैं जो कोविड के समय में सरकार ने मैनेजमेंट किया जिसकी खूब तारीफ की गई। लेकिन पूरा मैनेजमेंट फेल हुआ था। पूरे देश ने देखा था कि दिल्ली के बार्डर पर रातों रात कितने मजदूर पहूुच गए थे दिल्ली छोडकर। ये किसी से छुपा नहीं है। अन्य प्रदेशों में कहीं भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहां पर खाने में दिक्कत अनाज की दिक्कत। सारे मजदूर मजबूर हो गए कि हम दिल्ली से भागें और अपनी जान दूसरे राज्यों में जाकर बचाएं। स्वास्थ्य से सम्बन्धित पिछले वर्ष जो आदरणीय उप–मुख्यमंत्री जी ने बजट रखा था, उन्होंने कहा था कि 'आयुष्मान भारत' को हम लागू करेंगे। पूरे एक साल में कहीं भी लागू नहीं हुआ। रोजाना हमारे पास लोग आते हैं इलाज के लिए। पांच लाख का मुफ्त इलाज किसी भी अस्पताल में हम 'आयुष्मान भारत' में करा सकते हैं। पता नहीं क्यों ये सरकार इसकी घोषणा करने के बाद भी लागू नहीं कर पाई। इस बजट में 'आयुष्मान भारत' को लेकर आगे की कोई प्लानिंग भी नहीं बताई गई है। ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। विश्वास तोडने का काम किया गया है क्योंकि आयुष्मान भारत

से देश के अन्य राज्यों में बहुत सारे गरीब लोग लाभ उठा रहे हैं तो दिल्ली सरकार को तुरन्त लागू करना चाहिए। मोहल्ला क्लीनिक और पोलिक्लीनिक आदरणीय उप–मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में ये कहा था कि 491 मोहल्ला क्लीनिक दिल्ली में है और इस साल हम उसको एक हजार कर देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, सिर्फ 491 और उसके बाद क्या प्लान है कब एक हजार होंगे कैसे होंगे इसको लेकर इस बजट में कोई चर्चा नहीं है। पोलिक्लीनिक के लिए भी आदरणीय उप–मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी 24 पोलिक्लीनिक दिल्ली में हैं हम इसको 94 करेंगे। लेकिन सिर्फ 27 तक पहूंचे। क्यों हम फेल हो रहे हैं सरकार चलाने में। क्यों नहीं हमने 94 का अपना लक्ष्य पूरा किया। इस पर आदरणीय उप–मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में कुछ नहीं कहा। अध्यक्ष जी, मुफ्त टीका लगाने के लिए घोषणाएं कर दी गई। कल के अखबार में खूब छपा था कि दिल्ली वासियों को मुफ्त में टीका लगेगा। बजट कितना है 50 करोड। क्या पचास करोड में हम पूरे दिल्लीवासियों को मुफ्त में टीका लगा देंगे। इस पर जरूर जवाब देना चाहिए। मुझे तो पता है मैने कैल्कूलेट किया है दस लाख लोगों को मिल सकता है। तीस लाख लोगों को केन्द्र सरकार की योजना से दिल्ली में टीका लगने वाला है। दस लाख के लिए बजट आदरणीय उप–मुख्यमंत्री जी ने दिया है तीस लाख केन्द्र यानि एक लाख 60 हजार लोगों का क्या होगा। सभी अखबारों में बडी–बड़ी खबरें छप गई कि मुफ्त में टीके लगेंगे लेकिन उसकी कोई योजना इस बजट में नहीं है। उसके लिए कोई राशि आंवटित नहीं की गयी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले कहा कि ये बजट बड़ा निराशाजनक है। उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय को लेकर कई वर्षो से बजट को लेकर फंड को लेकर हमेशा विवाद होता है। दिल्ली की जनता ने एक गलती कर दी कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को दो तिहाई बहुमत से नगर निगम दे दिया। लेकिन उसकी सजा भाजपा अगर नगर निगम में आए तो हम नगर निगम को खत्म करेंगे, निरंकुश करेंगे और हमेशा उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो सिंगापुर बनाने का सपना छोड़ दीजिए। क्योंकि सब मद् में बजट बढ़े हैं। कुल बजट में छः परसेंट राशि बढ़ाई गई है लेकिन नगर निगम में 6828 करोड बजट था पिछले साल, इस साल 6172 करोड रूपये का बजट है। 658 करोड रूपया कम किया गया है। हम सब को पता है कि नगर निगम साफ सफाई कूड़ा उठाना, नाली

साफ करना, आज तक सबूत तो एक भी नहीं ले आए। आप भी तो नगर निगम में बैठे थे। एक बार भी आवाज उठाई।

माननीय अध्यक्षः चलिए कन्क्लूड करिए। नहीं कन्क्लूड करिए ना। आपको आठ मिनट हो गए हैं। मैं पांच मिनट से ज्यादा अलाऊ नहीं कर रहा हूं आठ मिनट हो गए हैं।

श्री अभय वर्माः 658 करोड रूपया कम करके हम क्या संदेश देना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए–चलिए।

श्री अभय वर्माः क्या हम दिल्ली की जनता को कूड़े के ढेर में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए। हो गया। कन्क्लूड करिए। अब कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री अभय वर्माः सर पांच मिनट मेरे को चाहिए।

माननीय अध्यक्षः नहीं अब पांच मिनट नहीं दे सकते। मेरे पास जो लिस्ट है ये इतनी लम्बी लिस्ट है। मुझे चार बजे तक सबको बुलाना है।

श्री अभय वर्माः अध्यक्ष जी शिक्षा को लेकर सरकार अपनी काफी तारीफ करती है। पिछले साल के बजट में हमने 17 नए स्कूल बनाने की बात की थी। इस साल के बजट में जीरो हो गया और वो 17 नए स्कूल बने या नहीं बने। किस जगह हम खड़े हैं उसके बारे में उप–मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं बताया बजट में। इसके अलावा पिछले बजट में हमने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए हाईटैक क्लास रूम बनाने की बात हुई थी। इस बजट से वो भी गायब है। आप बजट पेश ही ना करें अगर आप को लगता है कि हम नहीं कर पाऐंगे तो बजट ना पेश करें।

माननीय अध्यक्षः चलिए ठीक है हो गया। नहीं अब नहीं प्लीज। भैया जो बाकी रह गया है अपने साथियों को बता दो प्लीज।

श्री अभय वर्मा: एक चीज केवल एक प्वाइंट पर। कैमरे पर मेरे को बोलने दें सर। कैमरे पर इस बजट में असत्य तथ्य डाले गए हैं। आदरणीय उप–मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैने 01 लाख 40 हजार कैमरे लगाने के लिए प्रस्ताव किया था, जिसमें से 01 लाख 32 हजार कैमरे लग गए हैं। ये बिल्कुल असत्य है। आज भी मैने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की है। एक भी कैमरे 20 और 21 में नहीं लगे हैं और इसके लिए आदरणीय उप–मुख्यमंत्री जी को ये पैरा विद्ड्रा करना चाहिए क्योंकि ये हाउस को मिसगाईड नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा........दो लाईन सर दो लाईन।

माननीय अध्यक्ष: नहीं अब बिल्कुल नहीं। ऋतुराज झा। नहीं अब नहीं। ऋतुराज जी। भाई साहब ये ही दिक्कत है विपक्ष के साथ। बिल्कुल अब बैठ जाइए। अभी कल भी चर्चा होगी। अपने साथियों को बोल दीजिए। ऋतुराज झा जी।

श्री ऋतुराज गोविंद: आदरणीय अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष: अब मुंह से कह रहा हूं तीन बार बोल दिया। लो घंटी बजा दी बैठिए अब। ऋतुराज झा जी। संक्षेप में रखिए ऋतुराज जी। संक्षेप में रखिए। भई बोलने दो। समय बर्बाद हो रहा है। हॉ ऋतुराज जी शुरू करिए।

श्री ऋतुराज गोविंद: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि इस ऐतिहासिक बजट पर जो हमारे देश के एक ऐसे उप–मुख्यमंत्री जो बेहतरीन शिक्षा मंत्री के लिए तो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं लेकिन पहली बार इस पूरी दुनिया ने एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी इनको लगातार छह बार देखा है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय मंत्री जी की बात पर मैं आउं उससे पहले क्यूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं थोड़ा सा दिल्ली के इतिहास से मैं किस प्रकार से बजट को जोडूंगा इसको जरूर आप लोग सुनिए। और उससे पहले कि मैं शुरू करूं मैं एक बात कहना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्यूंकि बजट पर एक बहुत ही छोटी टिप्पणी की गयी है आज कि बजट पेश होने के एक दिन पहले माननीय प्रधान मंत्री जी भाषण दिए और वो छपा इक्नॉमिक्स टाइम्स में और उसको हमने कापी किया। ऐसा आरोप है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली एक

केन्द्र शासित प्रदेश है और यहां का बजट सदन के पटल पर पेश करने से पहले केन्द्र सरकार से उसकी मंजूरी ली जाती है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है it's a matter of record 28 तारीख को, 28 फरवरी को केन्द्र सरकार के पास हमारा बजट गया था। इसका मतलब।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई, आप बैठ जाइए प्लीज। आपने अभी बात कह दी वो जवाब नहीं देंगे। गलत आपने बोला है एक एक शब्द आपने गलत बोला है।

श्री ऋतुराज गोविंदः 28 फरवरी को हमने भेजा, 8 तारीख को भाषण दिया तो कापी किसने किया ? देखिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत इज्जत करता हूं। बहुत अच्छा भाषण देते हैं पर कापी तो न करें। और अध्यक्ष जी, दिल्ली शहर के अंदर कई शहर बसते हैं। यहां पर इन्द्रप्रस्थ से शुरू होता है जो भगवान श्रीकृष्ण के काल में था महाभारत के समय में इन्द्रप्रस्थ का नाम सुनते थे। पिथौरागढ़ बना, श्रीफोर्ट बना, मेहरोली बना, तुगलकाबाद बना, शाहजहांनाबाद बना, अंग्रेज आए, सिविल लाइंस बनाए, लुटियंस बनाएं, आजाद भारत के अंदर में द्वारका शहर, रोहिणी शहर, डीडीए ने बहुत सारे शहर बसाए। पर एक शहर ऐसा है अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर में जिसको किसी ने नहीं बसाया। लोगों ने खुद बसाया, लोगों की जरूरतों ने बसाया जिसको अनऑथोराइज्ड कालोनी कहते हैं साढे 17 सौ अनऑथोराइज्ड कालोनी पूरी दिल्ली में हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कैसे हुआ कि साढे 17 सौ कालोनी बस गए किसी भी राडार के अंदर में नहीं आया। किसी राजा के जैसा सौरभ भारद्वाज जी मजाक कर रहे हैं। आप सोचिए after liberalization जब हमारी इकानॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन के समय में शहरों के अंदर, चाहे वो दिल्ली हो, बंबई हो, चेन्नई हो, जितने भी मेट्रोपॉलिटन शहर हैं जब मार्किट ग्लोब्लाइज हुआ, प्राइवेटाइज हुआ तो jobs opportunities रातों–रात बहुत ज्यादा क्रिएट हुई। उस jobs opportunities को ग्रैब करने के लिए हम प्रवासी लोग जहां पर भी रोजगार के साधन कम थे, बहुत कम थे हम लोगों ने उसको ग्रैब किया, दिल्ली की तरफ कूच किए और after liberalization आदमी सबसे पहले अपनी रोटी की चिंता करता है उसके बाद वो

छत की चिंता करता है। छत तो कहीं बना लेगा, किसी सड़क पर रात गुजार लेगा लेकिन ये दो वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रामराज्य की कल्पना सबसे पहले तब हो सकती है जब ये सुनिश्चित किया जाए कि हमारे देश में और समाज में कोई भूखा न सोए। तो रोजगार के अभाव में अब हुआ क्या भैया रोजगार तो प्राप्त कर लिए, अब रहेंगे कहां ? अध्यक्ष महोदय, economy का liberalization तो हो गया, प्राइवेटाइजेशन तो हो गया लेकिन it was a failure of urban development policy कि जहां पर इस बात की forecasting नहीं की गयी कि जितनी जॉब्स क्रिएट होंगी after liberalization वो लोग जो job opportunity को ग्रैब करेंगे वो रहेंगे कहां, उसके लिए infrastructure कैसा होगा, उनके लिए छत कैसा होगा, उनके लिए घर कैसा होगा ? जिसके चलते दिल्ली के अंदर अनआथोराइज्ड कालोनिज बसी हैं और पिछले 25—30 साल के अंदर में बसती ही गयी, बसती गयी और आज साढे 17 सौ अनआथोराइज्ड कालोनी पूरी दिल्ली के अंदर हैं। वोट बैंक के रूप में सबने इस्तेमाल किया। कोई पार्टी इससे अछूत नहीं है। भाजपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया। लेकिन आज तक उनके लिए किया किसी ने नहीं। अनआथोराइज्ड कालोनिज में प्रवासी लोग रहते हैं अध्यक्ष महोदय, खाली हम बिहार से रहने वाले हैं, बिहार से आए हैं गमछा लगाकर कहने से नहीं होता है। उसके लिए काम करने से होता है, उसकी चिंता करने से होता है। उसके जीवन में परिवर्तन कैसे आए, इस बात को करने से होता है। अध्यक्ष महोदय, 2015 तक जब तक हमारी सरकार नहीं बनी थी दिल्ली के अंदर, अनआथोराइज्ड कालोनी में रहने वाले लोग हम बिहार, उत्तर प्रदेश के प्रवासी लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे, पीने के पानी के टैंकर के लिए महिलाएं सुबह 4 बजे लाइन लगाया करती थीं और सोचिए कि कितना अपमान का काम था, लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, एफआईआर, थाना, कोर्ट—कचहरी होता था और डेली का ये काम था सुबह से लेकर के रात तक के झगड़े होते थे। पीने का पानी तक नहीं था। आज माननीय उप—मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया उस बजट के अंदर आप सबके सामने डेटा पेश किया कि आज साढे 17 सौ कालोनी में से साढे 16 सौ कालोनिज के अंदर साढे 14 हजार किलोमीटर से ज्यादा के पाइप लाइन बिछाकर के घर घर तक पीने का पानी पहुंचा दिया और उन माताओं, बहनों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया, पीने के पानी

जैसी मूलभूत सुविधा के लिए आज तक हम वंचित थे और आज गर्व से हम पीने का पानी अपने घर पर पीते हैं और उसके लिए हमें किसी पैसे को देने की जरूरत नहीं है, फ्री में पीते हैं। 484 रूपया पर स्कवेयर मीटर के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज था अध्यक्ष महोदय यानि कि किसी गरीब आदमी का मकान अगर 50 गज का है उसको 30—40 हजार रूपया तो केवल डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर देना पड़ता था पीने के पानी का कनेक्शन लेने के लिए जिसको माननीय मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने 87 रूपया गज कर दिया, बिल्कुल नामिनल कर दिया ताकि गरीब से गरीब आदमी भी पीने के पानी का कनेक्शन ले सके। पीने का पानी दे दिया, उसके बाद नालियों में बहता हुआ गंद, चारों तरफ गंदगी, सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं, वहां पर भी सेफ्टी टैंकस बनाए हुए थे अनऑथोराइज्ड कालोनिज के अंदर में लोगों ने जिसका 15—15, 16—16 सौ रूप्ये जो है सेफ्टी टैंक वाले खाली करने के लेते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड किया कि पहले घर घर पीने का पानी पहुंचाया है, अभी आने वाले समय में सुनिश्चित करेंगे कि पूरे अनऑथोराइज्ड कालोनी के अंदर में, एक एक गली के अंदर में सीवर की लाइन बिछाकर के एक एक जनता को सीवरेज का भी सिस्टम देंगे ताकि अनऑथोराइज्ड कालोनी में जो गंदगी होती है वो गंदगी से भी मुक्ति मिलेगी, सम्मानजनक जीवन मिलेगा और उससे जो यमुना में प्रदूषण होता है उसमें भी कमी आएगी और यमुना नदी जो हमारी यमुना मैया है वो भी साफ हो पाएगी उसके लिए उन्होंने काम किया। जिसका बजट के अंदर साफ दिख रहा है। 3200 करोड़ से ज्यादा रूप्या जो है केवल और केवल पीने के पानी और ड्रेनेज के लिए दिया गया अध्यक्ष महोदय। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री सीवरेज सिस्टम जो है ये मुफ्त में चालू किया गया जिससे लगभग 5 लाख परिवार को, 5 लाख परिवार को मुफ्त में सीवर का कनेक्शन मिला है और जिस क्षेत्र को मैं रिप्रजेंट करता हूं वहां पर एक साथ 114 कालोनी के अंदर में सीवर की लाइन डालने का काम शुरू हो चुका है जिसका शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री 14 तारीख को हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आम आदमी पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने हम अनऑथोराइज्ड कालोनी में रहने वाले गरीब, जरूरतमंद लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। पीने का पानी, सीवरेज सिस्टम, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला

क्लिनिक मैं आपको एक बड़ी बात नहीं कहता हूं मेरे क्षेत्र के अंदर में जो मोहल्ला क्लिनिक्स बने हैं वहां पर रोहिणी के सेक्टर से भी लोग इलाज कराने के लिए लोग आते, अगर आपको यकीन न हो तो जाकर पता कर सकते हैं। रोहिणी के सेक्टर से आते हैं लोग। इतना काम हो रहा है। अरे गमछा लगाकर, लाल गमछा लगाकर आप उस दिन जब दंगा हो रहा था तो नारेबाजी कर रहे थे और आज जो है समझते हैं कि हम बिहारी हैं, तो हम बंगाली हैं। अरे भैया बिहारी कहने से नहीं होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश के प्रवासी लोगों के लिए काम करने से होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री द्वारा जो बजट के अंदर में खास कर के पीने के पानी के लिए, ड्रेनेज के लिए जो व्यवस्था की गयी है उसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं, सराहना करता हूं, सलाम करता हूं और अनऑथोराइज्ड कालोनी में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को पहली बार एक सम्मानजनक जिन्दगी जीने का अधिकार मिला है उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं और ये आगे भी सिलसिला जारी रहेगा और जो भी छोटा मोटा जो बचा हुआ काम है ये भी जरूर होगा, ये हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी ने पूरे 5 मिनट में अपनी बात पूरी रख दी, बड़े जोर से रख दी, उनको बधाई। बी.एस. जून जी।

श्री बी.एस. जूनः धन्यवाद अध्यक्ष जी। अभय वर्मा जी ने कुछ बातें उठाई, अध्यक्ष जी पहले मैं उनका रिप्लाई दूं। एक तो ये है अभय वर्मा जी कोई बजट ओवरनाइट नहीं बनता। आपने कहा कापी पेस्ट कर दिया ऋतुराज जी ने कहा कि कापी पेस्ट आप की स्पीच में हुआ ये डाकुमेंट पहले तैयार हो गया था। दूसरा आपने कहा कि बजट जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो प्लाज्मा थेरेपी थी इसका कोई असर नहीं हुआ सॉरी आइसोलेशन का इसका प्लाज्मा थेरेपी का कोई असर नहीं हुआ। ये गुप्ता जी यहां नहीं हैं पिछले सदन में उन्होंने एक बात कही थी कि वैक्सीनेशन आ चुकी है, तब तक वैक्सीनेशन नहीं आई थी और वो वैक्सीनेशन क्या है, दो गज की दूरी आइसोलेशन और मास्क। तो आप डिसाइड कर लें गुप्ता जी ठीक थे या आप ठीक थे। दो गज की दूरी का स्लोगन किसने दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। दो गज की दूरी। तो आप उसको मानते होंगे ? तो जिस तरीके से कोविड को दिल्ली

में कंट्रोल किया वो इतना एप्रिशिएबल है सिर्फ इंडिया में नहीं, एब्रोड भी। अब सुनिए मैं आपको एक फिगर देता हूं। आपने बताया फैटिलिटी रेट । आपने कह दिया साढे 3 मौत हुईं, वो तो हमारी समझ में आ गई। एक कहावत है गांव में वो एक छत से गिर के मर गया, नीचे खूंटा था। उन्होंन कहा यार बहुत अच्छा हुआ अगर खूंटे पे गिरता तो कतई मर जाता। तो साढ़े–तीन मौत कैसे हुई ये तो एक सीक्रेट है और सीक्रेट ही रहेगा। मैं आपको फैटिलिटी रेट बताता हूं। देहरादून, उत्तराखंड, आपका स्टेट है बीजेपी का फैटिलिटी रेट कितनी है 3.2 परसेंट, शिमला बीजेपी रूल्ड स्टेट है फैटिलिटी रेट

...व्यवधान...

श्री बी.एस. जूनः सुन जाओ।

...व्यवधान...

श्री बी.एस. जूनः सुन तो लो, शिमला। अरे सुन तो लो वो मैं बता रहा हूं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं उनपर।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई ये क्या आग न लगे वो शहर की तुलना करें या राज्य की। आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। हां बैठिए बैठिए।

...व्यवधान...

श्री बी.एस. जूनः सुनने की हिम्मत रखो।

माननीय अध्यक्षः ऐसे नहीं चलेगा। हां बैठिए।

श्री बी.एस. जूनः मैं fatality रेट पर हूं। शिमला हिमाचल प्रदेश।

माननीय अध्यक्षः वो बोल रहे हैं शिमला हिमाचल प्रदेश।

श्री बी.एस. जून: अरे अभय वर्मा जी सुनिए शिमला हिमाचल प्रदेश 2.5 परसेंट। हिमाचल प्रदेश बता रहा हूं न। एक सेकंड वो अरे सुन तो लो गुजरात, गुजरात 3.6 परसेंट अरे मैं दिल्ली पर आ रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: भाई आप सुन तो लीजिए। कमाल की बात है।

श्री बी.एस. जून: मैं दिल्ली पे आ रहा हूं। यूपी 2.5 परसेंट, महाराष्ट्र 3.4 परसेंट, चैन्नई 1.8 परसेंट, वेस्ट बंगाल सुन लो। अरे सुन लो। वेस्ट बंगाल 2.4 परसेंट। अब मैं दिल्ली पर आ रहा हूं जरा दिल्ली की फीगर सुन लो।

माननीय अध्यक्ष: अरे वो राज्य में बोल रहे हैं आप बोल क्या रहे हो वो एक—एक स्टेट का बोल। वो स्टेट।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष: देखिए वो अगर बोलेंगे, बोलने की बारी आएगी न अभी फिर वो जब खड़े होंगे तो मुझे मत बोलना।

श्री बी.एस. जून: कोविड में दिल्ली की फैटिलिटी रेट रही 1.7 परसेंट कन्ट्री में सबसे कम, सबसे कम और आप कहते हो सबकुछ फेल हो गया।

माननीय अध्यक्ष: चलिए।

श्री बी.एस. जून: अध्यक्ष जी, ये बजट आया 9 तारीख को, 10 तारीख को प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसमें बहुत आया हमें ऐसा लगा शायद ये यूनियन बजट है इतनी प्रशंसा हुई। क्रेडिट जाता है माननीय उप—मुख्यमंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो दस प्रिंसिपल्स का उन्होंने उसमें जिक्र किया था इस बजट में उसका समावेश है। प्रिंट मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने इस बजट को criticize किया हो, हां आप लोगों ने जरूर किया। आप लोगों ने जरूर किया और वो भी flimsy grounds पर कोई आपके पास cogent कोई logical बात आपने नहीं की है। हर आदमी ने कहा कि एक बैलेंस बजट है, प्रोग्रेसिव बजट है, इन्सपायरिंग बजट है और for entire

society के लिए है हर आदमी ने कहा, सिर्फ आपको तकलीफ हुई। देखिए किसी पर कोई टैक्स नहीं लगा। घाटे का बजट नहीं आया फिर भी हर आदमी खुश है। आप ये चाहते हैं घाटे का बजट होता तो अच्छा होता। आप ये कहते हैं झूठ का पुलिंदा है ये, ऐसा कुछ नहीं है। सर जो 10 अवधारणा कल सीएम साहब ने बताई थी 6 साल उन पर सरकार चलती रही। उनका रिजल्ट क्या हुआ। उनका रिजल्ट दखिए आप पर कैपिटा इनकम में 2015–16 में पर कैपिटा इनकम कितनी थी 19,218, anticipated 2021–22 की कितनी है 33,173 ये फर्क है गुड गवर्नेंस का और बैड गवर्नेंस का per capita income year-wise Delhiites की बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको बताउं, आपको शायद बुरा लगे, बैड गवर्नंस का कल ही एक उदाहरण मिला। उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ गया। अगर बैड गवर्नेंस थी तो क्या जरूरत पड़ती है एक साल इलेक्शन का रह गया। दिल्ली में देख लीजिए आप, दिल्ली में आपकी पांच साल सरकार रही तीन मुख्यमंत्री रहे। इसको कहते हैं बैड गवर्नेंस और हमारे मुख्यमंत्री 6 साल बाद भी, 6 साल बाद भी पॉपूलेरिटी की नई हाइट्स को अटेन करते जा रहे हैं। आज हर आदमी ये कहता है कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जब से आए हैं दिल्ली का उत्थान हो रहा है। आपको बीस साल हो गए उस साइड में ऐसा लगता है फेविकोल से चिपक गए हैं आप। ऐसा लगता है फेविकोल से आप चिपक गए हैं और क्योंकि आपकी विश्वसनीयता, trustworthiness आपकी खत्म हो चुकी है पब्लिक में और अगर यही सिस्टम रहा तो लगता है अगले 20 साल और वहीं बैठे रहोगे। अगले 20 साल और वहीं बैठे रहोगे। अध्यक्ष जी इस बजट में माननीय उप–मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बहुत चैलेंजिंग टास्क पेश किए हैं और ऐसे चैलेंजिंग टास्क जो आज के लोग कहेंगे ये तो हवा की बाते हैं, जुमलेबाजी है । नम्बर (1) 2048 की ओलंपिक गेम्स की मेजबानी। नम्बर (2) 1947 तक पर कैपिटा इनकम सिंगापुर के एम्पलायज के बराबर।

माननीय अध्यक्षः 2047।

श्री बी.एस. जूनः लेकिन जिस दस principles पर ये सरकार चल रही है और जो समावेश इस बजट में उन 10 प्रिंसिपल्स का है ये जो टारगेट है ये अपने आप

क्लोजर होते चले जाएंगे पास आते चले जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय उप–मुख्यमंत्री जी की जो पॉलिसीज हैं जो ये जितनी स्कीम्स लेकर आए हैं इंफ्रास्टक्चर के बारे में कि ये चैलेंजिंग टास्क भी हम जरूर पूरा करेंगे और 1935 के आस–पास हम ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी बिडिंग करेंगे। सॉरी सॉरी 2000 सॉरी सॉरी। सर, कोई भी सपना, कोई भी विजन in fact ये बजट जो है एक विजन डाक्युमेंट है जो अगले 25–30 साल को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें बहुत से ऐसे सपने हैं जिनको साकार करने के लिए बहुत बड़े infrastructure की जरूरत पड़ेगी। किसी भी बड़े सपने को, ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पहले आप सपना देखो, उसके साथ विजन हो, उसके बाद आपनी प्लानिंग हो और उसके बाद आपकी प्रीपेरेशन हो और फाइनली इंप्लीमेंटेशन हो और एग्जीक्यूशन हो। अगर ये चीज आपने कर ली तो कोई भी बड़े–से–बड़ा टारगेट हो वो आप अचीव कर लेंगे। सर चाहे एजुकेशन का infrastructure हो, हैल्थ का हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हो, रोड पर infrastructure हो, हैल्थ infrastructure, ट्रासंपोर्ट infrastructure हो, मेट्रो का हो, टूरिज्म का हो, हर infrastructure में इस बजट में कहीं–न–कहीं एसे प्रोजेक्टस आ रहे हैं जिनसे infrastructure को इन सेक्टर्स में बूस्ट मिलेगा और जब infrastructure को बूस्ट मिलेगा तो सर राज्य की इकानॉमी अपने आप साउंड होती चली जाएगी और लोगों का जीवन खुशहाल हो जाएगा। अभी आपने क्या किया, टैक्स शेयर आप कितना देते हैं दिल्ली सरकार को, 325 करोड़। आप बात कर रहे थे एमसीडी के बजट की कटौती की और grant-in-aid कितना दिया 657 करोड़। आप दिल्ली सरकार की मद्द नहीं कर रहे despite that दिल्ली सरकार इतना इफेक्टिव इतना attractive बजट दे रही है कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अध्यक्ष जी अगर मैं बात करूं एजुकेशन में infrastructure की पिछले 6 साल में गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोपर infrastructure दिया जिसकी वजह से एजुकेशन का स्टेंडर्ड बहुत हाई हुआ और आज उसको appreciate country में ही नहीं abroad में भी होता है। दूसरा, एजुकेशन का सोर्स का एक inter-connected मामला है। हमने दिल्ली में बहुत अच्छे–अच्छे infrastructure स्पोर्टस के लिए खड़े किए जिससे इन्टरनेशनल लेवल के प्लेयर्स पैदा हुए और उसकी वजह से शायद उप–मुख्यमंत्री जी ने 2048 ओलंपिक्स की मेजबानी प्लान की है कि उसमें

हम इतना सक्षम हो जाए कि उसकी बिड देने में हम कामयाबी हासिल कर पाएं। दूसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल infrastructure का ये भी infrastructure का हिस्सा है। मैक्सिमम सब्सिडी दी रजिस्ट्रेशन चार्जिज ड्रोप किए और ज्यादा—से—ज्यादा चार्जिंग प्वाइंट्स बनाए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का पॉल्यूशन को कन्ट्रोल करने के लिए। रोड इंफ्रास्टक्चर की बात करें अध्यक्ष जी, अभी अभय वर्मा जी कह रहे थे 1 लाख, 40 हजार कैमरे लगाने थे जिनमें से 1 लाख 32 हजार लगाने का मंत्री जी ने दिखाया बजट में और 2020—21 में कोई नहीं लगा। तो प्लीज सुन लो 2020—21 में कोई नहीं लगा। अरे सर सुनो तो सही 1 लाख 32 हजार की बात कर रहा हूं। 2020—21 में आपने कहा कोई नहीं लगा। मैं खड़ा हूं आपके सामने मेरी constituency में लगे हैं। ये कह रहे हैं एक नहीं लगा, मैं कह रहा हूं मैं खड़ा हूं मेरी constituency में लगे। तो ये बात न कहिए कि एक भी नहीं लगा। सर आपके नहीं लगे, आपके नहीं लगे उसपर 200 करोड़ जो इन्होंने बजट में रखे हैं इस बार लग जाएंगे। अध्यक्ष जी infrastructure की बात करें अण्डरपास बन रहा है आश्रम चौक पर 35 करोड़ रुपये उस बजट में रखे गए इस साल पूरा हो जाएगा और उससे रिडेक्शन होगा ट्रेफिक फ्लो में, ट्रेफिक ट्रेबल टाइम में पॉल्यूशन लेवल डाउन आएगा और फ्यूल सेविंगस भी डाउन आएंगी। फ्यूल सेविंगस जो है वो भी कम हो जाएंगी। इसी तरह आश्रम फलाइओवर बनने जा रहा है ट्रैफिक फ्लो कम होगा, ट्रैफिक फ्लो स्मूथ होगा, पॉल्यूशन लेवल भी जो है काफी डाउन आ जाएगा। 5 बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं सर जिसमें से पंजाबी बाग, ज्वालहेड़ी, मुकरबा चौक, मैन बुराड़ी रोड़ और खेड़ा गांव जिससे कि ट्रैफिक कंजेशन कम करने में मद्द मिलेगी। तीन बड़े बिग स्कीम्स जो है ईस्ट—वेस्ट कॉरिडोर, नोर्थ—वेस्ट, साउथ कॉरिडोर और आउटर रिंग रोड पर यमुना के पेरलल एक रोड बनाने की स्कीम है। सर ये सारे इंफ्रास्टक्चर ब्यूटिफिकेशन स्कीम 500 किलोमीटर सड़को का जिसमें 500 करोड़ मंत्री जी ने रखे हैं। हैल्थइंफ्रास्टक्चर सर कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। डवलप कन्ट्रीज अमेरिका, यूके, यूरोपियन कन्ट्रीज सब हार गए कोविड से लेकिन ये एक ऐसा देश था एक ऐसी देश की राजधानी थी जिसमें हमारे मंत्री जी रात—दिन इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि आज दिल्ली में ऐसा लगता है कोविड खत्म हो गया। कल एक बात आई किसी ने कहा कि भई हमारे स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य बिगड़ गया वो घर बैठकर नहीं

बिगड़ा, ये जगह–जगह गए हॉस्पिटल्स में गए, affected areas में गए तो after all human being तो ये भी है अगर ऐसा हुआ था तो इनकी क्या गलती थी। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से कोविड को संभाला वो appreciable है, इनकी तारीफ करनी चाहिए न कि इनको criticize करना चाहिए।

माननीय अध्यक्षः जून साहब अब। जून साहब हो गया

श्री बी.एस. जूनः सर एक सेकंड।

माननीय अध्यक्षः नहीं अब हो गया प्लीज जून साहब।

श्री बी.एस. जूनः सर एक सेकंड, एक सेकंड लूंगा। एक ट्रांसपोर्ट के उसमें और कहना चाहूंगा आज बड़ा हंगामा हुआ, गुप्ता जी ने बहुत हंगामा किया। सर गुप्ता जी के तीन शब्द बड़े फेवरेट हैं एक घोटाला, दूसरा घपला और तीसरा कांड। कुछ दिन पहले गुप्ता जी ने एक आरोप लगाया था जैसे आज लगा रहे थे कि स्कूल बनाने में 25 लाख रुपये में कमरा बना दिया और उसमें ये एक प्रेस कॉफ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि दो दिन बाद हम सबूत पेश करेंगे। सर कोई सबूत नहीं आया। रिजल्ट क्या हुआ रिजल्ट क्या हुआ गुप्ता जी बेल पर आ गए। उस केस में गुप्ता जी बेल पर आ गए। second, सर, प्लीज सर मुझे बोलने दो, second Sir ये हमारे मंत्री जी बैठे हैं कि इन्होंने 23 करोड़ रुपये ले लिए पेड़ काटने के। उसमें क्या हुआ गुप्ता जी का उस केस में भी गुप्ता जी बेल पे आ गए। अब तीन–चार ऐसे केसिज हैं जिसमें गुप्ता जी बेल पर हैं, प्लीज गुप्ता जी फ्री की सलाह है wild allegation मत लगाइए। wild allegation मत लगाइए। wild allegation का कोई फायदा नहीं है। अब आपने कोर्टो के चक्कर काटे है न मुझे बड़ा बुरा लगता है। सर आप कोर्टों के चक्कर काटते हैं न मुझे बड़ा बुरा लगता है। आप कोर्ट जाकर खड़े हो जाते हैं बहुत। देखिए गुप्ता जी, गुप्ता जी प्लीज एक बात सुनो आप अध्यक्ष जी गुप्ता जी कोर्टों में ज्यादा नजर आते हैं विधान सभा में कम नजर आते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे बयान मत दीजिए wild allegation मत लगाइए। तो आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

मननीय अध्यक्ष : श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट में हिस्सा लेने का मौका दिया बजट के धन्यवाद के रूप में। अध्यक्ष महोदय, अभी अभय वर्मा जी जो कह रहे थे कि ये कॉपी करने का बडा शौक है हमें। अभी तो पूरी दुनिया जान गयी है कि कौन किसको कापी कर रहा है क्योंकि देखिए, और इसलिए कापी करने वाला काम तो मत कहो, इल्जाम मत लगाओ। वो हम पर चिपकेगा नहीं। वो हम पर नहीं चिपकेगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कापी पर कहा कि बहुत सारे इन्होंने क्रिटिसिज्म किया हमारा, निन्दा किया इन्होंने हमारी। आपको शायद याद नहीं है कि भाजपा वाले बहुत क्लेम करते हैं कि दिल्ली में कोविड कन्टेन किया तो अमित शाह जी ने किया। पता है आपको । एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि अमित शाह जी ने किया, अमित शाह जी ने किया, अमित शाह जी ने किया। आपने होर्डिंग्स लगवाये दिल्ली में, 'अमित शाह जी का धन्यवाद'। तो या तो दिल्ली में कोविड कन्टेन हुआ या नहीं हुआ। ये बता दो। अब किया किसने वो बाद में देख लेंगे हम। वो हम बाद में देख लेंगे। यहां तक कि मोदी जी ने एक बार एक अखबार में मैंने पढ़ा कि कहा कि भई दिल्ली मॉडल अपनाओ। पूरे देश को कहा कि दिल्ली में जिस तरह से सरकार ने कोविड को कन्टेन किया है उसको पूरा देश अपनाये। हर राज्य अपनाये । तो इसलिए कहीं आपकी पार्टी आपको कोई नोटिस इश्यू न कर दे जिस तरह से आपने दिल्ली में कोविड कन्टेनमेन्ट की निन्दा की और ये सीसीटीवी वाला भूल गये। सीसीटीवी की आलोचना जब अमित शाह जी ने की कि सीसीटीवी नहीं लगाये तो जिस मोहल्ले में पर्चा बॉट रहे थे वही सीसीटीवी कैप्चर करके उन्हीं को दिखा दिया। इसलिए निन्दा मत किया करो। जो चीज हुई है वो हुई है। अरे भाई हमने दिखाया है आपको। अध्यक्ष महोदय, मैं,

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : प्रमिला जी।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं मनीष जी का, चूंकि उन्होंने एक नयी सोच बजट में लेकर आये outcome और output सिर्फ यही नहीं कि पैसा लगाकर

हमने वहां वो मशीन खरीद ली। मशीन का कितना उपयोग हुआ इसका ब्यौरा देना सदन के अन्दर बहुत बड़ी बात है और इस नयी सोच के लिए मैं उनको सलाम करता हूं। उनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय केजरीवाल साहब ने चूंकि हो ये रहा है कि ये कुछ भी सोचते हैं उस पर आगे हम निकल जाते हैं। देशभक्ति की चर्चा ये करें और देशभक्ति करके हम दिखायें। भगवान श्रीराम का नाम ये लेते हैं और राम राज्य करके हम दिखा देते हैं तो कहना और करना, करनी और कथनी में कितना फर्क है। तो जिस तरह से, जिस तरह से राम राज्य की अवधारणा की चर्चा माननीय केजरीवाल साहब ने सदन के अन्दर की। एक नयी दिशा दिया। भगवान श्रीराम का सिर्फ नाम नहीं लेना है, भगवान श्रीराम के बताये कदमों पर, उनके राम राज्य की परिकल्पना पर चलकर दिखाना है, दिल्ली को करके दिखाना है अध्यक्ष महोदय। ये माननीय केजरीवाल साहब ने करके दिखाया। बड़ा philosophical एक टर्न लिया मनीष जी का स्पीच जब उन्होंने कोट किया। रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने कोट किया। उन्होंने Keating जो 'Dead Poets Society' का एक character है उसे कोट किया। जब उन्होंने वशीर भद्र साहब को भी कोट किया। तो उसमें John Keating का एक बड़ा फेमस सा उसी मूवी के अन्दर आता है 'O captain, my captain', this was something said by Wall Betumen for Abraham Lincoln तो मैं अरविन्द जी यहां नहीं है लेकिन उनके प्रारूप मनीष जी को मैं कहता हूं वो 'o captain, my captain, what you have done for Delhi is remarkable and for that generations will be thankful to you that you have given a direction' जिससे कि देश के और फाइनेन्स मिनिस्टर्स को एक दिशा मिल पाये कि किस दिशा में काम करके दिखाना है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति बजट जो मनीष जी ने और जो एक टर्मनोलॉजी दी इस बजट में और एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर नजर आ रहा है चूंकि अरविन्द जी का जो पूरा एक जीवन रहा है rebel का जीवन रहा है। एक ऐसे व्यक्ति का जीवन रहा है जो कि status quo नहीं मानता। भई कुछ भी status quo है उसको चैलेन्ज करके जनता के लिए चेन्ज करना है तो करेंगे और उसी लाइन में मैं देखता हूं कि मनीष जी ने जो बात की कि भगत सिंह जी और डॉक्टर अम्बेडकर की जो जीवनी स्कूल में पढ़ायी जायेगी। देखो जी ये दोनो कैरेक्टर इस इतिहास के कोई आसान कैरेक्टर नहीं हैं। सरकारें झेल नहीं पातीं।

जो विचार भगत सिंह जी के हैं उसे अगर घर–घर पढ़ा दिया गया। जो डॉक्टर अम्बेडकर के विचार हैं, घर–घर पढ़ा दिया गया तो ये समझिए कि एक अरविन्द केजरीवाल तो आज ये सम्भाल नहीं पा रहे हैं अगर ये सब पढ़ा दिया गया तो घर–घर अरविन्द केजरीवाल हो जायेगा। फिर कैसे सम्भालेंगे। मैं इतनी बड़ी सोच के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति की बात करते हैं। भई 1925 में इनके जो मदर आर्गनाइजेशन है आरएसएस उसका स्थापना हुआ। 1925 से ले करके 1947 तक 22 साल में देश की आजादी की लड़ाई के 22 साल में एक उल्लेख नहीं है जब आरएसएस या उसके किसी नेता ने किसी संग्राम, किसी फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं, बताता हूं उसको बताता हूं। 23 मार्च, 1931 को जब भगत सिंह जी को फांसी हुई। एक स्टेटमेन्ट रिकार्ड में नहीं है डॉक्टर हेडगेवार के नाम या गोलवरकर के नाम। गोलवरकर ने और डॉक्टर हेडगेवार ने कुछ कभी नहीं कहा। इनको तनिक सा उस पर कोई खेद नहीं हुआ कि इतने बड़े फ्रीडम स्ट्रगल के अन्दर तीन नौजवान साथियों ने जब 23 साल और 22 साल की उम्र के थे तब उनको फांसी चढ़ा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, चाहे भारत माता की जय कहते रहो, कहने से बात नहीं होती है, करने से बात होती है। ये वो संस्था है जिसने कि 52 साल तक fifty two years तक fifty two years तक जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया अपने नागपुर के हेडक्वार्टर में, वो भारत माता की जय हमें सिखायेंगे। तो देशभक्ति का जो अभी चूंकि सदन के अन्दर ही आज जब बात हो रही थी तो नाथूराम गाडसे, ये तो खुल्लमखुल्ला कहते हैं। ये बड़ा dichotomy है और बड़े interesting dichotomy पता नहीं कैसे ये इतनी सारी dichotomy को ये sustain कर लेते हैं। कह रहे हैं नाथूराम गोडसे की तो पूजा करेंगे हम। ओमप्रकाश जी ने कहा कि हम करेंगे। अभी भी कह रहे हैं। तो नाथूराम गोडसे की भी पूजा करना चाहेंगे। मन्दिर बना लें जगह–जगह और महात्मा गॉधी की भी। तो ये dichotomy कैसे कर लेते हैं ये । तो देशभक्ति इनका दिखावे वाला है और जो मनीष जी ने बात की देशभक्ति का वो असली देशभक्ति है। इस जज्बे के लिए मैं उनको सलाम करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इन्वायरमेन्ट के उपर जो चर्चा हुई चूंकि इन्वायरमेन्ट और ह्यूमन्स का को–एक्जिस्टेन्स हार्मोनी के साथ–साथ होना बहुत जरूरी है। दिल्ली के अन्दर बहुत सारे काम इन्वायरमेन्ट के उपर प्रोटेक्ट करने के

लिए किये गये। उसमें चाहे वो एन्टी स्मोक गन्स हो, बायोडिकम्पोजर हो, पराली के लिए जो अभी माननीय केजरीवाल साहब ने पूरे विश्व को दिखाया कि कैसे पराली, पराली से हर कोई पीड़ित है। पंजाब भी पीड़ित था। हरियाणा भी पीड़ित था लेकिन दिल्ली के अन्दर केजरीवाल साहब ने वो जो एक केमिकल को यूज करके पूसा इन्स्टीट्यूट का जो उसको गलाकर दिखाया और एक इन्वायरमेन्ट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाकर दिखाया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, चाहे सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना हो, मैकेनिकल रोड शिपिंग करना हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट करना हो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट का प्लान्ट जगह–जगह बन रहा है, वो करना हो। ऐसे कई सारे मेजर्स और एक बड़ा मेजर जो है कि थर्मल प्लान्ट्स, दिल्ली पहला स्टेट है जहां थर्मल पावर प्लान्ट को बन्द किया गया। इसके लिए दिल्ली की सरकार को बहुत–बहुत बधाई। अध्यक्ष महोदय, और एक मदर ऑफ आल मेजर्स कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी। चूंकि जैसा मनीष जी ने उस दिन कहा हॉर्सेस से हम गाड़ी पर आये, अब गाड़ी से हम पेट्रोल–डीजल की गाड़ी से हम इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। तो ये समय मॉग करता है और इस बार पेट्रोल–डीजल वैसे भी बहुत महंगा हो गया। अनअफोर्डेबल हो गया है। चूंकि जैसे उन्होंने अनअफोर्डेबल कर दिया है उस दिन अतिशी जी कह रही थी जीडीपी नहीं बढ़ी। जीडीपी बढ़ी गैस, डीजल, पेट्रोल खूब बढ़ी। जीडीपी बढ़ाया है आपने लेकिन किसी और एंगल से बढ़ा है जनता को काफी दुखी किया। अध्यक्ष महोदय,

माननीय अध्यक्ष : सोमनाथ जी कन्क्लूड करिए। कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : कर रहा हूं। 3 लाख रूपया का सब्सिडी कार पर दे रही है दिल्ली सरकार। 30 हजार की सब्सिडी स्कूटर पर दे रही है दिल्ली सरकार और इसको करीब–करीब जो हमारी नार्मल व्हीकल्स है जो डीजल वाली व्हीकल है उसके बराबर के उपर, उसके बराबर ये सब कॉस्ट लेकर आ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, 1300 ई–बसेज दिसम्बर तक आ जायेगा जिससे दिल्ली में 7698 बसेज हो जायेंगी जो ये बार–बार डीटीसीज बसेज की बात उठा रहे थे। एक तरफ कहते हैं गुप्ता जी की बसेज नहीं आ रही हैं एक तरफ जब ला रहे होते हैं उस पर सवाल उठाते हैं। तो चित भी मेरी पट भी मेरी और सिक्का मोदी जी का।

माननीय अध्यक्ष : सोमनाथ जी हो गया। अब हो गया। नहीं, अब नहीं। प्लीज। सोमनाथ जी अब कन्क्लूड करिए।

श्री सोमनाथ भारती : दो मिनट।

माननीय अध्यक्ष : नहीं बस अब लास्ट। प्लीज। अभी सदस्य बाकी रह गये हैं।

श्री सोमनाथ भारती : जो एक जो न्यू पॉलिसी आयी है ट्रांसप्लान्टेशन की। इसमें 80 प्रतिशत जो पेड़ उखाड़ा जायेगा, जो काटा जायेगा उसको ट्रांसप्लान्ट कराना जरूरी है। ये इन्वायरमेन्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : हो गया। धन्यवाद। धन्यवाद, नहीं अब सोमनाथ जी प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : जिस शेप में, जिस कन्डीशन में, दो मिनट दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : अब नहीं सोमनाथ जी। नहीं है समय। सब लोगों ने बोलना है। माननीय सदस्यों ने बोलना है प्लीज। प्लीज अब कन्क्लूड कर दीजिए। आप सम्मानित सदस्य हैं। अच्छा बोलते है। मैं जानता हूं। आप एक घण्टा बोल सकते हैं। देखिए, अब कन्क्लूड कर दीजिए।

श्री सोमनाथ भारती : एक पॉलिसी इन्वायरमेन्ट की जो मुझे लग रहा है दिल्ली सरकार ने उसके उपर जो काम किया है। जिस रूप में और जिस शेप में हमने earth को inherit किया अपने पूर्वजों से। उससे बेटर करके छोड़ें। जब भी चूंकि हम सब impermanent हैं nobody is permanent here तो जैसे ही ये सोच अगर आगे रखी जाती है तो इन्वायरमेन्ट का प्रोटेक्शन अपने आप हो जाता है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: हो गया अब।

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय, पावर के अंदर।

माननीय अध्यक्षः नहीं अब हो गया सोमनाथ जी। नहीं देखों बार बार मुझे मत कहिए प्लीज। प्लीज आप कंक्लूड। बात को समझिए। मैं मानता हूं कि आपके पास बहुत मेटैरियल है बोलने के लिए। अरे आप भी वकील हैं, जून साहब भी वकील हैं। जून साहब तुरंत कहना मान गये। आप कहना नहीं मान रहे।

....व्यवधान....

श्री सोमनाथ भारतीः अब जो टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो केजरीवाल साहब ने different languages में आज तक का इतिहास है ये। लोग कहते थे, लेकिन पहली बार सरकार ने करके दिखाया है। देश की हर भाषा में दिल्ली में एकेडमी स्थापित हुआ है। यह बहुत बड़ी बात है। मैं देखता हूं कि सरदार पटेल ने जिस तरह से देश को, देश के different स्टेट्स को इक्ट्ठा किया। आज केजरीवाल साहब ने देश की different भाषाओं को एकेडमी के माध्यम से जो जोड़ने का काम किया है, ये अपने आप में काबिलेतारीफ है अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी अब।

श्री सोमनाथ भारतीः कि ये जो बजट है।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारतीः ये बजट, ये बजट हिन्दुस्तान को एक दिशा देने वाला है। ये बजट भाजपा के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चूंकि हर बार कॉपी तो हर कोई कर रहा है। चाहे कैप्टन अमरिन्दर सिंह हो पंजाब में, उन्होंने भी जो हमारा free bus ride for women उसमें कॉपी किया है तो कॉपी तो हर कोई कर रहा है, लेकिन नकलची बंदर कितना भी कॉपी कर ले, ओरिजनल नहीं हो सकता तो इसीलिए।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी अब बैठिये प्लीज। सोमनाथ जी बैठिये।

श्री सोमनाथ भारतीः हर तरफ राज्य के अंदर एक ही मांग है। ये बजट तो आज दिल्ली से जो एक दिशा गयी है, हर तरफ एक मांग है कि आज नहीं तो कल

केजरीवाल सरकार ही आए तभी जाकर बात बनेगी। देश का प्रधानमंत्री आज श्री अरविंद केजरीवाल साहब बनेंगे तब जाकर देश का कल्याण होगा, तभी जाकर बात बनेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद। ओम प्रकाश शर्मा जी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बजट के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। हमारे मित्र सिसोदिया जी, जिन्होंने केजरीवाल सरकार जी का जो बजट पेश किया है, मैं उनकी उड़ान देखकर हैरान हूं। 150 साल के करीब का कैन्वेस उनका है। कभी वो आर्टिस्ट हो जाते हैं, कभी वो टीचर हो जाते हैं, कभी फिल्म समीक्षक हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन इसका सबसे जो सुखद पहलू है इस बजट का क्योंकि मैं विपक्ष में होके भी निगेटिव की पोजिटिव बात करना चाहता हूं। इस बजट का नाम आपने रखा है देश शक्ति बजट, तो देर आए दुरूस्त आए। हम तो बड़े लंबे समय से आपको समझा रहे थे। देश भक्त होना इस देश में बिल्कुल ऐसे है, जैसे किसी जीव को वायु की जरूरत होती है तो जब आप 26 जनवरी पर संविधान के विरूद्ध उस पैरेड को रोकने की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ें होते हैं। पुलवामा में अटैक होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होता है, सेना के आप विरूद्ध जाते हैं तो उन सब चीजों को धता बताते हुए आपको ये समझ में आ गया कि इस देश में।

माननीय अध्यक्ष: सोमनाथ जी प्लीज।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: भाई ये ढाढ़ी जो है न, मोदी जी वाली नकली ढाढ़ी।

माननीय अध्यक्ष: सोमनाथ जी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: ये नकली ढाढ़ी से मोदी नहीं बनेगा।

माननीय अध्यक्ष: ओम प्रकाश जी मैं बात कर रहा हूं उनसे।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: तो, क्यों नकली बाल।

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी आपस में मत करिये। मैं बात कर रहा हूं उनसे भैया।

.....व्यवधान....

श्री ओमप्रकाश शर्माः तो ये जो।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी।

श्री ओमप्रकाश शर्माः ये जो देश भक्त की जो अवधारणा है। जो जन संघ और संघ की जो अवधारणा है उसको आपने आत्मसात् करने का जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। भाई ताली तो बजा दो। भैया, तुम भी बजा दो, बजाओ। राम राज्य परिषद्। राम राज्य की आप बात करते। इस देश में राम राज्य परिषद बनी थी। कृपात्र जी महाराज ने बनाई थी तो उस राम राज्य परिषद के दसों के दसों, जिनको आपने लिया है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। आप कल को क्या करेगे, क्या नहीं करेंगे, ये समय आने पर पता लगेगा लेकिन आपकी बुद्धि में जो बदलाव आ रहा है। मैं ये समझता हूं, ये जो राम मंदिर इस देश में बनने की जो प्रक्रिया है, उससे पूरा वातावरण के अंदर कोई तो अपने कोर्ट में जनेऊ पहने घूम रहा है। कोई चंडी पाठ कर रहा है, कोई राष्ट्र भक्त बन रहा है, कोई राम राज्य की अवधारणा को अपनाने का प्रयास कर रहा है और जब इस प्रकार के सकारात्मक बदलाव इस देश और समाज में होंगे तो मुझे लगता नहीं है कि विपक्ष की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अरे भाई मैं कह क्या रहा हूं। अरे भैया आज, मैं आज, भई आप तो सुनने को तैयार नहीं मैं क्या करूं यार। अरे सुन तो लो।

.....व्यवधान....

श्री ओमप्रकाश शर्माः अरे सुन लो यार। मैं तो तारीफ कर रहा हूं आपकी। तुम्हें तारीफ भी हजम नहीं हो रही है तो मैं क्या करूं। अब सवाल यह है कि मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी पिच पर आए। आप हमारी पिच पर आए, आपका धन्यवाद है। आप राष्ट्र और राम भक्त होने के लिए आपके मन में जो लालसा जगी, उसके लिए मैं प्रभु श्रीराम का धन्यवाद करता हूं। अब सवाल आता है जो बजट है। बजट

का जो कैमिस्ट है, एक साल का बजट और 150 साल का इसमें आपने विस्तार दे दिया है। किस फेंटेसी में हैं, क्या कर रहें हैं, क्यों कर रहे हैं? कभी कभी कोई बीच में फिल्म आ जाती है। कभी कोई कवि आ जाता है तो कम से कम मेरी जो बुद्धि है, मेरी बुद्धि में ये मामला आ नहीं रहा। वैसे आप ये कह सकते हैं कि इस दुनिया का जो सबसे बुद्धिमान और पागल है, उसमें एक बाल का ही फर्क है, उससे ज्यादा फर्क नहीं होता है तो अगर आप बात करें वाहनों की तो मैं इस पूरे सदन में तारीफ करता हूं कि इलैक्ट्रिक विहेकल को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार जो कार्य कर रही है, उसकी मैं तारीफ करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ आपने ने जो इलैक्ट्रिकल विहेकल के लिए जो सबसीडि थी, वो आपने वापस ली, जो आपको वापस नहीं लेनी चाहिए।

दूसरी बात स्पीकर महोदय हमारे इस परिसर में इलैक्ट्रिकल वाहन को चार्ज करने के लिए यहां भी व्यवस्था की जानी चाहिए। ये पोलूशन के लिए जो आपने काम किया है, एक अच्छा काम किया और एक इसके उल्ट काम किया है। जिस पराली के लिए आपने लाखों की दवाई खरीदी, करोड़ो के आपने विज्ञापन दे दिए, उस पराली के लिए जब किसानों ने ये कहा कि पराली जलाना अपराध नहीं होगा, तो वहां भी केजरीवाल जी खड़े हुए नजर आते हैं तो पर्यावरण पे आप कंफ्यूज हैं।

एक तरफ तो आप इलैक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी हम तारीफ करते हैं और एक तरफ पराली जलाना अपराध न हो, उसका भी समर्थन कर रहे हैं। ये जो दोनों चीजें, दोनों चीजें नहीं चलेंगे। कृपया अपने माइंड सेट को ठीक करें कि आपने इस पाले में बैठना है या उस पाले में बैठना है।

मैं अगर बिजली की बात करूं। बिजली, सड़क, पानी तो बिजली में जितने, जिन लोगों को आप दे रहे हैं, वो दे रहे हैं बाकि जो जनरल लोग हैं, उनके जो कर्मचारी, उन कर्मचारियों की पेंशन और पेंशन के अलावा अब मैं ये देख रहा हूं कि जिस जमाने में ये टोटल सरकारी होती थी बिजली कंपनी उससे ज्यादा भ्रष्टाचार आज बढ़ चुका है तो जगह जगह लोग कहते हैं जी कॉरपोरेशन से जाके एनओसी लेके आओ। भई ये प्राईवेट कंपनियां आपने बिजली देनी है, वो बिजली लेने आया,

आप उसको बिजली दे दो। वो तरह तरह की इतनी चीजें लगाके उस आदमी को बिजली देने की वजाय वही काल पुराना, जिसको हम बात करते थे, जब गवर्नमेंट के पास था ये डेसू या डूसू जो था, वही समय आ गया है और पूरी तरीके से मीटर लगवाने में पूरा भ्रष्टाचार आज हो चुका है। इसको भी, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सड़क कहां हैं, गड्डे कहां हैं, इसका कुछ पता नहीं हैं। इसपे भी कृपया करके आपको ध्यान देना चाहिए।

पानी पीने का मिल नहीं रहा है, मिलता है तो पीने के लायक नहीं हैं। आप कृपया सदन में ये बताने का कष्ट करें और एक दिन बिजली, सड़क, पानी पर चर्चा रखें और ये बतायें कि कितनी किलो मीटर सड़क आपने सही कर दी, कितने किलो मीटर आपने पानी की लाईनें बदल दीं और आज लेटेस्ट दिल्ली में जो पानी की लाईनें पुरानी कितनी हैं और वो कब कब बदली जाने का उनका शेड्यूल है, जिससे कि दिल्ली के लोगों को ये समझ में आए कि उनको पीने का स्वच्छ पानी उचित मात्रा में कब मिलेगा। तो ये जो बेसिक चीजें आप डेढ़ सौ साल का तो फेंटेसी में जी रहे हैं, लेकिन बिजली, सड़क, पानी जो बेसिक आदमी को चीज चाहिए, वो देने में आप पूरी तरीके से असमर्थ रहे हैं।

अब मैं बात अगर स्वास्थ्य की करता हूं। स्वास्थ्य के बारे में बहुत से लोगों ने चर्चा की है, उसकी चर्चा करना बेमानी है। इस सदन के हर आदमी ने अपनी हैसियत के अनुसार उसमें काम किया है। केन्द्र सरकार से लेकर पहली बार हमारी सरकार, केजरीवाल जी की सरकार थोड़ी लचीली हुई है और उन्होंने ये कहा है कि हमने केन्द्र सरकार के साथ मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ी है तो हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी है। बहुत से हमारे साथी, परिवार के लोग दिवंगत हो गये। आज ईश्वर की कृपा है कि हम और आप लोग बचे हुए हैं तो सभी लोगों ने इसमें काम किया है तो हर चीज में लड़ाई लड़ना ठीक नहीं हैं और हर जगह का अलग अलग वातावरण होता है। लेकिन दिल्ली में दिल्ली के लोगों ने पूरी तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी है और उससे बाहर भी निकले हैं, इसके लिए आप सभी को बधाई।

दूसरी बात शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो शिक्षा का हाल बेहाल है। एक स्कूल आपने खोला नहीं है। कमरे आप बनाये जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात होती है तो मंत्री जी नाराज हो जाते हैं, उनकी एरोगेंसी समझ नहीं आती। अरे भैया जब आप कोई चीज बनाओगे। सत्ता पक्ष में आप बैठे हो। आप कोई व्यापारिक काम करोगे तो विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाएगा तो ये एरोगेंसी से तो सदन चलेगा नहीं तो आप जितने कमरे बना रहे हैं वो कमरों को जितने में बनना चाहिए, उससे पांच, आठ, दस गुना कीमत आप ले रहे हो तो शिक्षा में जो आप पैसा लगा रहे हो वो जो दिल्ली की जो जनता है, उसके काम नहीं आ रहा है। वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। स्कूलों के अंदर न तो टीचर्स हैं, फैकल्टी नहीं हैं और स्कूलों का जो हाल है, वो बहुत बढ़िया हाल नहीं हैं और अस्पताल के बारे में तो कोर्ट ने जो कुछ कहा बूचड़खाना उसके बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता एक शब्द ही काफी है।

प्रदूषण के बारे में मैंने बताया एक तरफ आप सबसीडी दे रहे हैं। एक तरफ जो किसान कहते हैं कि पराली जलाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप उनके गले में बांहे डालकर खड़े हुए हैं। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है अब आप बात करते हैं पक्ष की और विपक्ष की। आप इसमें लिखते हैं एक लाख चालीस हजार यानि फर्स्ट फेज के कैमरे आपने लगा दिए। मैं इस सदन में कह रहा हूं कई–कई बार मैं कह चुका हूं एक सिंगल कैमरा मेरे यहां नहीं लगा, क्यों नहीं लगा क्योंकि मैं विपक्ष से हूं। रिसर्च सहायक आपने दो–दो लोगों को दे रखे हैं। हमने रिसर्च सहायक की शक्ल नहीं देखी तो मेरा आपसे कहना है आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में जो पक्षपातपूर्ण रवैया आप करते हो उससे रामराज्य नहीं आएगा। तो रामराज राष्ट्रवाद की जो आप कापी करना चाहते हो इसमें भी आप सफल नहीं होगे। सबसे पहला काम डेमोक्रेसी का ये है पक्ष और विपक्ष। पक्ष का ये काम है कि विपक्ष के अधिकारों की आप रक्षा करें। तभी इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी और इसमें भूमिका स्पीकर साहब की भी होनी चाहिए जो माफ करना मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आप उसके अंदर अपनी भूमिका ठीक नहीं निभा रहे, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिन्द–जय भारत।

माननीय अध्यक्षः अजय महावर जी।

श्री अजय कुमार महावरः आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बजट सत्र में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। दिल्ली का बजट जब भी आता है, इस बार कई सारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने लाता है। सरकार ऐसा कुछ बजट बनाती है

.....व्यवधान....

श्री अजय कुमार महावरः भैया मुझे बोलने दो मैंने किसी को नहीं टोका, सुन लो, आपको जो मेरी बुरी बात लगे उसको काट देना।

माननीय अध्यक्षः आप बोलिए सुनाई दे रहा है।

श्री अजय कुमार महावरः सरकार ऐसा कुछ बजट बनाती है बार—बार लगता है गरीबों पर अहसान जताती है। आदरणीय मनीष सिसोदिया जी ने बताया कि उनका सातवां बजट है। सातवें बजट के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इन्होंने पहला स्वराज थीम का बजट लाया था आज वो स्वराज थीम का कहां है किसी को नहीं पता। 2018 में पर्यावरण पर ग्रीन बजट पेश किया था उस थीम का बजट लाए थे सबको पता है क्या हुआ और डब्ल्यूएचओ ने जब ये कहा कि दिल्ली की राजधानी पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी है, तो वो इस बात की पोल खोलता है। 2019 तक 841 करोड़ रुपया ग्रीन टैक्स सेस आपने जमा लिया लेकिन उसमें से खर्च क्या किया 15.58 लाख और बाकी सिविल डिफेंस के नाम पर आपने 43 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसका क्या लाभ दिल्ली की जनता को हुआ, क्या हासिल हुआ ये मंत्री महोदय ही बता दे तो बेहतर है। कुल मिलाकर ग्रीन थीम बजट भी फेल रहा क्योंकि न तो स्मॉग टावर लगे न एंटी स्मॉग गन लगी, न एयर प्यूरीफायर गन लगी, न डस्ट कलेक्शन मशीन सड़कों पर दिखी। इस बार इन्होंने देशभक्ति थीम का बजट लिया है। मैं भी मेरे साथियों की भांति बहुत खुश हूं क्योंकि हम तो रामभक्त और राष्ट्रभक्तों की टोली है। चलो आपने मोदी सरकार की इस बात को तो अपनाया। राष्ट्रभक्ति के साथ—साथ रामराज स्थापना की बात की क्योंकि पहली बार जब आपने सरकार बनाई

दिल्ली में तब आपने उन लोगों के समर्थन से सरकार बनाई जिसने राम के अस्तित्व को मानने से इंकार किया था उसे काल्पनिक बताने का काम किया था। वह अपराध आपने किया था। चलो देश के लिए मर मिटना कबूल है हमें अखंड भारत के सपनों का तो जनून है हमें। मैं आपसे मांग करता हूं उप– मुख्यमंत्री जी कि जैसे मोदी जी ने देशभक्ति जागृत करने के लिए दिल्ली में एक नेशनल वॉर मैमोरियल बनाया है, आप भी दिल्ली के शहीदों के लिए एक दिल्ली वॉर मैमोरियल बनाएं जिससे यहां पर ये राष्ट्रभक्ति पोषित और पल्लवित हो सके। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से परिवहन पर एक बात कहना चाहता हूं कि डीटीसी के बेड़े में अभी माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 6693 बसे हैं और 1000 बस जोड़ी जाएंगी। मैं दावे से कह सकता हूं कि ये आंकड़ेबाजी का खेल है इसमें आपने डिपो में खड़ी कबाड़ बसों को भी जो लूली–लंगड़ी खड़ी है उसको भी गिनकर बताया है। दिल्लीवासियों को मूर्ख बनाने का काम हुआ है केवल 3781 बसे जो इस वक्त रनिंग कंडीशन में है और ये मैं नहीं कह रहा प्रमाणिकता से टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे रिर्पोट के आधार पर मैं ये बात कर रहा हूं जो मैं आपको टेबल कर सकता हूं। जबकि 5 वर्ष पहले से आप लगातार 11000 बसों की बात कर रहे हैं। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपये घाटे में डीटीसी चली गई। आपने पूरी डीटीसी का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। 2017 में आपने हाइड्रोजन पावर बसिज लाने की बात भी कही थी जो आज तक एक भी बस दिल्ली में नहीं आई है। मनीष जी ने शिक्षा पर बताया 1951 में हमें ले गए और कहा कि 619 स्कूल हाई स्कूल और हायर सैकेंडरी स्कूल थे और उस समय केवल 62 स्कूल थे हायर सैकेंडरी के, आज 5691 स्कूल आपने बताए हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 1951 से छोड़िए आप ये बताइए कि आप जब से सत्ता में आए आपने कितने स्कूल बनाए हैं। आपने दहाई अंक भी 500 का वादा करने के बाद दहाई अंक भी स्कूल नहीं बनाए। सारे वादे खोखले और झूठे साबित हुए, ये ही बात कॉलेज के लिए भी लागू होती है आंकड़ेबाजी से कुछ नहीं होगा। टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। आज तक वो टीचर्स यूनिवर्सिटी कहां है हमें कागज के पन्नों पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। जल बोर्ड पर आपने बात की कैसी झूठे वायदों वाली ये सरकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में हर वर्ष की वीडियो क्लिप इस सदन में रख सकता हूं

मुख्यमंत्री जी ने हर बार कहा कि 5 वर्ष में पूरी दिल्ली के घर में हम पानी दे देंगे, हर घर में नल और हर नल में जल दे देंगे और टैंकर और माफिया मुक्त दिल्ली बना देंगे। लेकिन आज क्या टेंकर माफिया मुक्त दिल्ली बनी नहीं बनी। सबको मालूम है कि माफियाओं के दबाव में कैसे कौन काम कर रहा है। साउथ दिल्ली में एक डाक्टर की मौत की और वो जो गुत्थी उलझी थी जिसमें उन्होंने सुसाइड नोट में सबकुछ खोलकर राज बता दिया था कि किनके दबाव में इस तरह की माफिया चल रहे हैं। दिल्ली की जनता तो अब आपसे ये पूछ रही है यमुना के बारे में भी, पानी के बारे में भी कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा और अब आपको चेता भी रही है कि भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन तुम्हारी सत्ता का आखिरी दिन होगा याद रहे कि वो 3 साल और 5 साल से बराबर जो आप लगातार गुमराह करते आ रहे हैं। अन्त में मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने 2047 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के बराबर कर देने की बात कही है अच्छी बात है। आप तो 6 वर्ष पहले दिल्ली को लंदन बनाने की बात भी कर रहे थे, अरे दिल्ली को दिल्ली ही रहने देते इतना प्रदूषित न करते। दिल्ली, दिल्ली ही रह जाए तो दिल्लीवासी बहुत खुश हो जाएंगे और जिस गति से आपने प्रदूषण पर काम किया, स्कूल पर, कॉलेज पर, बस पर, पर्यावरण पर काम कर रहे हो। ये वादा तो दशकों तक क्या सदियों तक भी पूरा होने की संभावना हमें नजर नहीं आती। सपने तो आप अपलोड बहुत जल्द कर देते हैं पर डाउनलोड करने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं ऐसा हमें लगता है। झुग्गी—झोपड़ी वालों के लिए कल बिधूड़ी जी ने भी कहा था, आपने कहा मकान देंगे बहुत अच्छी बात है हम आपके समर्थन में खड़े हैं। अरे लेकिन जो हजारों मकान बनाकर रखे हुए है जो जर्जर हालत में जा रहे हैं। इसकी मेंटिनेंस नहीं हो पा रही है उस मकान को देने में किसने रोका है आपको, क्यों रोक रहे हो आप, क्यों नहीं देना चाहते। आप तत्काल प्रभाव से उसको दीजिए हम आपके साथ खड़े हैं। कल सौरभ भारद्वाज जी ने एक बात कही कोरोना पर केन्द्र सरकार पी.आर. कर रही है। मैं कोरोना पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं ओम प्रकाश जी से सहमत हूं और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से भी सहमत हूं। उन्होंने कहा कि कोरोना पर कम से कम हमे राजनीति नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दिल्ली की दल—दल कहां फंस जाती पता नहीं लगती। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस कोरोना वर्ष में पी.आर. की।

सौरभ भारद्वाज जी ने कल कोट किया था कि केन्द्र सरकार पर इन्होंने बात कही थी। 2020 में पूरे कोरोना काल में दिल्ली की जनता पर गाढ़ी कमाई का इस कठोर समय में भी विज्ञापन पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए दिल्ली सरकार ने। यहां तक की 4 किलो गेहूं आपने एमएलए कूपन दिए अच्छी बात है उसमें क्या दिया आपने 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल 3 रुपया, 8 रुपये का 11 रुपये के सामान पर भी मुख्यमंत्री जी अपना फोटो छापना नहीं भूले, विज्ञापन की बड़ी भूख है। यह बात मुख्यमंत्री को समझनी चाहिए गरीबों से इतना मजाक नहीं करना चाहिए कि 11 रुपये की सामग्री पर भी अपनी फोटो चिपकाकर अहसान लादने का प्रयास करें। स्वास्थ्य मंत्री जी ने अनियंत्रित कोरोना संख्या के आंकलन को गलत बताया, इस दिल्ली को गुमराह करने का काम किया। अनुमानित आंकड़े से दिल्ली भय के वातावरण में चली गई। मुझे लगता है कि एक लास्ट बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आपने बजट में जो वृद्धा पेंशन है उस पर आपने जो बजट लगाया है, लेकिन बुजुर्ग आपकी बाट जोह रहे हैं आप पेंशन कब बढ़ाएंगे। पिछले पेंशनधारियों को तो आप दे रहे हैं लेकिन पिछले कई सालों से जो पेंशन बढ़ नहीं पा रही है उस पर भी अगर इस बजट में ध्यान देंगे तो आपकी बुजुर्गों पर बड़ी कृपा होगी क्योंकि दिल्ली के बुजुर्ग आपकी इस बात पर बाट जोह रहे हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया जय हिन्द–जय भारत, वन्देमातरम।

माननीय अध्यक्ष : जय भगवान उपकार जी।

श्री जय भगवान : आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इस बजट प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं दिल्ली देश की राजधानी है और इस राजधानी के अंदर लोग भारत के कोने–कोने से आकर यहां बसे हुए हैं और वो लोग दिल्ली के कोने–कोने से इसलिए यहां पर आए हैं कि उनके बच्चों को यहां पर अच्छी शिक्षा मिल सकें, अच्छा स्वास्थ्य मिल सकें, अच्छा रहन–सहन मिल सके क्योंकि अन्य प्रदेशों के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं शायद नहीं है जिसकी वजह से लोग दिल्ली का रास्ता अपनाते हैं और दिल्ली के अंदर आ रहे हैं और मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं दिल्ली सरकार का कि दिल्ली के लोगों के लिए सेवाएं यहां पर मुहैया करा रही है चाहे वो दिल्ली का कोई भी तबका

है। हर तबके के लिए चाहे वो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात है, चाहे अन्य किसी सुविधा की बात है, हर तरीके से यहां पर दिल्ली सरकार के द्वारा हर तबके के लिए लगातार काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभी आदरणीय ओमप्रकाश शर्मा जी बता रहे थे कि माननीय उप–मुख्यमंत्री जी स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं बन रहे हैं। माननीय ओमप्रकाश शर्मा जी को मैं बताना चाहता हूं मेरी बवाना विधान सभा है अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो अभी 17 नई स्कूल बिल्डिंगें बन रही है मैं आपको दिखा सकता हूं क्योंकि ये सरकार वो सरकार है जो कहती है वो करती है। ये सरकार वो सरकार नहीं है जुमलेबाजों की जो कह दिया वो नहीं करना है। तो अध्यक्ष महोदय जी, जो दिल्ली सरकार है वो लगातार अपने प्रयासों से दिल्ली के लोगों को हर तरीके से कोशिश में लगी हुई है कि जो दिल्ली के लोग जो स्वास्थ्य सेवाएं, जो शिक्षा, जो बिजली और पानी जो चाहते हैं वो ये सरकार दे। अध्यक्ष महोदय जी, अभी अजय महावर जी भी बोल रहे थे कि माननीय जो परिवहन मंत्री जी है।

अध्यक्ष जी अभी इन्होंने कहा कि जो बसें हैं, वो बसों की बात करते हैं लेकिन बसें लेकर नहीं आते। मैं अपनी बवाना विधानसभा की बात बताना चाहता हूं। आज से क्योंकि अभी सरकार को 6 साल हुए हैं और इन 6 सालों में मैंने देखा है कि बवाना के जो लोग हैं बेचारे परेशान होते थे बसों में आने के लिए लेकिन आज सरकार ने इतनी बसें लगा दीं बवाना के अंदर और अन्य विधानसभाओं के अंदर कि मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव के अंदर एक नया डिपो खुल गया है इतनी व्यवस्था की है दिल्ली सरकार ने बसें लगाकर। आज जो हमारी बहन बेटियां हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी महिलाएं हैं वो बेचारी बसों में क्योंकि दूर–दराज के गांव हैं और बाजारों के लिए बसों में आती हैं वो उनका पैसा बचता है, अपनी शॉपिंग करती हैं तो आज ये दिल्ली सरकार ने दिया है। तो मैं आदरणीय महोदय जी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट के अंदर वरिष्ठ नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए और वंचित वर्गों के लिए जो बजट के अंदर 2710 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है मैं इसका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा लगातार चाहे वो हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर,

चाहे वो जैसे बसों की मैं अभी बात कर रहा था कि बसें फ्री की हैं, बसों के अंदर मार्शल लगाए हैं, हमारी महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए वाईफाई लगाए हैं। तो ऐसी सरकार जो हर तबके के लिए काम कर रही है तो अध्यक्ष महोदय अभी जैसे की पेंशन की बात हो रही थी तो पेंशन के लिए भी सरकार ने जो हमारे जो पेंशनधारी थे कोरोना के दौरान वो बहुत परेशान थे और वो चाह रहे थे कि भगवान कहीं से कुछ भेजे तो मैं धन्यवाद करता हूं दिल्ली सरकार का कि दिल्ली सरकार ने हर तबके के लिए चाहे वो स्कूटर वाला है, चाहे वो कार वाला है, चाहे वो हमारे बुजुर्ग थे, चाहे जो हमारा विक्लांग साथी था, चाहे हमारी विधवा महिला थी, सबके लिए उनके खाते में पैसे भेजे। एक तरीके से गौड गिफ्ट उन लोगों के लिए दिया। उन लोगों ने बहुत दुआएं दी हैं कि कोरोना के दौरान जो हमें सहायता सरकार के द्वारा दी गई है उससे हमें बहुत लाभ हुआ है। अध्यक्ष महोदय कोरोना के दौरान ही मैं आपको अपनी विधानसभा के बारे में बताना चाहता हूं कि क्योंकि दिल्ली का सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है मेरा बवाना और बवाना के अंदर बहुत सी जो अनॉथराइज कालोनियां हैं, बहुत से गांव हैं, 27 गांव हैं और उन गांवों के अंदर बेचारे बहुत गरीब लोग रहते हैं और बहुत सी रिसेटेलमेंट कालोनियां हैं, उन कालोनियां के अंदर बेचारे गरीब लोग हैं और ये गरीब लोग कोरोना के दौरान बहुत परेशान थे, तो सरकार के द्वारा उनको जो सूखा राशन दिया गया और उनके लिए स्कूलों के अंदर जो खाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई, उससे उनको बहुत लाभ हुआ और उन्होंने बहुत दुआएं दी हैं तो अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार हर तबके के लिए काम कर रही है और दिल्ली के कोने–कोने में हर आदमी, चाहे उसमें मैं भी आता हूं क्योंकि मेरा जो इलाका है शाहबाद डेयरी वो झुग्गी–झोपड़ी का इलाका है, गरीब लोगों का इलाका है, कमजोर वर्ग के लोग वहां पर रहते हैं। हर तरीके से वो लोग चाहते हैं कि उनका विकास हो। तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि दिल्ली के अपने इलाके के अंदर कि रोडों की हालत क्या थी। वो सारे रोड खराब थे, उनकी गलियां खराब थीं, झुग्गियों के अंदर जाने का रास्ता नहीं था, गलियों के अंदर जाने का रास्ता नहीं था लेकिन दिल्ली सरकार के द्वारा वो सारी गलियां बनाई गईं, वो सारे रोड बनाए गए, उनके लिए लाइटें लगाई गईं, उनके लिए कैमरे लगाए गए। महिलाओं के लिए सीटीसी बनाई गईं क्योंकि हमारी

महिलाएं खुले में शौच करती थी उनके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से सीटीसी बनाई गई। तो अध्यक्ष महोदय हर तरीके से सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो गरीब तबका है उसको हर तरीके की सुविधाएं दी जाएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय अभी जिस तरीके से समाज कल्याण विभाग, महिला और बाल विभाग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए इस बजट सेशन में 4750 करोड़ का प्रावधान किया है इसका मैं बहुत—बहुत धन्यवाद करता हूं दिल्ली सरकार का और बस मैं लास्ट ये बोलना चाहता हूं कि मैं बहुत—बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, माननीय डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी का कि भारत के हर राज्य के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री ऐसे डिप्टी सीएम होने चाहिए जो देश के हर तबके के लिए सोचते हैं और विचार करते हैं और काम करते हैं धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत—बहुत धन्यवाद, मुकेश अहलावत जी।

श्री मुकेश अहलावतः धन्यवाद सभापति महोदय जी, आज मुझे पहली बार यहां पर विधानसभा में बोलने का मौका मिला और मैं आज अपने मुख्यमंत्री और अपने डिप्टी सीएम को सेल्यूट करता हूं जिन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया। आज मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि इस लोकतांत्रिक देश में दिल्ली विधानसभा में चुने गए सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि हम संविधान का सम्मान करें जिसमें माननीय उप—राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप—मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष, सभी एमएलए शामिल हैं। मैं शिक्षा के विषय में बात करना चाहता हूं। डॉक्टर बीआर अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले और रविन्द्र नाथ टैगोर, विवेकानंद जो अन्य कई भी हमेशा अमर रहे तो वो केवल शिक्षा के स्तर के कारण से। गांधी जी की अवधारणा थी बुनियादी शिक्षा में सफाई, रचनात्मक गतिविधियां, स्वास्थ्य, शिक्षा, देशभक्ति जो बच्चों में राष्ट्रीय, सामाजिक, अध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करना। भारत गणराज्य के संविधान में 3 अलग—अलग सूचियां हैं। पहली संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची— इस सूची में कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है। राज्य सूची— इस सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची— इस सूची में कानून बनाने का अधिकार केन्द्र

एवं राज्य सरकार दोनों को है। दिल्ली सरकार अब इस प्रकार अपना दिल्ली शिक्षा बोर्ड स्थापित करने जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा राज्य सूची में थी 1976 में और 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया तब से शिक्षा की व्यवस्था करना केन्द्र और राज्य की सरकार दोनों की जिम्मेदारी थी। 2002 में 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अनुच्छेद 21–ए जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य एवं निशुल्क व्यवस्था की गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुच्छेद 51–ए प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह माता–पिता अभिभावक के रूप में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों अथवा आश्रितों को शिक्षा प्रदान करे। संविधान के अनुच्छेद 15(3) में यह व्यवस्था की गई कि किसी भी बात से राज्य को स्त्री और बालकों के लिए नियम बनाने की कोई बाधा नहीं होगी। अनुच्छेद 15 के नियम 4 के मुताबिक राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा एससी/एसटी/ओबीसी के लिए विशेष नियम बनाने की छूट है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 9 मार्च, 2021 को दिल्ली बजट पेश किया। उन्होंने भारत के 75 साल की आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के मद्देनजर देशभक्ति बजट को देशभक्ति महोत्सव के रूप में 12 मार्च, 2021 से शुरु करने का फैसला किया है। दिल्ली शिक्षा बजट 2021 भारत की 75वीं वर्षगांठ के साथ–साथ 100 साल की स्वतंत्रता पर केन्द्रित होगा। दिल्ली का टोटल बजट 69 हजार करोड़ रुपये है और शिक्षा पर 16370 करोड़ रुपये खर्च किए हैं इसके लिए डिप्टी सीएम का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। दिल्ली शिक्षा बजट 2021 इस साल का सबसे बड़ा बजट है। दिल्ली को अपना सैनिक स्कूल मिलेगा यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। नर्सरी से आठवीं कक्षा के लिए एक नया पाठ्यक्रम शुरु किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली में देश का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक के 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में खोले जाएंगे। दिल्ली के स्कूल में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरु किया जाएगा जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और बच्चे भी अच्छी दिशा में जाने का प्रयास करेंगे। दिल्ली सरकार कानून की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए नई दिल्ली लॉ युनिवर्सिटी खोलने की तैयारी कर रही है। लॉकडाउन के समय सभी अध्यापकों के सहयोग से ऑनलाइन क्लासेज

शिक्षा संभव हो सकी। सरकारी स्कूल में 2019—20 के दौरान बारहवीं क्लास में 97.92 प्रतिशत और दसवीं कक्षा में 82.61 प्रतिशत बच्चे पास हुए। हमने साढ़े सात लाख मोड्यूलर डेस्क खरीदे। हमने सभी कक्षाओं को ग्रीन बोर्ड भी मुहैया कराए। अगर पड़ोसी राज्यों की तुलना करें तो आंकड़ा बड़ा गंभीर नजर आता है। भाजपा शासित हरयाणा में 2015 से 2018 की अवधि में 208 सरकारी स्कूल बंद हुए। कांग्रेस शासित पंजाब 2015 से 2018 की अवधि में 217 सरकार स्कूल बंद हुए और भाजपा शासित एमसीडी में 109 सरकारी स्कूल बंद हुए और भाजपा शासित राजस्थान में भी 2018 की अवधि तक 400 स्कूल बंद हुए परन्तु दिल्ली में हमारा कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं हुआ। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में 113000 प्राथमिक स्कूलों में से कई स्कूलों में बिजली तक के कनेक्शन नहीं हैं इससे यह प्रतीत होता है कि दिल्ली सरकार की तरह किसी भी सरकार का शिक्षा प्राथमिक मुद्दा नहीं है और वो अभी गरीब लोगों को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। एमसीडी के डीएमसी अधिनियम 1957 के अध्याय 3 के तहत प्राथमिक स्कूल चलता है जिसकी स्थिति बहुत ही खराब है और हमारे नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के एमएलए एमसीडी के करप्शन से अवगत हैं और उनको भी पता होगा कि आने वाले एमसीडी के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ है जिसके कारण से सरकारी स्कूलों को भी और अपनी पार्टी को भी मैं बधाई देना चाहूंगा एडवांस में कि एमसीडी में हमारी सरकार आएगी और लोग।

माननीय अध्यक्षः अहलावत जी कन्क्ल्यूड करिए प्लीज।

श्री मुकेश अहलावतः सर थोड़ा सा और।

माननीय अध्यक्षः नहीं नहीं एक वक्ता और है 4 बजे समाप्ता करना है।

श्री मुकेश अहलावतः एक मिनट सर एक कविता के साथ मैं अपने लफ्जों को विराम देना चाहूंगा

दिल्ली के सरकारी स्कूल अब तकदीर बनाने वाले,

छोड़ गये थे राम भरोसे बीजेपी, कांग्रेस वाले,

बुनियादी समस्याओं को अब केजरीवाल ने सुलझाया,

मनीश सिसोदिया शिक्षा का हनुमान कहलाया,

रोटी दी, शिक्षा दी, अब एक नई पहचान,

डॉक्टर और इंजीनियर बनने का बच्चे के मन में दीप जलाया,

जो किया न आज तक किसी ने, वो केजरीवाल ने कर दिखलाया,

दिल्ली सरकारी स्कूल अब सर्वश्रेष्ठ कहलाया,

गली–गली बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया,

वर्षों में जो न हुआ, वो अब कर दिखलाया,

टाट, तख्ती को स्मार्ट क्लास तक पहुंचाया,

कोरोना में भी शिक्षा को ऑनलाइन कर दिखलाया,

अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के स्तर तक पहुंचाया,

गरीब, वंचित, पिछड़ा और शोषित तथा अज्ञान,

इंग्लिश सीखी, हिंदी सीखी, सीखा संसार का ज्ञान,

पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, सीखा अब विज्ञान,

दिल्ली सरकारी स्कूल में बच्चा एक समान,

कैसे भूलूं उन लोगों को शिक्षा ने जिन्हें बनाया,

मूलभूत सुविधाओं ने जिन्हें बहुत सताया,

भविष्य का रास्ता जिन्होंने हमें दिखाया,

शिक्षा से बड़ा धन कभी न हमने कमाया।

धन्यवाद सभापति महोदय।

माननीय अध्यक्षः बहुत—बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छे। अंत में श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः माननीय अध्यक्ष जी, आपने बजट पर बोलने का मौका दिया, हालांकि सब लोग बहुत थक गये हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी और लोग घर जा सकें। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का जो बजट होता है वो दरअसल ऐसा होना चाहिए जिसमें जनता की कुछ बचत हो पाये। मोटे तौर पर सरकारें जब बजट बनाती हैं तो बस ये कोशिश करती हैं कि यहां से टैक्स ले लो, यहां से रेट बढ़ा दो और फिर कुछ रेवड़ियां बांट दो। लेकिन लगातार 2013 से और उसके बाद 15 से तो लगातार, ये जो 21—22 का बजट माननीय उप—मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, लगातार न सिर्फ उस बजट को बढ़ाया है बल्कि जो लोगों को सुविधाएं दी हैं वो सारी जनता आज जिस तरीके से उसकी तारीफ करती है बल्कि विपक्ष के साथी भी करते हैं और उसका रिजल्ट आप लगातार चुनावों मे देख भी रहे हैं। दरअसल जनता के मुद्दे होते क्या हैं? जब हम पब्लिक में जाते हैं और उनसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं, तो ज्यादातर महिलाएं खासतौर से कहती हैं वो चाहती हैं कि उनका बच्चा पढ़ जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए, सस्ती मिल जाए, घर के पास मिल जाए। अगर घर में कोई भगवान न करे बीमार हो जाए तो सस्ती दवाई मिल जाए, अस्पताल पास में हो। बिटिया अगर स्कूल जाती है या बाजार में जाती है तो सुरक्षित वापस आ जाए। तो ये शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, ये सम्मान कि बुजुर्गों को पेंशन मिल जाए, तीर्थयात्रा पर कोई सरकार सोच भी ले कि उनको ले जा सकती है, यही तो मुद्दे होते हैं। हम जो आम आदमी पार्टी की बात करते है, दरअसल आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी के मुद्दों की बात करते हैं और आम आदमी के यही मुद्दे हैं। वो मुद्दे नहीं जो गढ़ लिये जाते हैं चुनावों के आसपास और एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। आम आदमी पार्टी वो मुद्दों की बात नहीं करती बल्कि उन मुद्दों की बात करती है जो आपके हैं, जो मेरे हैं, जो हमारे दिलों के अदंर हैं।

उप—मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसमें हर महीने की जो लोगों को बचत होती है, किसी के 4 बच रहे हैं, किसी के 5 हजार बचते हैं, किसी के 7 हजार बचते हैं। अब सीधे तौर पर तो लोगों को पैसे नहीं दिये जा सकते। लेकिन उनकी

थोड़ी बहुत मदद की जा सकती है। और जब हम नए स्कूल बनाते हैं, कॉलेजिस बनाते हैं, जब हम कैमरा लगाते हैं, वाईफाई लगाते हैं तो उसमें रोजगार भी पैदा होता है। रोजगार के साथ में जो पैसा बचता है उसको भी लोग बाजार में ही खर्च करते हैं। तो हम उस इकोनॉमी की भी बात करते हैं, रोजगार भी देते हैं, मोटे तौर पर सारे ही पहलुओं को हम उसके अंदर अच्छे तरीके से छेड़ते हैं।

75 साल की जो आजादी का जो व ा हम मना रहे हैं, न सिर्फ उसके अंदर हमने ये प्लान किया, जो कल से शुरूआत हो रही है कि हम किस तरीके से उसे मनायेंगे, साथ—साथ ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि हमने सौवें साल का भी विजन दिया कि सौ साल बाद जो हमारी पैर—कैपिटा इन्कम है उसे हम सिंगापुर के आसपास ले जा सकते है। अब बहुत सारे हमारे विपक्ष के साथी उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये कैसे होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका एक बहुत अच्छा जवाब दिया और वो जवाब ये था कि फिर ये शिक्षा की ताकत को पहचानते नहीं है। इनको लगता है कि पैसे बढ़ेंगे कैसे। भई यहां से निकाल के वहां दे दिये, ऐसे तो बढ़ नहीं सकते। लेकिन जब हम अपनी आने वाली पौध को शिक्षित करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे, उसको स्किल्स के टूल्स देंगे तो वो अपने आपको कहां ले जा सकती है, इस बात का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा लीजिये कि अभी देश के अंदर बहुत ज्यादा आबादी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी लिखी नहीं हैं, उसके पास में उतने स्किल नहीं हैं अगर वो सब उनको मिल जाएंगी तो ये देश में जितनी अपार सम्भावनाएं हैं, ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उसको हम कहां तक लेकर जा सकते हैं। और जिस रफ्तार से माननीय उप—मुख्यमंत्री जी आप बढ़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के उस सपने को लेकर, मुझे कोई अजीब नहीं लगता कि सिंगापुर बहुत पीछे रह जाए और हम लक्ष्य तक पहुंच जाए। सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। हम उस सपने पे काम भी कर रहे हैं कि उसको किस तरीके से करना चाहिए। मैं जब भी, इनकी बातों को मैं देख रहा था कि बहुत मजाकियेपन में लेते हैं।

लेकिन जिस तरीके से ये सरकार काम करती है, आप करते हैं, बार—बार एक बात थी जो माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा कि भई गरीबों के लिए तो आप करते हो, लेकिन मिडिल क्लास के लिए, अमीरों के लिए क्या करते हो? तो पहली बात तो

वो ये भूल जाते है कि आज तक के किसी भी टैक्स बजट में हमने कोई टैक्स बढ़ाया नहीं है बल्कि उस टैक्स को लेवल किया है कि आसपास के क्षेत्रों से वो इतना लेवल रहे स्टेट्स के साथ में कि वो उस तरीके की दिक्कतें न आयें। एक बार ऐसा भी हुआ जब जूते के ऊपर, कपड़े के ऊपर कुछ टैक्स लेवल करने के चक्कर में ऐसा रहा कि थोड़ा बढ़ा, किसी भी घमंड को न देखते हुए अगले 24 घंटे के अंदर माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने उस टैक्स को वहीं की वहीं घटा दिया और जो 5 परसेंट था उसे भी बल्कि जीरो कर दिया। ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। हमें पता है केंद्र सरकार के ऊपर, जब सोने के ऊपर उन्होंने ड्यूटी बढ़ाई थी, लोग कह–कहकर मर गये, वो नहीं माने। आज किसानों के आंदोलन में भी वही हो रहा है, आप कह–कहकर मर जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है।

अब जो सवाल था कि गरीबों के लिए क्या होता है? जब एक बच्चा ये देखता है कि एक मकान के अंदर 8 शौचालय हैं और 80 लोगों के ऊपर या 80 घरों के ऊपर एक शौचालय भी नहीं है तो सामाजिक अव्यवस्था पैदा होती है। और मैं अगर थोड़ा सा अर्बन डेवलपमेंट की बात करूं तो हमारी सरकार ने जो उसके ऊपर काम किया कि न सिर्फ in situ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें कि लोगों को घर मिले, अच्छे घर मिले, घर के पास घर मिल जाएं, उसके ऊपर काम हो रहा है। सुल्तानपुरी के अंदर आलरेडी ये काम चल रहा है, इसके अलावा करोल बाग में देव नगर के अंदर भी ये काम शुरू हो रहा है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि 'जो शाम को थककर टूटे झोपड़े में सो जाता है, वो मजदूर जो शहर की ऊंची इमारतें बनाता है।' उसके लिए कोई नहीं सोचता। ये जिस किस्म की आम आदमी पार्टी की सरकार है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय उप–मुख्यमंत्री जी को कि ऐसे ही मुस्कुराते हुए क्योंकि जो उनकी स्माइल है वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है, अक्सर जो ये फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ये बहुत तंग करते हैं लोगों को, लोग घबराते हैं कि भई अब पता नहीं किस चीज पे टैक्स बढ़ जाए, किसपर एक्साइज हो जाए लेकिन हमारे उप–मुख्यमंत्री जब वो फाइनेंस का बिल लेकर आते हैं, कोई, बजट जब पेश करते हैं तो बड़े मुस्कुराते हुए ये उसे पेश करते हैं और इनके लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाती है हमारे विपक्ष के साथियों के लिए, मेरी बड़ी सहानुभूति

है इनके साथ में, ये कहते हैं कहे क्या, करें क्या, बोले क्या, तो इसीलिए आज तो तारीफ भी कर गये।

एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अभी उन्होंने, बिल्कुल 4.00 भी बज गये है इसीलिए, कि अभी उन्होंने कहा कि राम की बहुत बातें की, भगवान राम की बहुत बातें होती रही और अब से नहीं अनंत काल से हो रही हैं। माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से एक बार रामविलास पासवान जी ने कहा कि आपके नाम में तो राम नहीं है, मेरे तो नाम में भी राम है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि राम तो हराम में भी होते हैं, सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता, राम को मानना पड़ेगा, सिर्फ राम को कहने से नहीं, राम की माननी पड़ेगी और ये सरकार, दिल्ली की सरकार राम के, भगवान राम के उस हर सोच के साथ में, राम–राज्य की कल्पना के साथ में आगे बढ़ रही है और मेरी ऐसी भगवान से कामना है, ऐसी इच्छा है कि ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और ऐसे ही चलती रहे। बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद राजेश जी, बहुत–बहुत धन्यवाद। अब सदन की कार्यवाही 12 मार्च, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप सबका बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 12 मार्च, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, स्मैट फॉर्म्स, नई दिल्ली–110 007 द्वारा मुद्रित।